IAS BABA

RAPID REVISION SERIES

800 High Probable Topics for UPSC Prelims 2021

(Current Affairs + Static Portion)

हिंदी

Full Compilation

POLITY

Make the best use of this document by combining free explanation videos of these topics, Current Affairs Quiz, Static Quiz, CSAT Quiz, & 3 Full Mocks on rrs.iasbaba.Com (A Free Initiative targeting UPSC PRELIMS 2021)

Q.1) '1773 के रेगुलेटिंग एक्ट' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह भारत में EIC के मामलों को नियंत्रित और नियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था।
2. इस अधिनियम द्वारा EIC के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को पृथक किया गया।
3. इस अधिनियम द्वारा बॉम्बे और मद्रास प्रेसीडेंसी के गवर्नर बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए।

उपरोक्त कथनों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिये?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3

Q.1) Solution (c)

➢ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बहुत संवैधानिक महत्व का था क्योंकि यह ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित और नियमित करने के लिए उठाया गया पहला कदम था।

➢ इस अधिनियम ने पहले के विपरीत, जब तीनों प्रेसीडेंसी एक दूसरे से स्वतंत्र थी, बॉम्बे और मद्रास प्रेसीडेंसी के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर-जनरल के अधीनस्थ बना दिया।

➢ पिट्स इंडिया एक्ट 1784 (Pitt's India Act 1784) द्वारा EIC के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्य को पृथक किया गया।

Q.2) निम्नलिखित में से किस अधिनियम के पारित होने से भारत में कंपनी के क्षेत्रों को पहली बार 'भारत में ब्रिटिश संपत्ति' कहा गया था?

a) रेगुलेटिंग एक्ट 1773
b) चार्टर अधिनियम 1813
c) चार्टर अधिनियम 1793
d) पिट्स इंडिया अधिनियम 1784

Q.2) Solution (d)

➢ 1784 के पिट्स इंडिया अधिनियम (Pitt's India Act of 1784) के पारित होने के साथ, भारत में कंपनी के क्षेत्रों को पहली बार 'भारत में ब्रिटिश संपत्ति' कहा गया; तथा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के मामलों और उसके प्रशासन पर सर्वोच्च नियंत्रण प्राप्त हुआ।

Q.3) 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा पहली बार:

a) गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को पृथक किया गया।
b) एक वाणिज्यिक निकाय के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की सभी गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया।

c) भारत में अंग्रेज़ों के अधीन संपूर्ण प्रादेशिक क्षेत्र पर अधिकार रखने वाली सरकार का निर्माण किया गया।
d) उपरोक्त में से कोई नहीं।

Q.3) Solution (a)

➢ 1853 के चार्टर अधिनियम (Charter Act of 1853) द्वारा पहली बार गवर्नर-जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को पृथक किया गया। इसने परिषद में विधान पार्षद कहे जाने वाले छह नए सदस्यों को जोड़ने का प्रावधान किया। दूसरे शब्दों में, इसने एक अलग गवर्नर-जनरल की विधान परिषद की स्थापना की जिसे भारतीय (केंद्रीय) विधान परिषद के रूप में जाना जाने लगा। परिषद की इस विधायी शाखा ने ब्रिटिश संसद के समान प्रक्रियाओं को अपनाते हुए एक लघु संसद के रूप में कार्य किया। इस प्रकार, कानून को पहली बार सरकार के एक विशेष कार्य के रूप में माना गया, जिसके लिए विशेष मशीनरी और विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती थी।

➢ एक वाणिज्यिक निकाय के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की सभी गतिविधियों को 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा इस शर्त के साथ समाप्त कर दिया गया, कि भारत में कंपनी के क्षेत्र 'महामहिम, उनके वारिस और उत्तराधिकारियों के विश्वास में' थे।

➢ 1833 के चार्टर अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर-जनरल को भारत का गवर्नर-जनरल बना दिया और उनमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ निहित हो गईं। इस प्रकार, अधिनियम ने पहली बार, भारत में अंग्रेजों के कब्जे वाले पूरे क्षेत्रीय क्षेत्र पर अधिकार रखने वाली भारत सरकार का निर्माण किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर-जनरल बने।

Q.4) '1858 के भारत सरकार अधिनियम' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इस अधिनियम को भारत की अच्छी सरकार के लिए अधिनियम के रूप में भी जाना जाता था।
2. इस अधिनियम ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को खत्म करके दोहरी सरकार की व्यवस्था को समाप्त कर दिया।
3. इस अधिनियम में सिविल सेवकों के चयन और भर्ती की खुली प्रतिस्पर्धा प्रणाली की शुरुआत की गयी।

उपरोक्त कथनों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिये ?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3

Q.4) Solution (a)

➢ 1858 का भारत सरकार अधिनियम 1857 के विद्रोह के मद्देनजर अधिनियमित किया गया था- जिसे स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध या 'सिपाही विद्रोह' के रूप में भी जाना जाता है। भारत की अच्छी सरकार के लिए अधिनियम के रूप में विख्यात इस अधिनियम

ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और ब्रिटिश राज (क्राउन) को सरकार, क्षेत्रों और राजस्व की शक्तियां हस्तांतरित कर दी।

➢ इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दोहरी सरकार की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। इसने एक नया कार्यालय बनाया, भारत के लिए राज्य सचिव, भारतीय प्रशासन पर पूर्ण अधिकार और नियंत्रण के साथ निहित है। राज्य सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होते थे जो अंततः ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी थे।

➢ 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा सिविल सेवकों के चयन और भर्ती की खुली प्रतियोगिता प्रणाली शुरू की गई थी।

Q.5) बंगाल, उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रांत (NWFP), और पंजाब के लिए नई विधान परिषदों की स्थापना का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया?

a) भारतीय परिषद अधिनियम 1861
b) भारतीय परिषद अधिनियम 1892
c) भारतीय परिषद अधिनियम 1909
d) उपरोक्त में से कोई नहीं।

Q.5) Solution (a)

➢ 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम में बंगाल, उत्तर-पश्चिमी सीमांत प्रांत (NWFP) और पंजाब के लिए नई विधायी परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जो क्रमशः 1862, 1886 और 1897 में स्थापित हुई थी।

Q.6) 'भारत सरकार अधिनियम 1935' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसने लंदन में भारत के उच्चायुक्त का एक नया कार्यालय बनाया और भारत के राज्य सचिव द्वारा किए गए कुछ कार्यों को उन्हें स्थानांतरित कर दिया गया।
2. इस अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों को तीन सूचियों - संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची के रूप में विभाजित किया।
3. बिहार, असम और संयुक्त प्रांत में एक द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गयी।

उपरोक्त कथनों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिये?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3

Q.6) Solution (b)

➢ भारत सरकार अधिनियम 1935 में एक अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसमें प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में शामिल किया गया था। इस अधिनियम ने तीन सूचियों के संदर्भ में केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों को विभाजित किया-संघीय सूची (केंद्र के लिए, 59 विषयों के साथ), प्रांतीय सूची (प्रांतों के लिए, 54 विषयों के साथ) और समवर्ती सूची (दोनों के लिए, 36 विषयों के साथ)। वायसराय को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गयी। हालांकि, यह महासंघ कभी अस्तित्व में नहीं आया क्योंकि रियासतों ने इसमें शामिल होने से इंकार कर दिया।

➢ इसने ग्यारह में से छह प्रांतों में द्विसदनपद्धति (Bicameralism) की शुरुआत की। इस प्रकार, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत की विधायिकाओं को एक विधान परिषद (उच्च सदन) और एक विधान सभा (निम्न सदन) से मिलकर द्विसदनीय बनाया गया था। हालांकि उन पर कई तरह के प्रतिबंध लगाये गए थे।

➢ 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का एक नया कार्यालय बनाया और अब तक भारत के राज्य सचिव द्वारा किये जाने वाले कुछ कार्यों को उन्हें स्थानांतरित कर दिया गया।

Q.7) निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता की समाप्ति की घोषणा की?

a) भारतीय परिषद अधिनियम 1909
b) भारत सरकार अधिनियम 1919
c) भारत सरकार अधिनियम 1935
d) भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947

Q.7) Solution (d)

➢ 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया गया और 15 अगस्त, 1947 से भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित कर दिया गया। इस अधिनियम ने 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता और आदिवासी क्षेत्रों के साथ संधि संबंधों के समाप्ति की घोषणा की।

➢ इसने भारतीय रियासतों को या तो भारत या पाकिस्तान के प्रभुत्व में शामिल होने या स्वतंत्र रहने की स्वतंत्रता प्रदान की। इसने 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा नए संविधानों के निर्माण तक प्रत्येक उपनिवेश और प्रांतों के शासन प्रावधान किया। हालांकि रियासतों को इस अधिनियम में संशोधन करने के लिए अधिकृत किया गया था।

Q.8) संविधान सभा में पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए "उद्देश्य प्रस्ताव" के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसने भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गयी।
2. इसने अल्पसंख्यकों, पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों, और दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान किए।
3. उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित संस्करण वर्तमान संविधान में 'राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों' को प्रस्तुत करता है।

उपरोक्त कथनों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिये?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3

Q.8) Solution (a)

➢ उद्देश्य प्रस्ताव को 1946 में पं. जे. नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया था इसने संवैधानिक ढांचे के मूल सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित किया। इसने भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की गारंटी तथा सुरक्षा एवं अवसर और कानून के समक्ष समानता; कानून और सार्वजनिक नैतिकता के अधीन विचार, अभिव्यक्ति, आस्था, विश्वास, पूजा, व्यवसाय, संघ और कार्रवाई की स्वतंत्रता प्रदान की।

➢ इसमें अल्पसंख्यकों, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों और अवसादग्रस्त और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों का प्रावधान किया गया था।

➢ उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित संस्करण वर्तमान संविधान की प्रस्तावना बना।

Q.9) भारतीय संविधान की विभिन्न विशेषताएं विश्व संविधान के कई दस्तावेजों से उधार ली गई हैं। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जर्मनी के वाईमर संविधान से ली गई है।
2. व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता की विशेषता कनाडा के संविधान से ली गई है।

उपरोक्त कथनों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिये?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.9) Solution (d)

➢ संविधान में संशोधन और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है।

➢ व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की विशेषताएं ऑस्ट्रेलियाई संविधान से उधार ली गई हैं।

Q.10) भारत के संविधान की अनुसूचियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. संविधान की तीसरी अनुसूची में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए शपथ या प्रतिज्ञान के रूपों का प्रावधान है।

2. अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान संविधान की छठी अनुसूची में दिए गए हैं।

उपरोक्त कथनों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिये?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.10) Solution (a)

संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित के लिए शपथ या प्रतिज्ञान के रूपों का प्रावधान है:

- केंद्रीय मंत्री
- संसद चुनाव के लिए उम्मीदवार
- संसद सदस्य
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
- भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
- राज्य के मंत्री
- राज्य विधानमंडल चुनाव उम्मीदवार
- राज्य विधानमंडल सदस्य
- उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश

अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान संविधान की पांचवीं अनुसूची में दिए गए हैं।

Q.11) निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित है?

1. राजनीतिक न्याय
2. आस्था की स्वतंत्रता
3. वैधानिक न्याय
4. राजनीतिक स्वतंत्रता
5. आर्थिक समानता

उपरोक्त कथनों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिये:

a) केवल 1 और 2

b) केवल 1, 2, और 4
c) केवल 2, 4 और 5
d) 1, 2, 3, 4 और 5

Q. 11) Solution (a)

भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य है जो राष्ट्र के लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए, संविधान के सिद्धांतों को प्रस्तुत करने हेतु, उस स्रोत को इंगित करने के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करता है जिससे दस्तावेज़ अपना अधिकार और अर्थ प्राप्त करता है। यह लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को दर्शाता है। प्रस्तावना को उस परिचय अथवा भूमिका के रूप में संदर्भित किया जा सकता है जो संपूर्ण संविधान पर प्रकाश डालती है।

अपने वर्तमान स्वरुप में प्रस्तावना है:

"हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक

गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता,

प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में,

व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और

अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर

अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ईस्वी (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत दो हजार छह विक्रमी) को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कानूनी/ वैधानिक न्याय, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक समानता भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं हैं।

Q. 12) भारतीय संविधान की "प्रस्तावना" के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह विधायिका के लिए शक्ति का स्रोत है।
2. यह न्यायोचित नहीं (non-justiciable) है।

उपरोक्त कथनों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिये?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.12) Solution (b)

प्रस्तावना मूल दर्शन और मौलिक मूल्यों-राजनीतिक, नैतिक और धार्मिक- का प्रतीक है जिस पर संविधान आधारित है। इसमें संविधान सभा की भव्य और महान दृष्टि शामिल है और यह संविधान के संस्थापकों के सपनों और आकांक्षाओं को दर्शाता है। संविधान के किसी अन्य भाग की तरह प्रस्तावना को भी संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था; लेकिन, बाकी संविधान के लागू होने के बाद ऐसा किया गया था। प्रस्तावना को अंत में सम्मिलित करने का कारण यह सुनिश्चित करना था कि यह संविधान सभा द्वारा अपनाए गए संविधान के अनुरूप हो। प्रस्तावना को वोट के लिए अग्रेषित करते हुए संविधान सभा के अध्यक्ष ने कहा, प्रश्न यह है कि क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। प्रस्ताव को तब अपनाया गया था। इसलिए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्तमान राय है कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है। संविधान के संस्थापकों की राय के अनुरूप है।
हालाँकि, दो बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए:

1. प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही विधायिका की शक्तियों पर रोक है।
2. यह गैर-न्यायसंगत है, अर्थात इसके प्रावधान कानून की अदालतों में लागू करने योग्य नहीं हैं।

Q.13) भारत के संविधान में निहित राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के तहत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करें:

1. मातृत्व राहत (maternity relief) का प्रावधान करना।
2. गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना।
3. कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना।
4. धन और उत्पादन के साधनों की एकाग्रता की रोकथाम सुनिश्चित करना।

उपरोक्त में से कौन से समाजवादी सिद्धांत हैं जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में परिलक्षित होते हैं?

a) केवल 1, 2, और 3
b) केवल 2, 3, और 4
c) केवल 1, 2, और 4
d) 1, 2, 3 और 4

Q.13) Solution (c)

संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कोई वर्गीकरण नहीं है। हालांकि, उनकी विषय-सामग्री और दिशा के आधार पर उन्हें तीन व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी-बौद्धिक।

समाजवादी सिद्धांत समाजवाद की विचारधारा को दर्शाते हैं। वे एक लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य के ढांचे को निर्धारित करते हैं, जिसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना और कल्याणकारी राज्य की दिशा में रास्ता तय करना है। वे राज्य को निर्देशित करते हैं:

1. सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा व्याप्त सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करके आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करना (अनुच्छेद 38) और लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना।
2. (क) सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार सुरक्षित करने के लिए; (ख) सामान्य हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का समान वितरण; (ग) धन और उत्पादन के साधनों की एकाग्रता की रोकथाम; (घ) पुरुष और महिलाओं के समान कार्य के लिए समान वेतन; (ङ) बलात दुर्व्यवहार के विरुद्ध श्रमिकों और बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति का संरक्षण; और (च) बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसर (अनुच्छेद 39)।
3. समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना (अनुच्छेद 39 ए)।
4. बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और अक्षमता के मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार सुरक्षित करना (अनुच्छेद 41)।
5. काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों और मातृत्व राहत का प्रावधान करना (अनुच्छेद 42)।
6. सभी श्रमिकों के लिए एक जीवित मजदूरी, एक सभ्य जीवन स्तर और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों को सुरक्षित करने के लिए (अनुच्छेद 43)।
7. उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना (अनुच्छेद 43 ए)।
8. लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना (अनुच्छेद 47)।

Q.14) भारतीय संविधान में, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना शामिल है:

a) संविधान की प्रस्तावना
b) राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत
c) मौलिक कर्तव्य
d) नौवीं अनुसूची

Q.14) Solution (b)

राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित हैं। संविधान के अनुच्छेद 50 में राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रावधान है।

Q.15) निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में निर्धारित नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों में से हैं?

1. प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना।
2. भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना।
3. बलात दुर्व्यवहार के खिलाफ श्रमिकों और बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति की रक्षा करना।
4. सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा त्यागना।

उपरोक्त कथनों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिये:

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2, 3 और 4
c) केवल 1, 2 और 4
d) 1, 2, 3 और 4

Q.15) Solution (c)

मौलिक कर्तव्यों को देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने और भारत की एकता को बनाए रखने में मदद करने के लिए सभी नागरिकों के नैतिक दायित्वों के रूप में परिभाषित किया गया है। ये कर्तव्य संविधान के भाग IV-A में निर्धारित किये गए हैं। अनुच्छेद 51ए के अनुसार, यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा:

1. संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना।
2. स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना और उनका अनुसरण करना।
3. भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना।
4. देश की रक्षा करना और ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना।
5. भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधताओं से परे सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना और महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना।
6. देश की समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना।
7. वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति करुणा भाव रखना।
8. वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करना।
9. सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना।
10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना ताकि राष्ट्र निरंतर उद्यम और उपलब्धि के उच्च स्तर तक बढ़ सके।
11. छह से चौदह वर्ष तक की आयु के बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ा गया था।

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में बलात दुर्व्यवहार के खिलाफ श्रमिकों और बच्चों के स्वास्थ्य और सामर्थ्य के संरक्षण का प्रावधान है।

Q.16) राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है/हैं?

1. वे सत्ता में पार्टी के परिवर्तन के बावजूद घरेलू और विदेशी नीतियों में स्थिरता और निरंतरता को सुगम बनाते हैं।
2. वे नागरिकों द्वारा मौलिक अधिकारों के पूर्ण और उचित आनंद के लिए एक अनुकूल वातावरण का निर्माण करते हैं।

उपरोक्त कथनों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिये:

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.16) Solution (c)

राज्य के नीति निदेशक तत्व निम्नलिखित महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं:

1. वे सत्ता में पार्टी के परिवर्तन के बावजूद राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में घरेलू और विदेशी नीतियों में स्थिरता और निरंतरता को सुगम बनाते हैं।

2. वे नागरिकों के मौलिक अधिकारों के पूरक हैं। उनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक अधिकार प्रदान करके भाग III में रिक्त स्थान को भरना है।

3. उनका कार्यान्वयन नागरिकों द्वारा मौलिक अधिकारों के पूर्ण और उचित आनंद के लिए अनुकूल वातावरण बनाता है। आर्थिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं है।

4. वे विपक्ष को सरकार के संचालन पर प्रभाव और नियंत्रण करने में सक्षम बनाते हैं। विपक्ष सत्ताधारी दल को इस आधार पर दोष दे सकता है कि उनकी गतिविधियां निर्देशों के खिलाफ हैं।

5. वे सरकार के प्रदर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा के रूप में कार्य करते हैं। लोग इन संवैधानिक घोषणाओं के आलोक में सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की जांच कर सकते हैं।

6. वे एक साझा राजनीतिक घोषणापत्र के रूप में कार्य करते हैं। 'एक सत्तारूढ़ दल, चाहे वह अपनी राजनीतिक विचारधारा का हो, को इस तथ्य को पहचानना होगा कि इन सिद्धांतों का उद्देश्य उसके विधायी और कार्यकारी कृत्यों में उसका मार्गदर्शक, दार्शनिक और मित्र होना है।

Q.17) वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Freedom of Expression) के अधिकार में शामिल हैं:

1. वाणिज्यिक विज्ञापनों की स्वतंत्रता।
2. न्यायाधीश और वकीलों के बीच अदालतों में मौखिक वाद की रिपोर्ट की स्वतंत्रता।
3. मौन रहने की स्वतंत्रता।
4. सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार।

उपरोक्त कथनों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिये:

a) केवल 1
b) केवल 1, 2 और 3
c) केवल 1, 2 और 4
d) 1, 2, 3 और 4

Q.17) Solution (d)

वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Freedom Of Expression) का तात्पर्य है कि प्रत्येक नागरिक को अपने विचार, राय, विश्वास और आस्था को मौखिक रूप से, लेखन, मुद्रण, चित्र या किसी अन्य तरीके से स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित शामिल हैं:

- अपने विचारों के साथ-साथ दूसरों के विचारों को प्रचारित करने का अधिकार।
- पत्रकारिता की स्वतंत्रता।
- वाणिज्यिक विज्ञापनों की स्वतंत्रता।
- टेलीफोन पर बातचीत के टैपिंग के खिलाफ अधिकार।
- प्रसारण का अधिकार अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सरकार का कोई एकाधिकार नहीं है।
- किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा बुलाए गए बंद (bundh) के खिलाफ अधिकार।
- सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार।
- मौन रहने की स्वतंत्रता।
- किसी समाचार पत्र पर पूर्व सेंसरशिप लगाने के विरुद्ध अधिकार।
- प्रदर्शन या धरना देने का अधिकार लेकिन हड़ताल करने का अधिकार नहीं।

उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में एक निर्णय में कहा, कि मीडिया को न्यायाधीशों और वकीलों के बीच अदालतों में मौखिक वाद सहित सुनवाई के दौरान की गई टिप्पणियों की रिपोर्ट करने का अधिकार है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है।

Q.18) निजता का अधिकार संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है:

1. अनुच्छेद 19
2. अनुच्छेद 21
3. अनुच्छेद 23
4. अनुच्छेद 24

उपरोक्त कथनों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिये:

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 3 और 4

d) केवल 2 और 4

Q.18) Solution (a)

न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ में उच्चतम न्यायालय ने माना कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आंतरिक हिस्से के रूप में और संविधान के भाग III द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के एक हिस्से के रूप में संरक्षित है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि निजता का अधिकार एक पूर्ण अधिकार नहीं है और राज्य या गैर-राज्य अभिनेताओं द्वारा निजता के किसी भी अतिक्रमण को निम्नलिखित तीन परीक्षणों को पूरा करना चाहिए:

1. वैध उद्देश्य
2. समानता
3. वैधता

Q.19) निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए उपलब्ध है?

1. प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार
2. भेदभाव का निषेध
3. जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा

उपरोक्त कथनों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिये:

a) केवल 1
b) केवल 3
c) केवल 1 और 2
d) केवल 2 और 3

Q.19) Solution (a)

निम्नलिखित मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए उपलब्ध हैं:

मौलिक अधिकारों का पालन भारत के नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए उपलब्ध हैं:

1. विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण (अनुच्छेद 14)।
2. अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण (अनुच्छेद 20)
3. जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा (अनुच्छेद 21)
4. प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21A)।
5. कुछ मामलों (अनुच्छेद 22) में गिरफ्तारी और नजरबंदी के विरुद्ध सुरक्षा।
6. मानव दुर्व्यापार, बेगार तथा बंधुआ मज़दूरी की प्रथा का उन्मूलन (अनुच्छेद 23)।
7. कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर रोक (अनुच्छेद 24)।

8. अंत:करण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25)।
9. धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 26)।
10. किसी भी धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से मुक्ति (अनुच्छेद 27)।
11. कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने से स्वतंत्रता (अनुच्छेद 28)

निम्नलिखित मौलिक अधिकार केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, विदेशियों के लिए नहीं:

1. धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध (अनुच्छेद15)।
2. सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता (अनुच्छेद 16)
3. स्वतंत्रता के संबंध में छह अधिकारों का संरक्षण: (i) भाषण और अभिव्यक्ति, (ii) सभा, (iii) संघ, (iv) आंदोलन, (v) निवास, और (vi) व्यवसाय (अनुच्छेद 19)।
4. जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण (अनुच्छेद 21)।
5. अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार (अनुच्छेद 30)

Q.20) निम्नलिखित में से कौन सा देश में लोकतांत्रिक प्रणाली का आधार है और साथ ही सरकार के अधिकार की पूर्णता की जांच करता है?

a) प्रस्तावना
b) राज्य के नीति निर्देशक तत्व
c) मौलिक कर्तव्य
d) मौलिक अधिकार

Q.20) Solution (d)

मौलिक अधिकार निम्नलिखित मामलों में महत्वपूर्ण हैं:

- वे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार हैं।
- वे सरकार के अधिकार की पूर्णता की जांच करते हैं।
- वे मनुष्य की भौतिक और नैतिक सुरक्षा के लिए आवश्यक शर्तें प्रदान करते हैं।
- वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के एक दुर्जेय कवच के रूप में कार्य करते हैं।
- वे देश में कानून के शासन की स्थापना की सुविधा प्रदान करते हैं।
- वे अल्पसंख्यकों और समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करते हैं।
- वे भारतीय राज्य के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को मजबूत करते हैं।
- वे सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय की आधारशिला रखते हैं।
- वे व्यक्तियों की गरिमा और सम्मान सुनिश्चित करते हैं।
- वे राजनीतिक और प्रशासनिक प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी को सुगम बनाते हैं।

Q.21) प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है:

1. रिफ़रेंडम/ मत-संग्रह (Referendum) सार्वजनिक महत्व के किसी भी मुद्दे पर लोगों की राय प्राप्त करने की एक विधि है। इसका उपयोग आमतौर पर क्षेत्रीय/ प्रादेशिक विवादों को हल करने के लिए किया जाता है।
2. पहल (Initiative) एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा लोग विधायिका को अधिनियमित करने के लिए एक विधेयक का प्रस्ताव दे सकते हैं।
3. रिकॉल (Recall) एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से मतदाता किसी प्रतिनिधि या अधिकारी को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले हटा सकते हैं, जब वह अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन करने में विफल रहता है।
4. जनमत-संग्रह (Plebiscite) एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत एक प्रस्तावित कानून को मतदाताओं को उनके प्रत्यक्ष मतों द्वारा निपटान के लिए भेजा जाता है।

उपरोक्त कथनों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिये:

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 3 और 4
d) केवल 1 और 4

Q. 21) Solution (b)

लोकतंत्र दो प्रकार का होता है-प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, लोग अपनी सर्वोच्च शक्ति का सीधे प्रयोग करते हैं जैसा कि स्विट्जरलैंड में होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के चार उपकरण हैं, अर्थात् रिफ़रेंडम (Referendum), पहल (Initiative), रिकॉल (Recall) और जनमत-संग्रह (Plebiscite)।

- रिफ़रेंडम/ मत-संग्रह (Referendum) एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत एक प्रस्तावित कानून को मतदाताओं को उनके प्रत्यक्ष वोटों द्वारा निपटान के लिए भेजा जाता है।
- पहल (Initiative) एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा लोग विधायिका को अधिनियमित करने के लिए एक विधेयक का प्रस्ताव दे सकते हैं।
- रिकॉल (Recall) एक ऐसा विधि है जिसके माध्यम से मतदाता किसी प्रतिनिधि या अधिकारी को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले हटा सकते है, जब वह अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन करने में विफल रहता है।
- जनमत-संग्रह (Plebiscite) सार्वजनिक महत्व के किसी भी मुद्दे पर भारत के लोगों की राय प्राप्त करने का एक तरीका है। यह आमतौर पर क्षेत्रीय/ प्रादेशिक विवादों को हल करने के लिए प्रयोग किया जाता है।

Q. 22) भारतीय संविधान में निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा भारतीय राज्य की प्रकृति को परिभाषित करता है?

1. मौलिक कर्तव्य
2. मौलिक अधिकार
3. प्रस्तावना

4. राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत

Q. 22) Solution (c)

प्रस्तावना चार अवयवों या घटकों को प्रकट करती है:

1. संविधान के अधिकार का स्रोत: प्रस्तावना में कहा गया है कि संविधान भारत के लोगों से अपना अधिकार प्राप्त करता है।

2. भारतीय राज्य की प्रकृति: यह भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक और गणतंत्रात्मक राज्य घोषित करता है।

3. संविधान के उद्देश्य: यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को उद्देश्यों के रूप में निर्दिष्ट करता है।

4. संविधान को अपनाने की तिथि: यह तारीख के रूप में 26 नवंबर, 1949 को निर्धारित करती है।

Q. 23) संविधान की प्रस्तावना भारत को संप्रभु गणराज्य घोषित करती है। भारतीय संदर्भ में "गणराज्य" शब्द क्या है?

1. भारत में एक निश्चित अवधि के लिए एक निर्वाचित प्रमुख होता है।
2. निर्वाचित प्रमुख में राजनीतिक संप्रभुता का निहित होना।
3. किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति।

उपरोक्त कथनों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिये?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 1 और 3
c) केवल 2 और 3
d) 1, 2 और 3

Q. 23) Solution (b)

एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है- राजशाही और गणतंत्र। एक राजशाही में, राज्य के प्रमुख (आमतौर पर राजा या रानी) को वंशानुगत स्थिति प्राप्त होती है, अर्थात वह उत्तराधिकार के माध्यम से कार्यालय में आता है, उदाहरण के लिए, ब्रिटेन। एक गणतंत्र में, दूसरी ओर, राज्य के प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित अवधि के लिए चुने जाते हैं, उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका।

इसलिए, हमारी प्रस्तावना में 'गणतंत्र' शब्द इंगित करता है कि भारत में एक निर्वाचित प्रमुख है जिसे राष्ट्रपति कहा जाता है। वह अप्रत्यक्ष रूप से पांच साल की तय अवधि के लिए चुने जाते हैं।

एक 'गणतंत्र' के अर्थ में दो और चीजें भी हैं: एक, लोगों में राजनीतिक संप्रभुता का निहित होना और राजा जैसे किसी एक व्यक्ति में नहीं; दूसरा, किसी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का अभाव और इसलिए सभी सार्वजनिक कार्यालयों को बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुले रहते हैं।

Q. 24) मौलिक अधिकारों की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. वे न्यायोचित (justiciable) हैं।
2. वे निरपेक्ष (absolute) और अर्हताप्राप्त (qualified) हैं।
3. उनमें से कुछ चरित्र में नकारात्मक हैं।
4. वे अनुल्लंघनीय और स्थायी हैं।

उपरोक्त कथनों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिये?

a) केवल 1 और 4
b) केवल 2 और 3
c) केवल 2 और 4
d) केवल 1 और 3

Q. 24) Solution (d)

संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों की विशेषता निम्नलिखित है:

- वे न्यायोचित हैं, यदि उनका उल्लंघन किया जाता है, तो व्यक्तियों को उनके प्रवर्तन के लिए अदालतों में जाने की अनुमति दी गई है।
- वे निरपेक्ष नहीं बल्कि अर्हताप्राप्त (qualified) हैं। राज्य उन पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। हालाँकि, इस तरह के प्रतिबंध उचित हैं या नहीं, यह अदालतों द्वारा तय किया जाना है। इस प्रकार, वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच व्यक्ति और पूरे समाज के अधिकारों के बीच संतुलन बनाते हैं।
- उनमें से कुछ चरित्र में नकारात्मक हैं, अर्थात्, राज्य के अधिकार पर सीमाएं लगाते हैं, जबकि अन्य प्रकृति में सकारात्मक हैं, व्यक्तियों को कुछ विशेषाधिकार प्रदान करते हैं।
- वे अनुल्लंघनीय या स्थायी नहीं हैं। संसद उन्हें कम या निरस्त कर सकती है लेकिन केवल एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा, न की एक सामान्य अधिनियम द्वारा। इसके अलावा, यह संविधान के 'बुनियादी ढांचे' को प्रभावित किए बिना किया जा सकता है।

Q. 25) संविधान के भाग-3 के विभिन्न प्रावधानों में उल्लिखित "राज्य" शब्द में क्या शामिल है?

1. भारत की संसद
2. राज्यों के विधानमंडल
3. स्थानीय अधिकारी
4. सांविधिक और गैर-सांविधिक प्राधिकरण

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिये:

a) केवल 1
b) केवल 1 और 2
c) केवल 1, 2 और 3
d) 1, 2, 3 और 4

Q. 25) Solution (d)

मौलिक अधिकारों से संबंधित विभिन्न प्रावधानों में 'राज्य' शब्द का प्रयोग किया गया है। इसलिए, अनुच्छेद 12 ने भाग-3 के प्रयोजनों के लिए शब्द को परिभाषित किया है। इसके अनुसार, राज्य में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. भारत की सरकार और संसद, अर्थात केंद्र सरकार की कार्यपालिका और विधायी अंग।
2. राज्यों की सरकार और विधायिका अर्थात राज्य सरकार की कार्यपालिका और विधायी अंग।
3. सभी स्थानीय प्राधिकरण, जो नगर पालिकाओं, पंचायतों, जिला बोर्डों, सुधार न्यास आदि हैं।
4. अन्य सभी प्राधिकरण, अर्थात एलआईसी, ओएनजीसी, सेल आदि जैसे सांविधिक या गैर-सांविधिक प्राधिकरण।

इस प्रकार, राज्य को व्यापक अर्थों में परिभाषित किया गया है ताकि इसकी सभी एजेंसियों को शामिल किया जा सके। इन एजेंसियों के कार्यों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के रूप में अदालतों में चुनौती दी जा सकती है।

उच्चतम न्यायालय के अनुसार, यहां तक कि राज्य के साधन के रूप में काम करने वाली एक निजी संस्था या एजेंसी भी अनुच्छेद 12 के अंतर्गत 'राज्य' के अर्थ में आती है।

Q. 26) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है।
2. शिक्षा के अधिकार के अनुसरण में संसद ने निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 लागू किया।

उपरोक्त कथनों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिये?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 26) Solution (b)

अनुच्छेद 21 ए में घोषणा की गई है कि राज्य छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को राज्य द्वारा निर्धारित तरीके से मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। इस प्रकार, यह प्रावधान केवल प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है, न कि उच्च या व्यावसायिक शिक्षा को।

यह प्रावधान 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। यह संशोधन 'सभी के लिए शिक्षा' प्राप्त करने के देश के उद्देश्य में एक प्रमुख मील का पत्थर है। सरकार ने इस कदम को 'नागरिकों के अधिकारों के अध्याय में दूसरी क्रांति की सुबह' बताया।

उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को मान्यता दी।

अनुच्छेद 21ए के अनुसरण में संसद ने निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 लागू किया। इस अधिनियम में यह प्रावधान करने का प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक बच्चे को औपचारिक स्कूल में संतोषजनक और समान गुणवत्ता की पूर्णकालिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने का अधिकार है जो कुछ आवश्यक मानदंडों और मानकों को पूरा करता है।

Q. 27) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के पास मूल और अनन्य क्षेत्राधिकार है।
2. सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य अदालत को मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करने का अधिकार दे सकता है।

उपरोक्त कथनों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिये?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 27) Solution (d)

मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के मामले में, उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार मूल है लेकिन अनन्य नहीं है। यह अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के साथ समवर्ती है। यह मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सभी प्रकार के निर्देश, आदेश और रिट जारी करने के लिए उच्च न्यायालय में मूल शक्तियां निहित करता है। इसका मतलब है कि जब किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो पीड़ित पक्ष के पास सीधे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जाने का विकल्प होता है।

अनुच्छेद 32 एक पीड़ित नागरिक के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार का अधिकार प्रदान करता है। उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि अनुच्छेद 32 संविधान की एक मूल विशेषता है। इसलिए, इसे संविधान में संशोधन के माध्यम से भी संक्षिप्त या हटाया नहीं जा सकता है। इसमें निम्नलिखित चार प्रावधान शामिल हैं:

- मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उचित कार्यवाही द्वारा उच्चतम न्यायालय जाने के अधिकार की गारंटी है।

- उच्चतम न्यायालय के पास किसी भी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए निर्देश या आदेश या रिट जारी करने का अधिकार होगा। जारी किए गए रिट में बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण और अधिकार-पृच्छा शामिल हो सकते हैं।
- संसद किसी भी अन्य न्यायालय को सभी प्रकार के निर्देश, आदेश और रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। हालाँकि, यह सर्वोच्च न्यायालय को प्रदत्त उपरोक्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया जा सकता है। यहां किसी अन्य न्यायालय में उच्च न्यायालय शामिल नहीं हैं क्योंकि अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को पहले ही ये शक्तियां प्रदान कर चुका है।
- उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार संविधान द्वारा प्रदान किए गए अन्यथा के अलावा निलंबित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार संविधान में प्रावधान है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 359) के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी अदालत में जाने के अधिकार को निलंबित कर सकते हैं।

Q. 28) संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और 1978 के 44 वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक कानूनी अधिकार बनाया गया। इसके निहितार्थ क्या है/हैं?

1. निजी संपत्ति कार्यकारी कार्रवाई के खिलाफ सुरक्षित है लेकिन विधायी कार्रवाई के खिलाफ नहीं।
2. जब राज्य अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की संपत्ति का अधिग्रहण करता है तो मुआवजे का कोई गारंटीकृत अधिकार प्रदान नहीं किया जाता है।
3. जब राज्य व्यक्तिगत कृषि के अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा धारित भूमि का अधिग्रहण करता है तो मुआवजे का कोई गारंटीशुदा अधिकार प्रदान नहीं किया जाता है।

उपरोक्त कथनों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिये?

a) केवल 1
b) केवल 1 और 2
c) केवल 3
d) 1, 2 और 3

Q. 28) Solution (a)

मूल रूप से, संपत्ति का अधिकार संविधान के भाग III के तहत सात मौलिक अधिकारों में से एक था। 1978 के 44 वें संशोधन अधिनियम ने भाग III से अनुच्छेद 19 (1) (F) और अनुच्छेद 31 को निरस्त करके संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया। इसके बजाय, अधिनियम ने 'संपत्ति का अधिकार' शीर्षक के तहत भाग XII में एक नया अनुच्छेद 300A सम्मिलित किया। इसमें प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति कानून के अधिकार को छोड़कर उसकी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा।

इस प्रकार, संपत्ति का अधिकार अभी भी एक कानूनी अधिकार या एक संवैधानिक अधिकार बना हुआ है, हालांकि अब एक मौलिक अधिकार नहीं है। यह संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है।

कानूनी अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार (मौलिक अधिकारों से अलग) के निम्नलिखित निहितार्थ हैं:

- इसे संसद के एक सामान्य कानून द्वारा संवैधानिक संशोधन के बिना विनियमित किया जा सकता है, अर्थात, घटाया, संक्षिप्त या संशोधित किया जा सकता है।
- यह कार्यकारी कार्रवाई के खिलाफ निजी संपत्ति की रक्षा करता है लेकिन विधायी कार्रवाई के खिलाफ नहीं।
- उल्लंघन के मामले में, पीड़ित व्यक्ति इसके प्रवर्तन के लिए अनुच्छेद 32 (रिट सहित संवैधानिक उपचार का अधिकार) के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकता है। वह अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकता है।
- राज्य द्वारा निजी संपत्ति के अधिग्रहण या मांग के मामले में मुआवजे का कोई गारंटी अधिकार नहीं है।

हालांकि भाग III के तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है,लेकिन भाग III में अभी भी दो प्रावधान हैं जो राज्य द्वारा निजी संपत्ति के अधिग्रहण या मांग के मामले में मुआवजे के गारंटीकृत अधिकार का प्रावधान करते हैं। ये दो मामले जहां मुआवजे का भुगतान किया जाना है:

- जब राज्य अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की संपत्ति का अधिग्रहण करता है (अनुच्छेद 30); तथा
- जब राज्य व्यक्तिगत कृषि के अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा धारित भूमि का अधिग्रहण करता है और भूमि वैधानिक सीमा के भीतर है (अनुच्छेद 31 ए)।

पहला प्रावधान 44वें संशोधन अधिनियम (1978) द्वारा जोड़ा गया था, जबकि दूसरा प्रावधान 17वें संशोधन अधिनियम (1964) द्वारा जोड़ा गया।

Q. 29) निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा समाजवाद की विचारधारा को दर्शाता है?

1. कार्य हेतु न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों और मातृत्व राहत का प्रावधान करना।
2. बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसरों को सुरक्षित करना।
3. पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करना।

उपरोक्त कथनों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिये?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3

Q. 29) Solution (a)

संविधान में निर्देशक सिद्धांतों का कोई वर्गीकरण नहीं है। हालांकि, उनकी सामग्री और दिशा के आधार पर उन्हें तीन व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी-बौद्धिक।

समाजवादी सिद्धांत समाजवाद की विचारधारा को दर्शाते हैं। उन्होंने एक लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य की रूपरेखा तैयार की, जिसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना और कल्याणकारी राज्य की ओर मार्ग प्रशस्त करना था। वे राज्य को निर्देशित करते हैं:

1. सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा व्याप्त सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करना (अनुच्छेद 38)।
2. सभी नागरिकों के लिए (क) आजीविका के पर्याप्त साधनों के अधिकार सुरक्षित करना; (ख) आम भलाई के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का समान वितरण; (ग) धन की एकाग्रता और उत्पादन के साधनों की रोकथाम; (घ) पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन; (ङ) बलात दुर्व्यवहार के विरुद्ध कामगारों और बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति का संरक्षण; और (च) बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर (अनुच्छेद 39)।
3. समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना (अनुच्छेद 39 A)।
4. बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता के मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करना। (अनुच्छेद 41)
5. काम हेतु न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों और मातृत्व राहत का प्रावधान करना (अनुच्छेद 42)।
6. सभी श्रमिकों के लिए एक जीवनयापन वेतन, एक सभ्य जीवन स्तर और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों को सुरक्षित करना (अनुच्छेद 43)।
7. उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना (अनुच्छेद 43 A)।
8. लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना (अनुच्छेद 47)।

Q.30) राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन से 1976 के 42 वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए थे?

1. बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसरों को सुरक्षित करना।
2. आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करना
3. उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना।
4. सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना।

उपरोक्त कथनों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिये?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 4
c) केवल 3 और 4
d) केवल 1 और 3

Q. 30) Solution (d)

1976 के 42वें संशोधन अधिनियम ने मूल सूची में चार नए निदेशक सिद्धांतों को जोड़ा। वे राज्य के लिए आवश्यक है:

1. बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना (अनुच्छेद 39)।
2. समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना (अनुच्छेद 39 A)।
3. उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना (अनुच्छेद 43 A)।
4. पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा वनों और वन्य जीवों की रक्षा करना (अनुच्छेद 48 A)।

1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने एक और निर्देशक सिद्धांत जोड़ा, जिसके लिए राज्य को आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने की आवश्यकता है (अनुच्छेद 38)।

2002 के 86 वें संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 45 की विषय-वस्तु को बदल दिया और प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 A के तहत एक मौलिक अधिकार बना दिया। संशोधित निर्देश में राज्य को छह वर्ष की आयु पूरी होने तक सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है।

2011 के 97 वें संशोधन अधिनियम में सहकारी समितियों से संबंधित एक नया निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया। इसके लिए राज्य को सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है (अनुच्छेद 43 B)

Q. 31) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. नए राज्यों के गठन से संबंधित कानून को संसद में विशेष बहुमत से पारित किया जाएगा।
2. अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करके भारतीय क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को सौंपा जा सकता है।
3. भारत और दूसरे देश के बीच सीमा विवाद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करके सुलझाया जा सकता है।

उपरोक्त कथनों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिये ?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2
c) केवल 2 और 3
d) 1, 2 और 3

Q. 31) Solution (b)

संविधान (अनुच्छेद 4) में ही यह घोषणा की गई है कि नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना के लिए बनाए गए कानून (अनुच्छेद 2 के तहत) और नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन (अनुच्छेद 3 के तहत) को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के संशोधन के रूप में नहीं माना जायेगा। इसका मतलब यह है कि इस तरह के कानूनों को साधारण बहुमत से और साधारण विधायी प्रक्रिया से पारित किया जा सकता है।

क्या किसी राज्य के क्षेत्रों को कम करने की संसद की शक्ति (अनुच्छेद 3 के तहत) में भारतीय क्षेत्र को किसी विदेशी देश को सौंपने की शक्ति भी शामिल है?

1960 में राष्ट्रपति द्वारा दिए गए एक संदर्भ में यह प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष परीक्षण के लिए आया। केंद्र सरकार के बेरूबारी संघ (पश्चिम बंगाल) के रूप में जाना जाने वाला एक क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपने के निर्णय ने राजनीतिक आंदोलन और विवाद को जन्म दिया और इस प्रकार राष्ट्रपति के संदर्भ की आवश्यकता पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि किसी राज्य के क्षेत्र को कम करने की संसद की शक्ति (अनुच्छेद 3 के तहत) में किसी विदेशी देश के लिए भारतीय क्षेत्र के अधिग्रहण को शामिल नहीं करती है। इसलिए, भारतीय क्षेत्र को केवल अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करके एक विदेशी राज्य को सौंपा जा सकता है। नतीजतन, 9वां संविधान संशोधन अधिनियम (1960) उक्त क्षेत्र को पाकिस्तान में स्थानांतरित करने के लिए अधिनियमित किया गया था।

दूसरी ओर, 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि, भारत और दूसरे देश के बीच सीमा विवाद के निपटारे के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है। यह कार्यकारी कार्रवाई द्वारा किया जा सकता है क्योंकि इसमें किसी विदेशी देश के लिए भारतीय क्षेत्र का अधिग्रहण शामिल नहीं है।

Q. 32) 1956 के बाद भारत के नए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण का सही कालक्रम क्या है:

a) दादरा और नगर हवेली, पुडुचेरी, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम
b) पुडुचेरी, दादरा और नगर हवेली, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा
c) मिजोरम, त्रिपुरा, पुडुचेरी, दादरा और नगर हवेली, नागालैंड
d) नागालैंड, दादरा और नगर हवेली, मिजोरम, पुडुचेरी, त्रिपुरा

Q. 32) Solution (a)

दादरा और नगर हवेली: पुर्तगालियों ने 1954 तक इसकी स्वतंत्रता तक इस क्षेत्र पर शासन किया। इसके बाद, प्रशासन को 1961 तक लोगों द्वारा चुने गए प्रशासक द्वारा चलाया जाता रहा। इसे 10वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1961 द्वारा भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित कर दिया गया।

पुडुचेरी: पुडुचेरी के क्षेत्र में भारत में पूर्व फ्रांसीसी प्रतिष्ठान शामिल हैं जिन्हें पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम के नाम से जाना जाता है। 1954 में फ्रांसीसियों ने इस क्षेत्र को भारत को सौंप दिया। इसके बाद, 1962 तक इसको 'अधिग्रहित क्षेत्र' के रूप में प्रशासित किया गया, बाद में इसे 14 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया।

नागालैंड: 1963 में, नागा हिल्स और त्युएनसांग क्षेत्र को असम राज्य से बाहर निकालकर नागालैंड राज्य का गठन किया गया था। ऐसा विरोधी नागों के आंदोलन को संतुष्ट करने के लिए किया गया था। हालाँकि, नागालैंड को भारतीय संघ के 16वें राज्य का दर्जा देने से पहले इसे, 1961 तक असम के राज्यपाल के नियंत्रण में रखा गया था।

त्रिपुरा: 1972 में, पूर्वोत्तर भारत के राजनीतिक मानचित्र में एक बड़ा बदलाव आया। इस प्रकार, मणिपुर और त्रिपुरा के दो केंद्र शासित प्रदेशों और मेघालय के उप-राज्य को राज्य का दर्जा मिला और दो केंद्र शासित प्रदेश मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश (मूल रूप से पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी-नेफा के रूप में जाना जाता है) अस्तित्व में आए। इसके साथ ही भारतीय संघ के राज्यों की संख्या बढ़कर 21 (मणिपुर 19वें, त्रिपुरा 20वें और मेघालय 21वें) हो गई।

Q. 33) संविधान के लागू होने के समय निम्नलिखित में से कौन से भाग बी (Part B) के राज्य थे?

1. जम्मू और कश्मीर
2. त्रिपुरा
3. मैसूर
4. मणिपुर
5. राजस्थान

उपरोक्त कथनों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिये ?

a) केवल 1, 3 और 4
b) केवल 2 और 4
c) केवल 1, 3 और 5
d) केवल 2, 4 और 5

Q. 33) Solution (c)

1950 में, संविधान में भारतीय संघ के राज्यों और क्षेत्र चार भागों - भाग A, भाग B और भाग C राज्यों और भाग D क्षेत्रों में वर्गीकृत थे। कुल मिलाकर, उनकी संख्या 29 थी।

भाग A राज्यों में ब्रिटिश भारत के नौ तत्कालीन गवर्नर प्रांत शामिल थे। भाग B राज्यों में विधायिकाओं के साथ नौ पूर्ववर्ती रियासतें शामिल थीं। भाग C राज्यों में ब्रिटिश भारत के तत्कालीन मुख्य आयुक्त के प्रांत और कुछ पूर्ववर्ती रियासतें शामिल थीं। ये भाग C राज्य (संख्या में सभी 10 में) केंद्रीय रूप से प्रशासित थे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को एकान्त भाग D प्रदेशों के रूप में रखा गया था।

भाग B राज्य थे: हैदराबाद, जम्मू और कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला और पूर्वी पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर- कोचीन, विंध्य प्रदेश।

त्रिपुरा और मणिपुर भाग C के राज्य थे।

Q. 34) संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन से संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्य विधानसभाओं की सहमति से संशोधित किये जाते हैं;

1. संघ और राज्यों की कार्यकारी शक्ति का विस्तार
2. राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण
3. नागरिकता-अधिग्रहण और समाप्ति
4. राष्ट्रपति का चुनाव और उसका तरीका

उपरोक्त कथनों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिये?

a) केवल 1 और 2

b) केवल 2 और 3
c) केवल 3 और 4
d) केवल 1 और 4

Q. 34) Solution (d)

संविधान के वे प्रावधान जो राज्य व्यवस्था के संघीय ढांचे से संबंधित हैं, संसद के विशेष बहुमत द्वारा तथा एक साधारण बहुमत द्वारा राज्य विधानसभाओं के आधे हिस्से की सहमति से संशोधित किए जा सकते हैं। यदि एक या कुछ या सभी शेष राज्य विधेयक पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो कोई बात नहीं; जैसे ही आधे राज्य अपनी सहमति देते हैं, औपचारिकता पूरी हो जाती है। ऐसी कोई समय सीमा नहीं है जिसके भीतर राज्यों को विधेयक पर अपनी सहमति देनी चाहिए।

निम्नलिखित प्रावधानों को इस प्रकार संशोधित किया जा सकता है:

- राष्ट्रपति का चुनाव और उसका तरीका।
- संघ और राज्यों की कार्यकारी शक्ति की सीमा।
- उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय।
- संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण।
- गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल (वस्तु एवं सेवा कर परिषद)
- सातवीं अनुसूची में से कोई भी सूची।
- संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व।
- संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन करने की संसद की शक्ति (अनुच्छेद 368 ही)

राज्यों में विधान परिषदों के उन्मूलन या निर्माण और नागरिकता-अधिग्रहण और समाप्ति से संबंधित प्रावधानों में केवल साधारण बहुमत के माध्यम से संशोधन किया जा सकता है।

Q. 35) अनुच्छेद 368 में निर्धारित संविधान के संशोधन से संबंधित प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति से संसद में पेश किया जाता है।
2. इस विधेयक को प्रत्येक सदन में संसद के विशेष बहुमत से ही अलग-अलग पारित किया जाना चाहिए।
3. राष्ट्रपति को विधेयक पर अपनी सहमति देनी चाहिए। वह न तो विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकता है और न ही संसद के पुनर्विचार के लिए विधेयक को वापस कर सकता है।

उपरोक्त कथनों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिये?

a) केवल 1
b) केवल 2 और 3
c) केवल 3

d) 1, 2 और 3

Q. 35) Solution (c)

अनुच्छेद 368 दो प्रकार के संशोधनों का प्रावधान करता है, अर्थात् संसद के विशेष बहुमत से और आधे राज्यों के साधारण बहुमत द्वारा अनुसमर्थन के माध्यम से। लेकिन, कुछ अन्य अनुच्छेद संसद के साधारण बहुमत से संविधान के कुछ प्रावधानों में संशोधन का प्रावधान करते हैं, यानी प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से (सामान्य विधायी प्रक्रिया के समान)। उल्लेखनीय है कि, इन संशोधनों को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं माना जाता है।

अनुच्छेद 368 में निर्धारित संविधान के संशोधन की प्रक्रिया इस प्रकार है:

1. संविधान में संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन में इस उद्देश्य के लिए एक विधेयक पेश करके शुरू किया जा सकता है, न कि राज्य विधानसभाओं में।

2. विधेयक को या तो एक मंत्री या एक निजी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है।

3. विधेयक को प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, अर्थात सदन की कुल सदस्यता का बहुमत तथा सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से।

4. प्रत्येक सदन को अलग से विधेयक पारित करना होगा। दोनों सदनों के बीच असहमति की स्थिति में, विधेयक पर विचार-विमर्श और पारित होने के उद्देश्य से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

5. यदि विधेयक संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन करना चाहता है, तो इसे आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से, यानी सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से भी अनुमोदित किया जाना चाहिए।

6. संसद के दोनों सदनों द्वारा विधिवत पारित होने और राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित होने के बाद, जहां आवश्यक हो, विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

7. राष्ट्रपति को विधेयक पर अपनी सहमति देनी चाहिए। वह न तो विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकता है और न ही संसद के पुनर्विचार के लिए विधेयक को वापस कर सकता है।

8. राष्ट्रपति की सहमति के बाद, विधेयक एक अधिनियम (यानी, एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम) बन जाता है और संविधान अधिनियम की शर्तों के अनुसार संशोधित होता है।

Q. 36) निम्नलिखित में से कौन संविधान की मूल संरचना के तत्व हैं/हैं?

1. न्यायिक समीक्षा
2. कानून का शासन
3. स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव

उपरोक्त कथनों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिये ?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3

Q. 36) Solution (d)

विभिन्न निर्णयों से, निम्नलिखित संविधान की' बुनियादी विशेषताओं 'या संविधान की' मूल संरचना' के तत्वों के रूप में उभरे हैं:

- संविधान की सर्वोच्चता
- भारतीय राज्य व्यवस्था की संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक प्रकृति
- संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र
- विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण
- संविधान का संघीय चरित्र
- राष्ट्र की एकता और अखंडता
- कल्याणकारी राज्य (सामाजिक-आर्थिक न्याय)
- न्यायिक समीक्षा
- व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा
- संसदीय प्रणाली
- कानून का शासन
- मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच सामंजस्य और संतुलन
- समानता का सिद्धांत
- स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव
- न्यायपालिका की स्वतंत्रता
- संविधान में संशोधन के लिए संसद की सीमित शक्ति
- न्याय तक प्रभावी पहुंच
- मौलिक अधिकारों के अंतर्निहित सिद्धांत (या सार)
- अनुच्छेद 32, 136, 141 और 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां
- अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालयों की शक्तियां।

Q. 37) एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक पार्टी को किन शर्तों को पूरा करना चाहिए:

1. इसे लोकसभा के आम चुनाव में किन्हीं छह या अधिक राज्यों में मतदान किये गए वैध मतों का चार प्रतिशत सुरक्षित करना चाहिए।
2. इसे कम से कम तीन राज्यों में एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।

उपरोक्त कथनों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिये ?

a) केवल 1
b) केवल 1 और 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 37) Solution (d)

एक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती है यदि निम्नलिखित में से कोई भी शर्त पूरी होती है:

1. यदि यह लोकसभा या विधान सभा के आम चुनाव में किन्हीं चार या अधिक राज्यों में डाले गए वैध मतों का छह प्रतिशत हासिल करता है; और, इसके अलावा, यह किसी भी राज्य या राज्यों से लोकसभा में चार सीटें जीतती है; या

2. यदि वह आम चुनाव में लोकसभा में दो प्रतिशत सीटें जीतती है; और ये उम्मीदवार तीन राज्यों से चुने जाते हैं; या

3. यदि इसे चार राज्यों में एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है।

Q. 38) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 15 से कम नहीं होगी।
2. एक सदन का मनोनीत सदस्य सदन के सदस्य होने के लिए अयोग्य हो जाता है यदि वह सदन में अपना स्थान ग्रहण करने की तारीख से छह महीने के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।
3. दलबदल से उत्पन्न होने वाली अयोग्यता के संबंध में सदन के पीठासीन अधिकारी का निर्णय अंतिम होता है और इसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

उपरोक्त कथनों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिये ?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) 1, 2 और 3
d) उपरोक्त से कोई नहीं

Q. 38) Solution (d)

किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधान सभा की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन, किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए।

एक सदन का मनोनीत सदस्य सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य हो जाता है यदि वह सदन में अपना स्थान ग्रहण करने की तारीख से छह महीने की समाप्ति के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। इसका मतलब है कि वह इस अयोग्यता को आमंत्रित किए बिना सदन में अपना स्थान ग्रहण करने के छह महीने के भीतर किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो सकता है।

दलबदल से उत्पन्न अयोग्यता के संबंध में कोई प्रश्न सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा तय किया जाएगा। मूल रूप से, अधिनियम में यह प्रावधान है कि पीठासीन अधिकारी का निर्णय अंतिम है और किसी भी अदालत में इसपर प्रश्न नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, किहोतो होलोहन मामले (1993) में, सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रावधान को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित किया कि वह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को छीनना चाहता है। यह माना गया कि पीठासीन अधिकारी दसवीं अनुसूची के तहत एक प्रश्न का निर्णय करते समय एक न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करता है। इसलिए, किसी भी अन्य न्यायाधिकरण की तरह उसका निर्णय दुर्भावना, विकृति आदि के आधार पर न्यायिक समीक्षा के अधीन है। लेकिन, अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि पीठासीन अधिकारी में निर्णयात्मक शक्तियों का निहित होना राजनीतिक पूर्वाग्रह के आधार पर अपने आप में अमान्य है ।

Q. 39) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति, स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से करता है।
2. केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाओं की स्थापना उन पर राष्ट्रपति और संसद के सर्वोच्च नियंत्रण पर कुछ प्रतिबंध लगाती है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

a) केवल 1
b) केवल **2**
c) दोनों 1 **और** 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 39) Solution (a)

Basic Information:

- प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से करता है। एक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक राष्ट्रपति का एजेंट होता है, न कि राज्यपाल की तरह राज्य का मुखिया।
- राष्ट्रपति एक प्रशासक के पद को निर्दिष्ट कर सकता है; यह उपराज्यपाल या मुख्य आयुक्त या प्रशासक हो सकता है।
- राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक भी नियुक्त कर सकता है। उस क्षमता में, राज्यपाल को अपने मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रूप से कार्य करना होता है।
- केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संसद तीन सूचियों (राज्य सूची सहित) के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है।
- राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए विनियम में संसद के अधिनियम के समान बल और प्रभाव होता है तथा इन केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में संसद के किसी भी अधिनियम को निरस्त या संशोधित भी कर सकता है।

नोट: केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाओं और मंत्रिपरिषद जैसी प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना से उन पर राष्ट्रपति और संसद का सर्वोच्च नियंत्रण कम नहीं होता है।

Q.40) नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. एक व्यक्ति पंजीकरण द्वारा नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है यदि वह एक वर्ष के लिए भारत में रहता है और यदि उसके माता-पिता में से कोई एक पूर्व भारतीय नागरिक है।
2. अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले कम से कम 5 साल के लिए भारत में रहने पर देशीयकरण/ प्राकृतिकरण (naturalisation) द्वारा नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं।

उपरोक्त कथनों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिये ?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 40) Solution (c)

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन करना चाहता है।

नागरिकता अधिनियम, 1955 विभिन्न तरीके प्रदान करता है जिसमें नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। यह जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिककरण और भारत में क्षेत्र को शामिल करके नागरिकता प्रदान करता है।

संशोधन अधिनियम के प्रमुख प्रावधान:

- विधेयक में अधिनियम में संशोधन करते हुए यह प्रावधान किया गया है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, जिन्होंने 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था, उन्हें अवैध प्रवासियों के रूप में नहीं माना जाएगा।
- प्राकृतिककरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए, योग्यताओं में से एक यह है कि नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले व्यक्ति को भारत में निवास करना चाहिए या कम से कम 11 वर्षों तक केंद्र सरकार की सेवा में होना चाहिए। यह विधेयक इस योग्यता के संबंध में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों के लिए एक अपवाद बनाता है। व्यक्तियों के इन समूहों के लिए, 11 वर्ष की आवश्यकता को घटाकर पांच वर्ष कर दिया जाएगा।
- अवैध प्रवासियों के लिए नागरिकता पर ये प्रावधान संविधान की छठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे। इन आदिवासी क्षेत्रों में कार्बी आंगलोंग (असम में), गारो हिल्स (मेघालय में), चकमा जिला (मिजोरम में) और त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र जिला शामिल हैं।
- इसके अलावा, यह बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, 1873 के तहत अधिसूचित "इनर लाइन" क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। इन क्षेत्रों में, भारतीयों द्वारा यात्रा 'इनर लाइन परमिट' के माध्यम से नियंत्रित होते हैं।

Q. 41) निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए:

1. बहुमत दल का शासन
2. दोहरी कार्यकारी
3. शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण
4. निचले सदन का विघटन

उपरोक्त में से कौन सी सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषताएं हैं?

a) केवल 1, 2 और 3 3
b) केवल 2, 3 और 4
c) केवल 1, 2 और 4
d) 1, 2, 3 और 4

Q. 41) Solution (c)

भारत का संविधान केंद्र और राज्यों दोनों में सरकार के संसदीय स्वरूप का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 74 और 75 केंद्र में संसदीय प्रणाली से संबंधित है और अनुच्छेद 163 और 164 राज्यों में संसदीय प्रणाली से संबंधित है।

भारत में संसदीय सरकार की विशेषताएं या सिद्धांत हैं:

- बहुमत दल का शासन: वह राजनीतिक दल जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त करता है, सरकार बनाता है। उस पार्टी के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधान मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है; अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। हालाँकि, जब किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलता है, तो राष्ट्रपति द्वारा सरकार बनाने के लिए पार्टियों के गठबंधन को आमंत्रित किया जा सकता है।
- दोहरी सदस्यता: मंत्री विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य हुए बिना मंत्री नहीं हो सकता। संविधान में कहा गया है कि एक मंत्री जो लगातार छह महीने तक संसद का सदस्य नहीं होता है, वह मंत्री नहीं रहता है।
- निचले सदन का विघटन: संसद के निचले सदन (लोकसभा) को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर भंग किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, प्रधान मंत्री राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले लोकसभा को भंग करने और नए चुनाव कराने की सलाह दे सकता है। इसका अर्थ है कि कार्यपालिका को संसदीय प्रणाली में विधायिका को भंग करने का अधिकार प्राप्त है।

शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण सरकार के राष्ट्रपति स्वरूप की विशेषता है। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली का आधार है। सरकार की विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियां सरकार के तीनों अंग में स्वतंत्र रूप से पृथक और निहित होती हैं।

Q. 42) निम्नलिखित में से कौन सरकार के संसदीय स्वरूप के गुण हैं/हैं?

1. विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य
2. निरंकुशता पर रोक (Prevents despotism)
3. नीतियों में निश्चितता (Definiteness in policies)

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

a) केवल 1 और 2

b) केवल 2 और 3

c) केवल 1 और 3

d) 1, 2 और 3

Q. 42) Solution (a)

सरकार की संसदीय प्रणाली के निम्नलिखित गुण हैं:

- विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य: संसदीय प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह सरकार के विधायी और कार्यकारी अंगों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध और सहयोग सुनिश्चित करती है। कार्यपालिका विधायिका का एक हिस्सा है और दोनों काम पर परस्पर-निर्भर हैं। नतीजतन, दोनों अंगों के बीच विवाद और संघर्ष की गुंजाइश कम होती है।
- निरंकुशता पर रोक: इस प्रणाली के तहत, कार्यकारी अधिकार व्यक्तियों के एक समूह (मंत्रिपरिषद) में निहित होता है, न कि किसी एक व्यक्ति में। सत्ता का यह फैलाव कार्यपालिका की तानाशाही प्रवृत्तियों को रोकता है। इसके अलावा, कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसे अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है।

संसदीय सरकार के दोषों में से एक यह है कि नीतियों की निरंतरता नहीं होती है। संसदीय प्रणाली दीर्घकालिक नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शक नहीं है। इसका कारण है सरकार के कार्यकाल की अनिश्चितता। सत्तारूढ़ दल में बदलाव के बाद आमतौर पर सरकार की नीतियों में बदलाव होता है।

Q. 43) निम्नलिखित में से कौन संसदीय सरकार का आधारभूत सिद्धांत है?

a) स्थिर सरकार

b) विशेषज्ञों द्वारा सरकार

c) सामूहिक उत्तरदायित्व

d) इच्छुक या उत्सुक वैकल्पिक सरकार (Ready alternative government)

Q. 43) Solution (c)

सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय सरकार का मूल सिद्धांत है। मंत्री सामूहिक रूप से संसद के प्रति और विशेष रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं (अनुच्छेद 75)। वे एक टीम के रूप में कार्य करते हैं, और एक साथ तैरते और डूबते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व के

सिद्धांत का तात्पर्य है कि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रालय (यानी, प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद) को पद से हटा सकती है।

Q. 44) निम्नलिखित में से कौन-सी संविधान की संघीय विशेषताएँ (federal features) हैं?

1. लचीला संविधान
2. लिखित संविधान
3. संविधान की सर्वोच्चता
4. राज्य अविनाशी नहीं (States not indestructible)

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

a) केवल 1 और 2

b) केवल 2 और 3

c) केवल 3 और 4

d) केवल 1 और 4

Q. 44) Solution (b)

लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता संविधान की संघीय विशेषताएं हैं जबकि संविधान का लचीलापन और राज्यों की अविनाशीता (Non indestructibility) संविधान की एकात्मक विशेषताएं हैं।

संविधान की संघीय विशेषताएं:

- लिखित संविधान: भारतीय संविधान न केवल एक लिखित दस्तावेज है बल्कि दुनिया का सबसे लंबा संविधान भी है। मूल रूप से, इसमें एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद (22 भागों में विभाजित) और 8 अनुसूचियाँ शामिल थीं। वर्तमान में (2019), इसमें एक प्रस्तावना, लगभग 470 अनुच्छेद (25 भागों में विभाजित) और 12 अनुसूचियाँ शामिल हैं। यह संरचना को निर्दिष्ट करता है। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के संगठन, शक्तियां और कार्य और उन सीमाओं को निर्धारित करता है जिनके भीतर उन्हें काम करना चाहिए। इस प्रकार, यहाँ दोनों के बीच गलतफहमी और असहमति से बचा जाता है।
- संविधान की सर्वोच्चता: भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च (या सर्वोच्च) कानून है। केंद्र और राज्यों द्वारा बनाए गए कानूनों को इसके प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए। अन्यथा, उन्हें सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों द्वारा न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति के माध्यम से अमान्य घोषित किया जा सकता है। इस प्रकार, दोनों स्तरों पर सरकार के अंगों (विधायी, कार्यकारी और न्यायिक) को संविधान द्वारा निर्धारित क्षेत्राधिकार के भीतर काम करना चाहिए।

संविधान की एकात्मक विशेषताएं:

- संविधान का लचीलापन: संविधान संशोधन की प्रक्रिया अन्य संघों की तुलना में कम कठोर है। संविधान के अधिकांश भाग को संसद की एकतरफा कार्रवाई द्वारा या तो साधारण बहुमत से या विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। इसके

अलावा, संविधान में संशोधन शुरू करने की शक्ति केवल केंद्र के पास है। अमेरिका में राज्य संविधान में संशोधन का प्रस्ताव भी दे सकते हैं।

- राज्य अविनाशी नहीं: अन्य संघों के विपरीत, भारत के राज्यों को क्षेत्रीय अखंडता का कोई अधिकार नहीं है। संसद एकतरफा कार्रवाई से किसी भी राज्य के क्षेत्र, सीमाओं या नाम को बदल सकती है। इसके अलावा, इसके लिए केवल एक साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है न कि विशेष बहुमत की। इसलिए, भारतीय संघ "विनाशकारी राज्यों का एक अविनाशी संघ" है। दूसरी ओर, अमेरिकी संघ को "अविनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ" के रूप में वर्णित किया गया है।

Q. 45) निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए:

1. आपातकालीन प्रावधान
2. एकीकृत न्यायपालिका
3. स्वतंत्र न्यायपालिका
4. अखिल भारतीय सेवाएं
5. द्विसदनीय विधानमंडल

उपरोक्त में से कौन संविधान की एकात्मक विशेषताएं (unitary features) हैं?

a) केवल 1, 2 और 3 3
b) केवल 2, 3 और 5
c) केवल 1, 2 और 4 4
d) केवल 2, 3, 4 और 5

Q. 45) Solution (c)

संविधान की एकात्मक विशेषताएं:

- आपातकालीन प्रावधान: संविधान तीन प्रकार की आपात स्थितियों को निर्धारित करता है-राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय। एक आपात स्थिति के दौरान, केंद्र सरकार पूरी तरह से शक्तिशाली हो जाती है और राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। यह संविधान के औपचारिक संशोधन के बिना संघीय ढांचे को एकात्मक में बदल देता है। इस तरह का परिवर्तन किसी अन्य संघ में नहीं मिलता है।

- एकीकृत न्यायपालिका: भारतीय संविधान ने एक एकीकृत न्यायिक प्रणाली की स्थापना की है जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे राज्य उच्च न्यायालय हैं। अदालतों की यह एकल प्रणाली केंद्रीय कानूनों के साथ-साथ राज्य के कानूनों को भी लागू करती है। दूसरी ओर, अमेरिका में, अदालतों की दोहरी प्रणाली है जिसके तहत संघीय कानून संघीय न्यायपालिका द्वारा और राज्य के कानूनों को राज्य न्यायपालिका द्वारा लागू किया जाता है।

- अखिल भारतीय सेवाएं: अमेरिका में, संघीय सरकार और राज्य सरकारों की अपनी अलग सार्वजनिक सेवाएं हैं। भारत में भी केंद्र और राज्यों की अलग-अलग सार्वजनिक सेवाएं हैं। लेकिन, इसके अलावा, अखिल भारतीय सेवाएं (आईएएस, आईपीएस और आईएफएस) हैं जो केंद्र और राज्यों दोनों के लिए समान हैं। इन सेवाओं के सदस्यों की भर्ती और प्रशिक्षण

केंद्र द्वारा किया जाता है जिसका उन पर अंतिम नियंत्रण भी होता है। इस प्रकार, ये सेवाएं संविधान के तहत संघवाद के सिद्धांत का उल्लंघन करती हैं।

संविधान की संघीय विशेषताएं:

- स्वतंत्र न्यायपालिका: संविधान दो उद्देश्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है: एक, न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करके संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करना; और दो, केंद्र और राज्यों के बीच या राज्यों के बीच विवादों को निपटाने के लिए। संविधान में न्यायपालिका को सरकार से स्वतंत्र बनाने के लिए न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, निश्चित सेवा शर्तों आदि जैसे विभिन्न उपाय शामिल हैं।
- द्विसदनीयवाद: संविधान एक द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान करता है जिसमें एक उच्च सदन (राज्य सभा) और एक निचला सदन (लोकसभा) शामिल है। राज्यसभा भारतीय संघ के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि लोकसभा समग्र रूप से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। केंद्र के अनुचित हस्तक्षेप के खिलाफ राज्यों के हितों की रक्षा करके संघीय संतुलन बनाए रखने के लिए राज्य सभा (भले ही कम शक्तिशाली सदन) की आवश्यकता होती है।

Q. 46) भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के कामकाज में निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संघवाद की भावना को दर्शाती है:

1. राज्यों के बीच क्षेत्रीय विवाद
2. नदी जल बंटवारे को लेकर राज्यों के बीच विवाद
3. क्षेत्रीय दलों का उदय और राज्यों में उनका सत्ता में आना

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3

Q. 46) Solution (d)

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के कामकाज में निम्नलिखित रुझान इसकी संघीय भावना को दर्शाते हैं::

i. राज्यों के बीच क्षेत्रीय विवाद, उदाहरण के लिए, बेलगाम को लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच।

ii. नदी के पानी के बंटवारे को लेकर राज्यों के बीच विवाद, उदाहरण के लिए, कावेरी जल को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच।

iii. आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय और उनका सत्ता में आना।

iv. क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नए राज्यों का निर्माण, उदाहरण के लिए मिजोरम या झारखंड।

v. राज्यों की विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र से अधिक वित्तीय अनुदान की मांग।

vi. राज्यों द्वारा स्वायत्तता का दावा और केंद्र के हस्तक्षेप का उनका प्रतिरोध।

vii. केंद्र द्वारा अनुच्छेद 356 (राज्यों में राष्ट्रपति शासन) के उपयोग पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा कई प्रक्रियात्मक सीमाएं लागू करना।

Q. 47) राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है।
2. राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को जारी होने की तारीख से दो महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।
3. संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होने पर, राष्ट्रीय आपातकाल छह महीने तक जारी रहता है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

a) केवल 1
b) केवल 1 और 2
c) केवल 3
d) 1, 2 और 3

Q. 47) Solution (c)

अनुच्छेद 352 के तहत, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं जब भारत या उसके एक हिस्से की सुरक्षा को युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरा हो।

राष्ट्रपति, हालांकि, कैबिनेट से लिखित सिफारिश प्राप्त करने के बाद ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर ही नहीं, बल्कि कैबिनेट की सहमति से ही आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। 1975 में, तत्कालीन प्रधान मंत्री, इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति को अपने मंत्रिमंडल से परामर्श किए बिना आपातकाल की घोषणा करने की सलाह दी थी। घोषणा के बाद कैबिनेट को सूचित किया गया था, क्योंकि यह एक विश्वास के रूप में किया गया था। 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने इस संबंध में केवल प्रधानमंत्री द्वारा निर्णय लेने की किसी भी संभावना को समाप्त करने के लिए इस सुरक्षा उपाय की शुरुआत की।

आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। मूल रूप से, संसद द्वारा अनुमोदन के लिए अनुमत अवधि दो महीने थी, लेकिन 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा इसे कम कर दिया गया था।

यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो आपातकाल छह महीने तक जारी रहता है, और इसे हर छह महीने के लिए संसद की मंजूरी के साथ अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। समय-समय पर संसदीय अनुमोदन के लिए यह प्रावधान भी 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जोड़ा गया था।

Q. 48) राष्ट्रीय आपातकाल का भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव है/हैं?

1. राज्य सरकारों को निलंबित कर दिया जाता है और उन्हें केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में लाया जाता है।
2. संविधान संघीय के बजाय एकात्मक हो जाता है।
3. राष्ट्रपति केंद्र से राज्यों को वित्त के हस्तांतरण को या तो कम या रद्द कर सकता है।

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

a) केवल 1 और 2

b) केवल 2 और 3

c) केवल 1 और 3

d) 1, 2 और 3

Q. 48) Solution (b)

जबकि आपातकाल की घोषणा लागू है, केंद्र-राज्य संबंधों के सामान्य ताने-बाने में एक बुनियादी बदलाव आता है:

एक राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, केंद्र की कार्यकारी शक्ति किसी भी राज्य को उस तरीके के बारे में निर्देश देने तक विस्तारित है जिसमें उसकी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग किया जाना है। सामान्य समय में, केंद्र किसी राज्य को कुछ विशिष्ट मामलों पर ही कार्यकारी निर्देश दे सकता है। हालांकि, एक राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, केंद्र किसी राज्य को 'किसी भी' मामले पर कार्यकारी निर्देश देने का हकदार हो जाता है। इस प्रकार, राज्य सरकारों को केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में लाया जाता है, हालांकि उन्हें निलंबित नहीं किया जाता है।

राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, संसद को राज्य सूची में उल्लिखित किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। यद्यपि राज्य विधानमंडल की विधायी शक्ति निलंबित नहीं होती है, यह संसद की अधिभावी शक्ति के अधीन हो जाती है। इस प्रकार, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का सामान्य वितरण निलंबित होता है, हालांकि राज्य विधानमंडल निलंबित नहीं होता हैं। संक्षेप में, संविधान संघीय के बजाय एकात्मक हो जाता है।

जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा चल रही होती है, राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति केंद्र से राज्यों को वित्त के हस्तांतरण को या तो कम या रद्द कर सकता है। इस तरह का संशोधन वित्तीय वर्ष के अंत तक जारी रहता है जिसमें आपातकाल समाप्त हो जाता है।

Q. 49) अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की उद्घोषणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. राष्ट्रपति केवल तभी उद्घोषणा जारी करता है जब राज्यपाल रिपोर्ट प्रस्तुत करता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें किसी राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकती है।
2. अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा सही हैं?

a) केवल 1

b) केवल 2

c) दोनों 1 और 2

d) न तो 1 और न ही 2

Q. 49) Solution (d)

अनुच्छेद 355 यह सुनिश्चित करने के लिए केंद्र पर एक कर्तव्य लगाता है कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलती है। यह वह कर्तव्य है जिसके प्रदर्शन में केंद्र राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य की सरकार को अपने हाथ में ले लेता है। इसे लोकप्रिय रूप से 'राष्ट्रपति शासन' के रूप में जाना जाता है। इसे 'राज्य आपातकाल' या 'संवैधानिक आपातकाल' के रूप में भी जाना जाता है।

अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को एक उद्घोषणा जारी करने का अधिकार देता है, यदि वह संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें किसी राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकती है। विशेष रूप से, राष्ट्रपति या तो राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट पर कार्य कर सकता है या अन्यथा भी (अर्थात राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना भी)।

राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तारीख से दो महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। तथापि, यदि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा ऐसे समय में जारी की जाती है जब लोक सभा भंग हो गई हो या लोक सभा का विघटन उद्घोषणा के अनुमोदन के बिना दो महीने की अवधि के दौरान हो, तो उद्घोषणा पहली बैठक से 30 दिनों तक बनी रहती है। लोकसभा की बैठक के पुनर्गठन के बाद भी, बशर्ते कि राज्य सभा ने इसे इस बीच में मंजूरी दे दी हो।

Q.50) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. राज्यों में राष्ट्रपति शासन का नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
2. राज्यों में राष्ट्रपति शासन हर छह महीने के लिए संसद की मंजूरी से अनिश्चित काल तक जारी रखा जा सकता है।
3. राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति या उनके द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य प्राधिकरण को सौंप सकती है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

a) केवल 1

b) केवल 1 और 2

c) केवल 3

d) 1, 2 और 3

Q. 50) Solution (a)

राज्यों में राष्ट्रपति शासन का नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जबकि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है।

राष्ट्रपति शासन के संचालन के लिए अधिकतम अवधि निर्धारित है, अर्थात तीन वर्ष। इसके बाद, इसे समाप्त किया जाना चाहिए और राज्य में सामान्य संवैधानिक तंत्र को बहाल किया जाना चाहिए। दूसरी ओर राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन के लिए कोई अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं है। इसे हर छह महीने में संसद की मंजूरी से अनिश्चित काल तक जारी रखा जा सकता है।

राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, संसद राज्य सूची में उल्लिखित विषयों पर केवल स्वयं ही कानून बना सकती है, अर्थात वह किसी अन्य निकाय या प्राधिकरण को उसे प्रत्यायोजित नहीं कर सकती है। दूसरी ओर राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति या उनके द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य प्राधिकरण को सौंप सकती है। अब तक यह प्रथा राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य से संसद सदस्यों के परामर्श से राज्य के लिए कानून बनाने की रही है। ऐसे कानूनों को राष्ट्रपति के कृत्यों के रूप में जाना जाता है।

Q. 51) निम्नलिखित में से किन विषयों को संसद ने 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया था?

1. सार्वजनिक स्वास्थ्य
2. कृषि
3. शिक्षा
4. वन

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 3 और 4
d) केवल 1 और 4

Q. 51) Solution (c)

संविधान केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों के त्रि-स्तरीय वितरण का प्रावधान करता है, अर्थात सातवीं अनुसूची में सूची- I (संघ सूची), सूची- II (राज्य सूची) और सूची- III (समवर्ती सूची)।

समवर्ती सूची में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में संसद और राज्य विधायिका दोनों कानून बना सकते हैं। इस सूची में वर्तमान में आपराधिक कानून और प्रक्रिया, नागरिक प्रक्रिया, विवाह और तलाक, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, बिजली, श्रम कल्याण, आर्थिक और सामाजिक नियोजन, ड्रग्स, समाचार पत्र, किताबें और प्रिंटिंग प्रेस जैसे 52 विषय (मूल रूप से 47 विषय) और अन्य हैं। 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम ने पांच विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया, अर्थात, (ए) शिक्षा, (बी) वन, (सी) वजन और माप, (डी) वन्य जीवों और पक्षियों की सुरक्षा, और (ई) न्याय का प्रशासन; सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को छोड़कर सभी न्यायालयों का गठन और संगठन।

Q. 52) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. राष्ट्रपति को राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों पर पूर्ण वीटो प्राप्त होता है जो राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित होते हैं।
2. व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयकों को राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किया जा सकता है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

a) केवल 1

b) केवल 2

c) दोनों 1 और 2

d) न तो 1 और न ही 2

Q. 52) Solution (c)

संविधान केंद्र को राज्य के विधायी मामलों पर निम्नलिखित तरीकों से नियंत्रण करने का अधिकार देता है:

- राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। राष्ट्रपति को उन पर पूर्ण वीटो प्राप्त होता है।
- राज्य सूची में उल्लिखित कुछ मामलों पर विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। (उदाहरण के लिए, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक)।
- केंद्र राज्यों को वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयकों और अन्य वित्तीय विधेयकों को आरक्षित करने का निर्देश दे सकता है।

Q. 53) केंद्र-राज्य संबंधों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. समवर्ती विषय पर एक कानून, हालांकि संसद द्वारा अधिनियमित किया जाता है, राज्यों द्वारा निष्पादित किया जाता है।
2. राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा उन्हें हटाया जाता है।
3. संसद केंद्र के कार्यकारी कार्यों को उक्त राज्य की सहमति के बिना किसी राज्य को सौंप सकती है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

a) केवल 1 और 2

b) केवल 2 और 3

c) केवल 3

d) केवल 1 और 3

Q. 53) Solution (d)

उन मामलों के संबंध में जिन पर संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों के पास कानून बनाने की शक्ति है (अर्थात, समवर्ती सूची में वर्णित विषय), जब तक संवैधानिक उपबंध या संसदीय विधि इसे केंद्र में विशिष्ट रूप से प्रदान नहीं कर देती, तब तक कार्यपालिका-शक्ति राज्यों के पास रहती है। इसलिए, समवर्ती विषय पर एक कानून, हालांकि संविधान या संसद द्वारा अन्यथा निर्देशित किए जाने के सिवाय, किसी समवर्ती विषय पर लागू विधि का निष्पादन राज्यों द्वारा किया जाना है।

यद्यपि भारत की राज्य व्यवस्था दोहरी है, लेकिन न्याय प्रशासन की कोई दोहरी व्यवस्था नहीं है। दूसरी ओर, संविधान ने एक एकीकृत न्यायिक प्रणाली की स्थापना की, जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे राज्य उच्च न्यायालय थे। अदालतों की यह एकल प्रणाली केंद्रीय कानूनों के साथ-साथ राज्य के कानूनों को भी लागू करती है। यह उपचारात्मक प्रक्रिया में विविधता को खत्म करने के लिए किया गया है। एक राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा स्थानांतरित और हटाया भी जा सकता है।

संविधान केंद्र के कार्यकारी कार्यों को उक्त राज्य की सहमति के बिना किसी राज्य को सौंपने का प्रावधान करता है। लेकिन, इस मामले में, संसद द्वारा निष्पादन होता है, न कि राष्ट्रपति द्वारा। इस प्रकार, संघ सूची के विषय पर संसद द्वारा बनाया गया कानून किसी राज्य को शक्तियां प्रदान कर सकता है और कर्तव्यों को लागू कर सकता है, या केंद्र द्वारा किसी राज्य को शक्तियां प्रदान करने और कर्तव्यों को लागू करने के लिए अधिकृत कर सकता है (संबंधित राज्य की सहमति के साथ या सहमति के बिना भी)। परंतु, राज्य विधायिका द्वारा समान कार्य नहीं किया जा सकता है।

Q. 54) निम्नलिखित में से कौन से कर राज्यों द्वारा लगाए, एकत्र और बनाए रखे जाते हैं?

1. कृषि आय पर कर।
2. बिजली के उपभोग या बिक्री पर कर
3. कुछ करों पर अधिभार

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

a) केवल 1 और 2

b) केवल 2 और 3

c) केवल 1 और 3

d) 1, 2 और 3

Q. 54) Solution (a)

18 कर हैं जो विशेष रूप से राज्यों से संबंधित हैं। उन्हें राज्य सूची में शामिल किया जाता है और राज्यों द्वारा लगाया जाता है, एकत्र किया जाता है और बनाए रखा जाता है। वो हैं:

1. भू राजस्व
2. कृषि आय पर कर
3. कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क
4. कृषि भूमि के संबंध में संपत्ति शुल्क
5. भूमि और भवनों पर कर
6. खनिज अधिकारों पर कर
7. मानव उपभोग के लिए मादक शराब पर उत्पाद शुल्क; अफीम, भारतीय भांग और अन्य नशीले पदार्थ और नशीले पदार्थ, लेकिन इसमें अल्कोहल या नशीले पदार्थों से युक्त औषधीय और प्रसाधन की चीज़ें शामिल नहीं है
8. बिजली की खपत या बिक्री पर कर
9. पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट (आमतौर पर पेट्रोल के रूप में जाना जाता है), प्राकृतिक गैस, विमानन टर्बाइन ईंधन और मानव उपभोग के लिए मादक शराब की बिक्री पर कर, लेकिन अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बिक्री या ऐसे माल के अंतरराष्ट्रीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बिक्री शामिल नहीं है
10. सड़क या अंतर्देशीय जलमार्ग द्वारा ले जाए जाने वाले माल और यात्रियों पर कर
11. वाहनों पर कर
12. जानवरों और नावों पर कर
13. टोल
14. व्यवसायों, व्यापारों, कॉलिंग और रोजगार पर कर
15. कैपिटेशन टैक्स (capitation taxes)
16. पंचायत या नगर पालिका या क्षेत्रीय परिषद या जिला परिषद द्वारा लगाए और एकत्र की गई सीमा तक मनोरंजन और मनोरंजन पर कर
17. दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क (संघ सूची में निर्दिष्ट को छोड़कर)
18. राज्य सूची में उल्लिखित मामलों पर शुल्क (अदालत शुल्क को छोड़कर)

संसद किसी भी समय अनुच्छेद 269 और 270 (ऊपर उल्लिखित) में निर्दिष्ट करों और शुल्कों पर अधिभार लगा सकती है। इस तरह के अधिभार की आय विशेष रूप से केंद्र के पास जाती है। दूसरे शब्दों में, इन अधिभारों में राज्यों का कोई हिस्सा नहीं होता है। हालांकि, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को इस अधिभार से छूट दी गई है। दूसरे शब्दों में, यह अधिभार GST पर नहीं लगाया जा सकता है।

Q. 55) अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह केंद्र सरकार को एक अंतर-राज्यीय नदी या नदी घाटी के पानी के संबंध में दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद के निर्णय के लिए एक तदर्थ न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है।
2. न्यायाधिकरण के निर्णय स्वभाव में अनुशंसात्मक होते हैं और विवाद के पक्षकारों पर बाध्यकारी नहीं हैं।
3. इस अधिनियम के तहत पीड़ित पक्ष न्यायाधिकरण के निर्देशों के खिलाफ सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

a) केवल 1
b) केवल 1 और 2
c) केवल 3
d) 1, 2 और 3

Q. 55) Solution (a)

संविधान का अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्यायनिर्णयन का प्रावधान करता है। यह दो प्रावधान करता है:

(i) संसद कानून द्वारा किसी भी अंतर्राज्यीय नदी और नदी घाटी के जल के उपयोग, वितरण और नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत के न्यायनिर्णयन का प्रावधान कर सकती है।

(ii) संसद यह भी प्रावधान कर सकती है कि इस तरह के किसी भी विवाद या शिकायत के संबंध में न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही कोई अन्य अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करे।

इस प्रावधान के तहत, संसद ने दो कानून बनाए हैं:

- नदी बोर्ड अधिनियम (1956)
- अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम (1956)

नदी बोर्ड अधिनियम अंतर्राज्यीय नदी और नदी घाटियों के नियमन और विकास के लिए नदी बोर्डों की स्थापना का प्रावधान करता है। संबंधित राज्य सरकारों के अनुरोध पर उन्हें सलाह देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक नदी बोर्ड की स्थापना की जाती है।

अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम केंद्र सरकार को एक अंतर-राज्यीय नदी या नदी घाटी के पानी के संबंध में दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद के निर्णय के लिए एक तदर्थ न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है। न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगा और विवाद के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा। किसी भी जल विवाद के संबंध में न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही किसी अन्य न्यायालय के पास अधिकार क्षेत्र है, जिसे इस अधिनियम के तहत ऐसे न्यायाधिकरण को संदर्भित किया जा सकता है।

Q. 56) अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरणों में शामिल राज्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है?

(अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण)	(शामिल राज्य))
1. महादयी जल विवाद न्यायाधिकरण	गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र
2. वंशधारा जल विवाद न्यायाधिकरण	तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश
3. महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण	ओडिशा और छत्तीसगढ़

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

a) केवल 1 और 2

b) केवल 1 और 3

c) केवल 2 और 3

d) 1, 2 और 3

Q. 56) Solution (b)

अब तक स्थापित अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण हैं:

Sl. No.	जल विवाद न्यायाधिकरण	स्थापित	शामिल राज्य
1.	कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण-I	1969	महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश
2.	गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण	1969	महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा
3.	नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण	1969	राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र
4.	रावी और ब्यास जल विवाद न्यायाधिकरण	1986	पंजाब, हरियाणा और राजस्थान
5.	कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण	1990	कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी
6.	कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण-II	2004	महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश
7.	वंशधारा जल विवाद न्यायाधिकरण	2010	ओडिशा और आंध्र प्रदेश
8.	महादयी जल विवाद न्यायाधिकरण	2010	गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र
9.	महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण	2018	उड़ीसा और छत्तीसगढ़

- 1969 में गठित कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण-I ने 1976 में अपना अंतिम निर्णय दिया।
- 1969 में गठित गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण ने 1979 में अपना अंतिम निर्णय दिया।
- 1990 में गठित कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण ने 2007 में अपना अंतिम निर्णय दिया।

- 1969 में बनाए गए नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण ने 1979 में अपना अंतिम निर्णय दिया।
- बाकी न्यायाधिकरण अभी भी सक्रिय हैं।

Q. 57) अंतरराज्यीय परिषद (Inter-State Council) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए::

1. अंतरराज्यीय परिषद का उद्देश्य राज्यों को यथासंभव शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना है।
2. यह एक अस्थाई संवैधानिक निकाय है।
3. इसके निर्णय प्रकृति में बाध्यकारी होते हैं।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

a) केवल 1
b) केवल 1 और 2
c) केवल 3
d) 1, 2 और 3

Q. 57) Solution (b)

संघीय मुद्दों से निपटने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 द्वारा प्रदान की गई अंतरराज्यीय परिषद (आईएससी) एक संवैधानिक निकाय है। इसका अधिदेश अंतरराज्यीय विवादों की जांच और सलाह देना और बेहतर नीति समन्वय के लिए सिफारिशें प्रदान करना है।

अंतरराज्यीय परिषद के उद्देश्य इस प्रकार हैं::

- यथासम्भव राज्यों को शक्तियों का विकेन्द्रीकरण।
- राज्यों को वित्तीय संसाधनों का अधिक हस्तांतरण।
- हस्तांतरण की व्यवस्था इस प्रकार की जाए कि राज्य अपने दायित्वों को पूरा कर सकें।
- राज्यों को दिए जाने वाले ऋणों का संबंध 'उत्पादक सिद्धांत' से होना चाहिए।
- राज्यों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती या तो उनके अनुरोध पर या भिन्न प्रकार से।

अंतरराज्यीय परिषद में निम्नलिखित सदस्य होते हैं:

- प्रधान मंत्री, अध्यक्ष।
- सभी राज्यों के मुख्यमंत्री।
- विधानसभाओं वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री।

- केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक जिनकी विधानसभाएं नहीं हैं।
- गृह मंत्री सहित 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों को प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाएगा।
- राज्यों के राज्यपालों को राष्ट्रपति शासन के अधीन प्रशासित किया जाता है
- स्थाई समिति
- गृह मंत्री, अध्यक्ष
- 5 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री
- 9 मुख्यमंत्री

अंतरराज्यीय परिषद केवल एक सलाहकार निकाय है जिसका केंद्र या राज्य पर कोई बंधन नहीं है। इस प्रकार, अक्सर केंद्र और राज्यों में सरकार द्वारा इसकी सिफारिशों की अनदेखी की जाती है।

Q. 58) क्षेत्रीय परिषदों (Zonal Councils) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ये संवैधानिक निकाय हैं।
2. इनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं।
3. महाराष्ट्र और गोवा राज्य पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा हैं।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

a) केवल 1

b) केवल 2 और 3

c) केवल 3

d) 1, 2 और 3

Q. 58) Solution (c)

क्षेत्रीय परिषदें सांविधिक (संवैधानिक नहीं) निकाय हैं। वे संसद के एक अधिनियम, यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा स्थापित किए गए हैं। इस अधिनियम ने देश को पांच क्षेत्रों (उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी) में विभाजित किया और प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद प्रदान की।

प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में निम्नलिखित सदस्य होते हैं: (ए) केंद्र सरकार के गृह मंत्री। (बी) क्षेत्र के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। (सी) क्षेत्र में प्रत्येक राज्य से दो अन्य मंत्री। (डी) क्षेत्र में प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक।

केंद्र सरकार के गृह मंत्री पांच क्षेत्रीय परिषदों के सामान्य अध्यक्ष होते हैं। प्रत्येक मुख्यमंत्री बारी-बारी से परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, एक समय में एक वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते है

गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा हैं।

Q. 59) केंद्र-राज्य संबंधों के संबंध में, निम्नलिखित पर विचार करें:

1. ट्रेड यूनियन
2. अंतर-राज्यीय व्यापार और वाणिज्य
3. बैंकिंग
4. श्रम कल्याण

उपरोक्त में से कौन-से संघ सूची के विषय हैं?

a) केवल 1 और 2

b) केवल 2 और 3

c) केवल 3 और 4

d) केवल 1 और 4

Q. 59) Solution (b)

संविधान केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों के त्रि-स्तरीय वितरण का प्रावधान करता है, अर्थात सातवीं अनुसूची में सूची- I (संघ सूची), सूची- II (राज्य सूची) और सूची- III (समवर्ती सूची)

संघ सूची में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद के पास विशेष शक्तियां हैं। इस सूची में वर्तमान में रक्षा, बैंकिंग, विदेशी मामलों, मुद्रा, परमाणु ऊर्जा, बीमा, डाक और तार, संचार, अंतर-राज्य व्यापार और वाणिज्य, जनगणना, लेखा परीक्षा आदि जैसे 98 विषय (मूल रूप से 971 विषय) हैं।

ट्रेड यूनियन और श्रम कल्याण समवर्ती सूची में शामिल विषय हैं। समवर्ती सूची में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं।

Q.60) जब दो या दो से अधिक राज्यों की विधायिकाएं राज्य सूची में किसी मामले पर कानून बनाने के लिए संसद से अनुरोध करने वाले प्रस्ताव पारित करती हैं, तो संसद उस मामले को विनियमित करने के लिए कानून बना सकती है। इस संदर्भ में उपर्युक्त प्रावधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन-सा/से कानून पारित किया गया है/हैं?

1. वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
2. जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
3. शहरी भूमि (सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

a) केवल 1 और 2

b) केवल 2 और 3

c) केवल 1 और 3

d) 1, 2 और 3

Q. 60) Solution (d)

जब दो या दो से अधिक राज्यों की विधायिकाएं राज्य सूची में किसी मामले पर कानून बनाने के लिए संसद से अनुरोध करने वाले प्रस्ताव पारित करती हैं, तो संसद उस मामले को विनियमित करने के लिए कानून बना सकती है। इस प्रकार अधिनियमित कानून केवल उन राज्यों पर लागू होता है जिन्होंने प्रस्ताव पारित किए हैं। हालाँकि, कोई भी अन्य राज्य अपनी विधायिका में इस आशय का प्रस्ताव पारित करके बाद में इसे अपना सकता है। इस तरह के कानून को केवल संसद द्वारा संशोधित या निरस्त किया जा सकता है, न कि संबंधित राज्यों के विधानमंडलों द्वारा।

उपरोक्त प्रावधान के तहत एक प्रस्ताव पारित करने का प्रभाव यह है कि संसद उस मामले के संबंध में कानून बनाने की हकदार हो जाती है जिसके लिए उसे कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं है। दूसरी ओर, राज्य विधायिका की उस मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति समाप्त हो जाती है। संकल्प उस मामले के संबंध में राज्य विधायिका की शक्ति के त्याग या समर्पण के रूप में कार्य करता है और इसे पूरी तरह से संसद के हाथों में रखा जाता है, जो अकेले ही इसके संबंध में कानून बना सकता है।

उपरोक्त प्रावधान के तहत पारित कानूनों के कुछ उदाहरण पुरस्कार प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 1955 ; वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972; जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974; शहरी भूमि (सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976; और मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 हैं।

Q. 61) राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में शामिल हैं:

1. संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य।
2. केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के सभी सदस्य।
3. राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य।

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

a) केवल 1

b) केवल 1 और 2

c) केवल 3

d) 1, 2 और 3

Q. 61) Solution (c)

संघ की कार्यकारिणी में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत के महान्यायवादी होते हैं।

राष्ट्रपति भारतीय राज्य का प्रमुख होता है। वह भारत के प्रथम नागरिक हैं और राष्ट्र की एकता, अखंडता और एकजुटता के प्रतीक के रूप में कार्य करते हैं।

राष्ट्रपति का चुनाव सीधे लोगों द्वारा नहीं बल्कि निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें शामिल हैं:

- संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य;
- राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य;
- केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।

इस प्रकार, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान सभाओं के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषदों के सदस्य (निर्वाचित और मनोनीत दोनों) (द्विसदनीय विधायिका के मामले में) तथा दिल्ली और पुडुचेरी की विधान सभाओं के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। जहां एक विधानसभा को भंग कर दिया जाता है, सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने के लिए अर्हता प्राप्त नहीं होती है, भले ही राष्ट्रपति चुनाव से पहले भंग विधानसभा के लिए नए चुनाव न हुए हों।

Q. 62) राष्ट्रपति के महाभियोग के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए::

1. महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरू की जा सकती है।
2. महाभियोग के आरोपों पर सदन के एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए
3. संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं।
4. राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेते हैं।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 4
d) केवल 1 और 4

Q. 62) Solution (a)

राष्ट्रपति को 'संविधान के उल्लंघन' के लिए महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है। हालाँकि, संविधान 'संविधान का उल्लंघन' वाक्यांश के अर्थ को परिभाषित नहीं करता है।

महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरू की जा सकती है। इन आरोपों पर सदन के एक चौथाई सदस्यों (जिन्होंने आरोप तय किए थे) द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिनों का नोटिस दिया जाना चाहिए। महाभियोग प्रस्ताव उस

सदन की कुल सदस्यता के दो-तिहाई बहुमत से पारित होने के बाद, इसे दूसरे सदन में भेजा जाता है, जिसे आरोपों की जांच करनी चाहिए। राष्ट्रपति को ऐसी जांच में उपस्थित होने और प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। यदि दूसरा सदन भी आरोपों को बरकरार रखता है और कुल सदस्यता के दो-तिहाई बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव पारित करता है, तो राष्ट्रपति को उस तिथि से अपने पद से हटा दिया जाता है जिस दिन प्रस्ताव पारित किया जाता है।

इस प्रकार, महाभियोग संसद में एक अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया है। इस संदर्भ में दो बातों का ध्यान रखना चाहिए:

- संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग ले सकते हैं, हालांकि वे उसके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं।
- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं, हालांकि वे उनके चुनाव में भाग लेते हैं।

अभी तक किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है।

Q. 63) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. राष्ट्रपति चुनाव आयोग के परामर्श से संसद के सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्नों पर निर्णय लेता है।
2. राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों को संसद द्वारा इसकी पुन: बैठक से छह महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए।
3. धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 1 और 3
c) केवल 2 और 3
d) 1, 2 और 3

Q. 63) Solution (b)

राष्ट्रपति भारत की संसद का एक अभिन्न अंग है, और निम्नलिखित विधायी शक्तियों का आनंद लेता है:

- वह चुनाव आयोग के परामर्श से संसद के सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्नों पर निर्णय लेता है।
- जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। इन अध्यादेशों को संसद द्वारा अपने पुन: संयोजन से छह सप्ताह के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। वह किसी भी समय अध्यादेश को वापस भी ले सकता है
- वह संसद को बुला सकता है या उसका सत्रावसान कर सकता है और लोकसभा को भंग कर सकता है। वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी बुला सकता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं।
- वह प्रत्येक आम चुनाव और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के बाद पहले सत्र के प्रारंभ में संसद को संबोधित कर सकता है।

- वह लोकसभा के किसी भी सदस्य को इसकी कार्यवाही की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त कर सकता है जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो जाते हैं।
- संसद में कुछ प्रकार के विधेयकों को पेश करने के लिए उनकी पूर्व सिफारिश या अनुमति की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, एक विधेयक जिसमें भारत की संचित निधि से व्यय शामिल है, या राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन या एक नए राज्य के निर्माण के लिए एक विधेयक।

राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां और कार्य हैं:

- उनकी पूर्व सिफारिश से ही धन विधेयक संसद में पेश किए जा सकते हैं।
- वह वार्षिक वित्तीय विवरण (यानी, केंद्रीय बजट) को संसद के समक्ष रखने को कहता है।
- उसकी सिफारिश के अलावा अनुदान की कोई मांग नहीं की जा सकती है।
- वह किसी भी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिक निधि से अग्रिम ले सकता है।
- वह केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण की सिफारिश करने के लिए हर पांच साल के बाद एक वित्त आयोग का गठन करता है।

Q. 64) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों के संबंध में राष्ट्रपति पूर्ण वीटो (absolute veto) का प्रयोग करता है।
2. जब राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए किसी विधेयक को लौटाता है तो वह निलंबनकारी वीटो (suspensive veto) का प्रयोग करता है।
3. राष्ट्रपति राज्य विधान के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकते हैं।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3

Q. 64) Solution (d)

संसद द्वारा पारित विधेयक तभी अधिनियम बन सकता है जब उसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो। जब ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो उसके पास तीन विकल्प होते हैं (संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत):

1. वह विधेयक पर अपनी सहमति दे सकता है, या
2. वह विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकता है, या

3. वह संसद के पुनर्विचार के लिए विधेयक (यदि यह धन विधेयक नहीं है) लौटा सकता है। हालाँकि, यदि विधेयक को संसद द्वारा संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के फिर से पारित किया जाता है और राष्ट्रपति को फिर से प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति को विधेयक पर अपनी सहमति देनी होगी।

इस प्रकार, राष्ट्रपति के पास संसद द्वारा पारित विधेयकों पर वीटो शक्ति होती है, अर्थात वह विधेयकों पर अपनी सहमति रोक सकता है।

राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित दो मामलों में पूर्ण वीटो का प्रयोग किया जाता है:

- गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों के संबंध में (अर्थात, संसद के किसी ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत विधेयक जो मंत्री नहीं है); तथा
- सरकारी विधेयकों के संबंध में जब मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है (बिलों के पारित होने के बाद लेकिन राष्ट्रपति द्वारा सहमति से पहले) और नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को ऐसे विधेयकों पर अपनी सहमति न देने की सलाह देता है।

जब राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए किसी विधेयक को लौटाता है तो वह निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करता है। हालाँकि, यदि विधेयक को संसद द्वारा संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के फिर से पारित किया जाता है और फिर से राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति के लिए विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य है।

जब राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्यपाल द्वारा एक विधेयक सुरक्षित रखा जाता है, तो राष्ट्रपति के पास तीन विकल्प होते हैं (संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत):

- वह विधेयक पर अपनी सहमति दे सकता है, या
- वह बिल पर अपनी सहमति रोक सकता है, या
- वह राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के पुनर्विचार के लिए विधेयक (यदि यह धन विधेयक नहीं है) वापस करने का निर्देश दे सकता है। यदि विधेयक को राज्य विधानमंडल द्वारा संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के फिर से पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति की सहमति के लिए फिर से प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। इसका मतलब यह है कि राज्य विधायिका राष्ट्रपति की वीटो शक्ति को समाप्त नहीं कर सकती है।

इसलिए, राष्ट्रपति राज्य विधान के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकते हैं।

Q. 65) उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में शामिल हैं:

1. संसद के निर्वाचित सदस्य।
2. राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

a) केवल 1

b) केवल 2

c) दोनों 1 और 2

d) न तो 1 और न ही 2

Q. 65) Solution (d)

उपराष्ट्रपति का देश में दूसरा सर्वोच्च पद होता है। उन्हें वरीयता के आधिकारिक अधिपत्र में राष्ट्रपति के बाद में एक रैंक दिया गया है। यह पद अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तर्ज पर डिजाइन किया गया है।

उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति की तरह, सीधे लोगों द्वारा नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष चुनाव की पद्धति से चुना जाता है। वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों वाले निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। इस प्रकार, यह निर्वाचक मंडल निम्नलिखित दो मामलों में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल से अलग है:

1. इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं (राष्ट्रपति के मामले में, केवल निर्वाचित सदस्य)।
2. इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं हैं (राष्ट्रपति के मामले में, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल हैं)।

दोनों ही मामलों में चुनाव का तरीका एक ही है। इस प्रकार, उपराष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव की तरह, एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होता है और मतदान गुप्त मतदान द्वारा होता है।

Q. 66) निम्नलिखित कथन पर विचार करें:

1. उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति पद तब ग्रहण करता है जब वह पद खाली हो जाता है और वह अपने पूर्ववर्ती की अपूर्ण अवधि तक के लिए राष्ट्रपति बना रहता है।
2. राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति राज्य सभा के सभापति के कार्यालय के कर्तव्यों का पालन नहीं करता है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

a) केवल 1

b) केवल 2

c) दोनों 1 और 2

d) न तो 1 और न ही 2

Q. 66) Solution (b)

हालांकि भारतीय उपराष्ट्रपति का कार्यालय अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है, लेकिन इसमें अंतर है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति पद ग्रहण करता है, और अपने पूर्ववर्ती की अपूर्ण अवधि तक के लिए राष्ट्रपति बना रहता है। दूसरी ओर, भारतीय उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का पद ग्रहण नहीं करता है, जब वह अपूर्ण अवधि के लिए रिक्त हो जाता है। वह केवल एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है जब तक कि नया राष्ट्रपति कार्यभार ग्रहण नहीं करता।

उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में तब कार्य करता है जब राष्ट्रपति के कार्यालय में उनके इस्तीफे, महाभियोग, मृत्यु या अन्यथा कारण रिक्ति होती है। वह केवल छह महीने की अधिकतम अवधि के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है जिसके भीतर एक नया राष्ट्रपति चुना जाना होता है।

राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हुए, उपराष्ट्रपति राज्य सभा के सभापति के कार्यालय के कर्तव्यों का पालन नहीं करता है। इस अवधि के दौरान, उन कर्तव्यों का पालन राज्यसभा के उपसभापति द्वारा किया जाता है।

Q. 67) किसी व्यक्ति को राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने के लिए संविधान द्वारा क्या योग्यताएं निर्धारित की गई हैं?

1. वह भारत का नागरिक होना चाहिए।
2. उसे 30 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए।
3. उसे विधान सभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए।

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

a) केवल 1

b) केवल 1 और 2

c) केवल 3

d) 1, 2 और 3

Q. 67) Solution (a)

राज्यपाल राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख होता है। लेकिन, राष्ट्रपति की तरह, वह नाममात्र का कार्यकारी प्रमुख (नाममात्र या संवैधानिक प्रमुख) होता है। राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। इसलिए, राज्यपाल के कार्यालय की दोहरी भूमिका होती है।

राज्यपाल न तो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है और न ही परोक्ष रूप से किसी विशेष रूप से गठित निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है जैसा कि राष्ट्रपति के मामले में होता है। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा उनके हाथ और मुहर के तहत अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जाता है। एक तरह से वह केंद्र सरकार के नामनिर्दिष्ट हैं।

राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए संविधान केवल दो योग्यताएं निर्धारित करता है। ये:

a) वह भारत का नागरिक होना चाहिए।

b) उसे 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, पिछले कुछ वर्षों में इस संबंध में दो कन्वेन्शन भी विकसित हुए हैं। सबसे पहले, वह एक बाहरी व्यक्ति होना चाहिए, यानी वह उस राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए जहां उसे नियुक्त किया गया है, ताकि वह स्थानीय राजनीति से मुक्त हो। दूसरा, राज्यपाल

की नियुक्ति करते समय, राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करने की आवश्यकता होती है, ताकि राज्य में संवैधानिक तंत्र का सुचारू संचालन सुनिश्चित हो सके। हालांकि, कुछ मामलों में दोनों परंपराओं का उल्लंघन किया गया है।

Q. 68) राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. वह राष्ट्रपति को किसी राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की सिफारिश कर सकता है।
2. महाधिवक्ता हालांकि राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, जिसे केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।
3. राज्य चुनाव आयुक्त राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है।
4. राज्य मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त पद धारण करती है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 3 और 4
d) केवल 1 और 4

Q. 68) Solution (d)

राज्यपाल के पास भारत के राष्ट्रपति के समान कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियां होती हैं। हालाँकि, उसके पास राष्ट्रपति की तरह कोई राजनयिक, सैन्य या आपातकालीन शक्तियाँ नहीं हैं।

राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँ और कार्य हैं:

1. किसी राज्य की सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से उसके नाम पर किए जाते हैं।
2. वह उस तरीके को निर्दिष्ट करते हुए नियम बना सकता है जिसमें उसके नाम पर किए गए और निष्पादित किए गए आदेश और अन्य साधन प्रमाणित किए जाएंगे।
3. वह किसी राज्य सरकार के व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक लेन-देन और उक्त व्यवसाय के मंत्रियों के बीच आवंटन के लिए नियम बना सकता है।
4. वह मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वे उसके प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं।
5. वह एक राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है और उसका पारिश्रमिक निर्धारित करता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त पद धारण करता है।
6. वह राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है और इसकी सेवा की शर्तों और कार्यालय के कार्यकाल को निर्धारित करता है। हालांकि, राज्य चुनाव आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान केवल उसी तरह और समान आधार पर हटाया जा सकता है।

7. वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। हालाँकि, उन्हें केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, राज्यपाल द्वारा नहीं।

8. वह मुख्यमंत्री से राज्य के मामलों के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकता है।

9. वह मुख्यमंत्री को किसी भी मामले पर मंत्रिपरिषद के विचार को प्रस्तुत करने की आवश्यकता कर सकता है, जिस पर एक मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया है लेकिन जिस पर परिषद द्वारा विचार नहीं किया गया है।

10. वह राष्ट्रपति को किसी राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की सिफारिश कर सकता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि के दौरान, राज्यपाल को राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में व्यापक कार्यकारी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं।

11. वह राज्य में विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में कार्य करता है। वह राज्य में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की भी नियुक्ति करता है।

Q. 69) राष्ट्रपति निम्नलिखित विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से राज्यसभा के बारह सदस्यों को नामित करता है:

1. साहित्य
2. विज्ञान
3. कला
4. सहकारी आंदोलन
5. समाज सेवा

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

a) केवल 1, 2, 3 और 4
b) केवल 1, 2, 3 और 5
c) केवल 2, 3 और 5
d) 1, 2, 3, 4 और 5

Q. 69) Solution: (b)

राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से नामित करता है, जबकि राज्यपाल राज्य विधान परिषद के सदस्यों में से एक-छठे सदस्यों को साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से नामित करता है।

Q.70) राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वह मृत्यु दंड को माफ कर सकता है, निलंबित कर सकता है, परिहार कर सकता है या लघुकरण कर सकता है।
2. वह कोर्ट-मार्शल द्वारा सजा या दंड के संबंध में क्षमा, दण्डविराम, विराम, निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकता है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

a) केवल 1

b) केवल 2

c) दोनों 1 और 2

d) न तो 1 और न ही 2

Q. 70) Solution (d)

राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां:

- वह राज्य के कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा या दंड के संबंध में क्षमा, दण्डविराम, विराम, निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकता है।
- वह मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता। यहां तक कि अगर राज्य के कानून में मृत्यु दंड का प्रावधान है, तो माफी देने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, न कि राज्यपाल के पास। लेकिन, राज्यपाल मृत्यु दंड को निलंबित, कम कर सकता है।
- उसके पास कोर्ट-मार्शल (सैन्य न्यायालय) द्वारा सजा या दंड के संबंध में क्षमा, दण्डविराम, विराम, निलंबन, परिहार या लघुकरण के संबंध में कोई शक्ति नहीं होती है। यह शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास होती है।

Q. 71) निम्नलिखित को ध्यान मे रखते हुए:

1. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
2. जैव प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Biotechnology)
3. राष्ट्रीय गंगा परिषद
4. राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL)
5. अंतरिक्ष विभाग

उपरोक्त में से किन संगठनों की अध्यक्षता प्रधान मंत्री द्वारा की जाती हैं?

a) केवल 1 और 3

b) केवल 2, 3 और 4

c) केवल 1, 3, 4 और 5

d) 1, 2, 3, 4 और 5

Q. 71) Solution (c)

भारत के प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय है। एनडीएमए की स्थापना और राज्य और जिला स्तर पर संस्थागत तंत्र के लिए एक सक्षम वातावरण का निर्माण आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 द्वारा अनिवार्य है।

राष्ट्रीय गंगा परिषद का गठन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम (EPA), 1986 के तहत किया गया है। इसे गंगा और उसकी सहायक नदियों सहित गंगा बेसिन के प्रदूषण की रोकथाम और कायाकल्प के पर्यवेक्षण के लिए समग्र जिम्मेदारी दी गई है।इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं।

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन 2002 में वन्यजीव अधिनियम के संशोधन के माध्यम से किया गया था। यह एक 47 सदस्यीय समिति है, जिसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री (पर्यावरण मंत्री) उपाध्यक्ष के रूप में करते हैं।

अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में तत्कालीन भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। यह भारतीय अंतरिक्ष आयोग की नीतिगत सिफारिशों पर कार्य करता है और मोटे तौर पर भारत की अंतरिक्ष गतिविधियों के दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। एक सचिव की अध्यक्षता में, जो इसरो का नेतृत्व भी करता है, विभाग प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) के सीधे दायरे में आता है। परंपरागत रूप से इस विभाग के लिए उत्तरदायी मंत्री हमेशा प्रधान मंत्री होता है।यह विभाग कैबिनेट में किसी और को नहीं बल्कि स्वयं प्रधानमंत्री को आवंटित किया जाता है।

जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) भारत में आधुनिक जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास और व्यावसायीकरण के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। इस विभाग के लिए उत्तरदायी मंत्री केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं।

Q. 72) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हालाँकि संवैधानिक रूप से, प्रधान मंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य हो सकता है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद से भारत के सभी प्रधान मंत्री केवल लोकसभा के सदस्य रहे हैं।
2. एक व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे छह महीने के लिए प्रधान मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
3. प्रधान मंत्री के चयन और नियुक्ति में राष्ट्रपति कभी भी अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग नहीं कर सकते हैं; उन्हें सबसे बड़ी पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करना होता है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

a) केवल 1 और 2

b) केवल 2

c) केवल 3

d) 1, 2 और 3

Q. 72) Solution (b)

संवैधानिक रूप से, प्रधान मंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य हो सकता है। उदाहरण के लिए, तीन प्रधान मंत्री, इंदिरा गांधी (1966), देवेगौड़ा (1996) और मनमोहन सिंह (2004) राज्यसभा के सदस्य थे।

एक व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे छह महीने के लिए प्रधान मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, जिसके भीतर उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना चाहिए; अन्यथा, वह प्रधान मंत्री के पद पर नहीं रहेगा।

सरकार की संसदीय प्रणाली की परंपराओं के अनुसार, राष्ट्रपति को लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधान मंत्री के रूप में नियुक्त करना होता है। लेकिन, जब लोकसभा में किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं होता है, तब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति में अपने व्यक्तिगत विवेक का प्रयोग कर सकता है। ऐसी स्थिति में, राष्ट्रपति आमतौर पर लोकसभा में सबसे बड़े दल या गठबंधन के नेता को प्रधान मंत्री के रूप में नियुक्त करता है और उसे एक महीने के भीतर सदन में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहता है। राष्ट्रपति द्वारा इस विवेक का प्रयोग 1979 में पहली बार किया गया था, जब नीलम संजीव रेड्डी (तत्कालीन राष्ट्रपति) ने मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार के पतन के बाद चरण सिंह (गठबंधन नेता) को प्रधान मंत्री नियुक्त किया था।

एक और स्थिति यह भी है कि राष्ट्रपति को प्रधान मंत्री के चयन और नियुक्ति में अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करना पड़ सकता है, अर्थात, जब प्रधान मंत्री की अचानक मृत्यु हो जाती है और कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं होता है। ऐसा ही तब हुआ जब 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। तत्कालीन राष्ट्रपति जैल सिंह ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त करने की मिसाल को नजरअंदाज करते हुए राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। बाद में कांग्रेस संसदीय दल ने सर्वसम्मति से उन्हें अपना नेता चुना। हालाँकि, यदि, एक मौजूदा प्रधान मंत्री की मृत्यु पर, सत्ताधारी दल एक नए नेता का चुनाव करता है, तो राष्ट्रपति के पास उसे प्रधान मंत्री के रूप में नियुक्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है।

Q. 73) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
2. मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है।
3. संसद के किसी भी सदन का सदस्य जो दलबदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया जाता है, वह मंत्री के रूप में भी नियुक्त होने के लिए अयोग्य होगा।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

a) केवल 1 और 2

b) केवल 2

c) केवल 3

d) 1, 2 और 3

Q. 73) Solution (c)

सरकार की संसदीय प्रणाली के सिद्धांत संविधान में विस्तृत नहीं हैं, लेकिन दो अनुच्छेद (74 और 75) उनके साथ व्यापक, संक्षिप्त और सामान्य तरीके से निपटते हैं। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद की स्थिति से संबंधित है जबकि अनुच्छेद 75 मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारी, योग्यता, शपथ और वेतन और भत्ते से संबंधित है।

मंत्रिपरिषद में प्रधान मंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्य की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह प्रावधान 2003 के 91वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था।

सरकार की संसदीय प्रणाली के कामकाज का मूल सिद्धांत सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। अनुच्छेद 75 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका अर्थ यह है कि सभी मंत्री लोक सभा के प्रति संयुक्त उत्तरदायित्व रखते हैं। वे एक टीम के रूप में काम करते हैं और एक साथ तैरते या डूबते हैं। जब लोकसभा मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है, तो सभी मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ता है, जिसमें वे मंत्री भी शामिल हैं जो राज्यसभा से हैं।

किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित संसद के किसी भी सदन के सदस्य को दलबदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया जाता है, वह मंत्री के रूप में भी नियुक्त होने के लिए अयोग्य होगा। यह प्रावधान 2003 के 91वें संशोधन अधिनियम द्वारा भी जोड़ा गया था।

Q. 74) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. मंत्रिमंडल संसद के निचले सदन में मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व को लागू करता है।
2. मंत्रिपरिषद एक छोटा निकाय है जिसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं जबकि कैबिनेट एक व्यापक निकाय होता है जिसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं।
3. मंत्रिपरिषद, एक निकाय के रूप में, अक्सर और आमतौर पर सप्ताह में एक बार बैठक करती है ताकि सरकारी कामकाज के लेन-देन के संबंध में विचार-विमर्श किया जा सके और निर्णय लिया जा सके।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

a) केवल 1
b) केवल 1 और 2
c) केवल 3
d) केवल 2 और 3

Q. 74) Solution (a)

'मंत्रिपरिषद' और 'कैबिनेट' शब्दों का प्रयोग अक्सर एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है, हालांकि उनके बीच एक निश्चित अंतर है। वे संरचना, कार्य और भूमिका के मामले में एक दूसरे से भिन्न होते हैं।

S.No.	मंत्रिपरिषद	मंत्रिमंडल
1.	यह एक व्यापक निकाय है जिसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं।	यह एक छोटा निकाय है जिसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं।
2.	इसमें मंत्रियों की सभी तीन श्रेणियां शामिल हैं, यानी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, और उप मंत्री होते है।	इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल हैं। इस प्रकार, यह मंत्रिपरिषद का एक हिस्सा है।

3.	यह एक निकाय के रूप में सरकारी कामकाज के लिए बैठक नहीं करता है। इसका कोई सामूहिक कार्य नहीं है	यह एक निकाय के रूप में, अक्सर और आमतौर पर सप्ताह में एक बार सरकारी व्यवसाय के लेन-देन के संबंध में विचार-विमर्श करने और निर्णय लेने के लिए मिलते है। इस प्रकार, इसके सामूहिक कार्य हैं।
4.	यह सभी शक्तियों के साथ निहित है लेकिन सिद्धांत रूप में	यह, व्यवहार में, मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग करता है।
5.	इसके कार्य कैबिनेट द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।	यह सभी मंत्रियों के लिए बाध्यकारी नीतिगत निर्णय लेकर मंत्रिपरिषद को निर्देश देता है।
6.	यह कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करता है।	यह मंत्रिपरिषद द्वारा अपने निर्णय के कार्यान्वयन की निगरानी करता है
7.	यह एक संवैधानिक निकाय है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 द्वारा विस्तार से पेश किया गया है। हालाँकि, इसके आकार और वर्गीकरण का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। इसका आकार प्रधान मंत्री द्वारा समय की आवश्यकताओं और स्थिति की आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित किया जाता है। त्रि-स्तरीय निकाय में इसका वर्गीकरण ब्रिटेन में विकसित संसदीय सरकार की कन्वेन्शनों पर आधारित है।हालांकि, इसे विधायी मंजूरी मिल गई है।	इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1978 में संविधान के अनुच्छेद 352 में सम्मिलित किया गया था। इस प्रकार, इसे संविधान के मूल पाठ में स्थान नहीं मिला। अब भी, अनुच्छेद 352 केवल कैबिनेट को यह कहते हुए परिभाषित करता है कि यह 'प्रधान मंत्री और अनुच्छेद 75 के तहत नियुक्त कैबिनेट रैंक के अन्य मंत्रियों से मिलकर बनी परिषद' है और इसकी शक्तियों और कार्यों का वर्णन नहीं करता है। दूसरे शब्दों में, हमारी राजनीतिक-प्रशासनिक व्यवस्था में इसकी भूमिका ब्रिटेन में विकसित संसदीय सरकार की परिपाटी पर आधारित है।
8.	यह संसद के निचले सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है।	यह संसद के निचले सदन में मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व को लागू करता है।

Q. 75) कैबिनेट समितियों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वे अतिरिक्त-संवैधानिक निकाय हैं।
2. विशेष समस्याओं से निपटने के लिए समय-समय पर तदर्थ समितियों का गठन किया जाता है।
3. प्रधानमंत्री सभी कैबिनेट समितियों का पदेन प्रमुख (Ex-officio head) होता है

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

a) केवल 1 और 2

b) केवल 2

c) केवल 3

d) 1, 2 और 3

Q. 75) Solution (a)

कैबिनेट समितियों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

1. वे उद्भव में अतिरिक्त-संवैधानिक हैं। दूसरे शब्दों में, उनका संविधान में उल्लेख नहीं है। हालांकि, व्यापार के नियमों में उनकी स्थापना का प्रावधान है।
2. वे दो प्रकार के होते हैं-स्थायी और तदर्थ। पूर्व स्थायी प्रकृति के हैं जबकि बाद वाले अस्थायी प्रकृति के हैं। विशेष समस्याओं से निपटने के लिए समय-समय पर तदर्थ समितियों का गठन किया जाता है। काम पूरा होने के बाद उन्हें भंग कर दिया जाता है।
3. वे समय की आवश्यकताओं और स्थिति की आवश्यकताओं के अनुसार प्रधान मंत्री द्वारा स्थापित किए जाते हैं। इसलिए, उनकी संख्या, नामकरण और संरचना समय-समय पर बदलती रहती है।
4. वे ज्यादातर प्रधान मंत्री के नेतृत्व में होती हैं। कभी-कभी अन्य कैबिनेट मंत्री, विशेष रूप से गृह मंत्री या वित्त मंत्री भी उनके अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन, यदि प्रधान मंत्री किसी समिति का सदस्य होता है, तो वह हमेशा इसकी अध्यक्षता करता है।
5. उनकी सदस्यता तीन से आठ तक होती है। इनमें आमतौर पर केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। हालाँकि, गैर-कैबिनेट मंत्रियों को उनकी सदस्यता से वंचित नहीं किया जाता है।
6. इनमें न केवल उनके द्वारा कवर किए गए विषयों के प्रभारी मंत्री शामिल हैं बल्कि अन्य वरिष्ठ मंत्री भी शामिल होते हैं।
7. वे न केवल मुद्दों को सुलझाते हैं और कैबिनेट के विचार के लिए प्रस्ताव तैयार करते हैं, बल्कि निर्णय भी लेते हैं।हालांकि कैबिनेट उनके फैसलों की समीक्षा कर सकती है।
8. वे मंत्रिमंडल के भारी कार्यभार को कम करने के लिए एक संगठनात्मक उपकरण हैं। वे नीतिगत मुद्दों की गहन जांच और प्रभावी समन्वय की सुविधा भी प्रदान करते हैं। वे श्रम विभाजन और प्रभावी प्रतिनिधिमंडल के सिद्धांतों पर आधारित हैं।

Q. 76) निम्नलिखित में से कौन सी समिति प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में होती है?

1. राजनीतिक मामलों की समिति
2. आर्थिक मामलों की समिति
3. नियुक्ति समिति
4. संसदीय कार्य समिति

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

a) केवल 2 और 4
b) केवल 2, 3 और 4
c) केवल 1 और 3

d) केवल 1, 2 और 3

Q. 76) Solution (d)

महत्वपूर्ण समितियां हैं:

1. राजनीतिक मामलों की समिति घरेलू और विदेशी मामलों से संबंधित सभी नीतिगत मामलों को देखती है।
2. आर्थिक मामलों की समिति आर्थिक क्षेत्र में सरकारी गतिविधियों का निर्देशन और समन्वय करती है।
3. नियुक्ति समिति केंद्रीय सचिवालय, सार्वजनिक उद्यमों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों में सभी उच्च स्तरीय नियुक्तियों का फैसला करती है।
4. संसदीय कार्य समिति संसद में सरकारी कार्य की प्रगति को देखती है।

पहली तीन समितियों की अध्यक्षता प्रधान मंत्री करते हैं और अंतिम की गृह मंत्री द्वारा की जाती है। सभी कैबिनेट समितियों में, सबसे शक्तिशाली राजनीतिक मामलों की समिति है, जिसे अक्सर "सुपर-कैबिनेट" के रूप में वर्णित किया जाता है।

Q. 77) मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से किसके सदस्य होते हैं:

1. नीति आयोग
2. आंचलिक परिषद (Zonal Council)
3. राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद
4. अंतर्राज्यीय परिषद

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

a) केवल 1, 2 और 3

b) केवल 1, 2 और 4

c) केवल 3 और 4

d) 1, 2, 3 और 4

Q. 77) Solution (b)

मुख्यमंत्री बारी-बारी से संबंधित आंचलिक परिषद (Zonal Council) के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, एक समय में एक वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है।

मुख्यमंत्री अंतर-राज्य परिषद और नीति आयोग की शासी परिषद के सदस्य होते हैं, दोनों प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में हैं।

"कौशल विकास के लिए समन्वित कार्रवाई और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की स्थापना" पर 15 मई 2008 को हुई बैठक में कैबिनेट के निर्णय के अनुसरण में प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद का गठन 1 जुलाई 2008 को किया गया था। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं।

परिषद के सदस्य हैं:

- मानव संसाधन विकास मंत्री
- वित्त मंत्री
- भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री
- ग्रामीण विकास मंत्री
- आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री
- श्रम और रोजगार मंत्री
- उपाध्यक्ष, योजना आयोग
- अध्यक्ष, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद
- राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के अध्यक्ष

Q. 78) राज्य मंत्रिपरिषद के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए।
2. बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा राज्यों में आदिवासी कल्याण के प्रभारी मंत्री की नियुक्ति एक संवैधानिक आवश्यकता है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 78) Solution (a)

किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधान सभा सदस्यों की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन, एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी।यह प्रावधान 2003 के 91वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था।

छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा राज्यों में आदिवासी कल्याण के प्रभारी मंत्री की नियुक्ति एक संवैधानिक आवश्यकता है जो अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण या किसी अन्य कार्य के अतिरिक्त प्रभारी हो सकते हैं। 2006 के 94वें संशोधन अधिनियम द्वारा बिहार राज्य को इस प्रावधान से बाहर रखा गया था।

Q. 79) निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है/हैं?

S. No.	अनुच्छेद	संबंधित प्रावधान
1	अनुच्छेद 75	राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद
2	अनुच्छेद 78	राष्ट्रपति को सूचना देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य
3	अनुच्छेद 88	सदनों के संबंध में मंत्रियों के अधिकार

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3

Q. 79) Solution (b)

अनुच्छेद 74: राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधान मंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद होगी, जो अपने कार्यों के प्रवर्तन में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा।

अनुच्छेद 75:

- प्रधान मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधान मंत्री की सलाह पर की जाएगी;
- राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत मंत्री पद धारण करेंगे; तथा
- मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होगी।

अनुच्छेद 78: प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा:

- राष्ट्रपति को संघ के मामलों के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों से अवगत कराना;
- संघ के मामलों के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए, जो राष्ट्रपति मांगे; तथा
- यदि राष्ट्रपति को आवश्यकता हो, तो किसी भी मामले को मंत्रिपरिषद के विचार के लिए प्रस्तुत करना, जिस पर एक मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया हो, लेकिन जिस पर परिषद द्वारा विचार नहीं किया गया हो।

अनुच्छेद 88: भारत के प्रत्येक मंत्री और महान्यायवादी को किसी भी सदन, सदनों की किसी भी संयुक्त बैठक और संसद की किसी भी समिति, जिसमें वह हो सकता है, की कार्यवाही में बोलने और अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा। लेकिन इस अनुच्छेद के आधार पर मत देने का हकदार नहीं होगा।

Q.80) राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच संबंधों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. अनुच्छेद 163: राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद होगी
2. अनुच्छेद 164 : मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेंगे।
3. अनुच्छेद 167: मंत्रिपरिषद राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

a) केवल 1

b) केवल 1 और 2

c) केवल 3

d) केवल 2 और 3

Q. 80) Solution (b)

संविधान के निम्नलिखित प्रावधान राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच संबंधों से संबंधित हैं:

1. अनुच्छेद 163:

राज्यपाल को अपने कार्यों के अभ्यास में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद होगी, सिवाय इसके कि जहां तक उसे अपने कार्यों या उनमें से किसी को अपने विवेक से करने की आवश्यकता हो।

2. अनुच्छेद 164:

a. मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी;
b. राज्यपाल के प्रसादपर्यंत मंत्री पद धारण करेंगे; तथा
c. मंत्रिपरिषद राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।

3. अनुच्छेद 167: मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा:

a. राज्य के मामलों के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को राज्य के राज्यपाल को सूचित करना;
b. राज्य के मामलों के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए जो राज्यपाल मांगे; तथा
c. यदि राज्यपाल को आवश्यकता हो, तो किसी भी मामले को मंत्रिपरिषद के विचार के लिए प्रस्तुत करना, जिस पर एक मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया हो, लेकिन जिस पर परिषद द्वारा विचार नहीं किया गया हो।

Q. 81) निम्नलिखित में से कौन-सा/से कारक हैं जो भारतीय संसद की संप्रभुता को सीमित करते हैं?

1. मौलिक अधिकार
2. सरकार की संघीय व्यवस्था
3. लिखित संविधान

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

a) केवल 1

b) केवल 1 और 2

c) केवल 3

d) 1, 2 और 3

Q. 81) Solution (d)

'संसद की संप्रभुता' का सिद्धांत ब्रिटिश संसद से जुड़ा है। संप्रभुता का अर्थ राज्य के भीतर सर्वोच्च शक्ति है। ग्रेट ब्रिटेन में वह सर्वोच्च शक्ति संसद के पास है। इसके प्राधिकार और अधिकार क्षेत्र पर कोई 'कानूनी' प्रतिबंध नहीं हैं।

भारतीय संसद को इस अर्थ में एक संप्रभु निकाय नहीं माना जा सकता है क्योंकि इसके प्राधिकार और अधिकार क्षेत्र पर 'कानूनी' प्रतिबंध हैं। भारतीय संसद की संप्रभुता को सीमित करने वाले कारक हैं:

- मौलिक अधिकार: संविधान के भाग 3 के तहत न्यायालयों योग्य मूल अधिकारों की संहिता को शामिल करके संसद के प्राधिकार को भी प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद 13 राज्य को ऐसा कानून बनाने से रोकता है जो या तो पूरी तरह से छीन लेता है या आंशिक रूप से मौलिक अधिकार को समाप्त कर देता है। इसलिए, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला संसदीय कानून शून्य होगा।
- सरकार की संघीय प्रणाली: भारत में सरकार की एक संघीय प्रणाली है जिसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का संवैधानिक विभाजन है। दोनों को आवंटित क्षेत्रों के भीतर काम करना है। इसलिए, संसद का कानून बनाने का अधिकार संघ सूची और समवर्ती सूची में शामिल विषयों तक ही सीमित हो जाता है और राज्य सूची में शामिल विषयों तक इसका विस्तार नहीं होता है।
- संविधान की लिखित प्रकृति: संविधान हमारे देश में भूमि का मौलिक कानून है। इसने केंद्र सरकार के तीनों अंगों के अधिकार और अधिकार क्षेत्र और उनके बीच अंतर्संबंध की प्रकृति को परिभाषित किया है। इसलिए, संसद को संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर काम करना है। विधायी प्राधिकरण और संसद के घटक प्राधिकरण के बीच कानूनी अंतर भी है। इसके अलावा, संविधान में कुछ संशोधनों को लागू करने के लिए, आधे राज्यों के अनुसमर्थन की भी आवश्यकता है।

Q. 82) संसदीय विशेषाधिकारों (parliamentary privileges) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संसद के सत्र के दौरान किसी भी दीवानी या फौजदारी मामले में संसद सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।

2. कोई भी संसद सदस्य संसद या उसकी समितियों में उसके द्वारा कही गई किसी बात या उसके द्वारा दिए गए किसी भी वोट के लिए किसी भी अदालत में किसी भी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं है।

3. जब संसद सत्र चल रहा हो तो संसद सदस्य अदालत में लंबित मामले में साक्ष्य देने से और गवाह के रूप में पेश होने से इनकार कर सकता है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

a) केवल 1 और 2

b) केवल 2 और 3

c) केवल 1 और 3

d) 1, 2 और 3

Q. 82) Solution (b)

संसदीय विशेषाधिकार संसद के दोनों सदनों, उनकी समितियों और उनके सदस्यों द्वारा प्राप्त विशेष अधिकार, उन्मुक्तियां और छूट हैं। यह उन्हें अपने कार्यों की स्वतंत्रता और प्रभावशीलता को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक हैं।

इन विशेषाधिकारों के बिना, सदन न तो अपने अधिकार, गरिमा और सम्मान को बनाए रख सकते हैं और न ही अपने सदस्यों को उनकी संसदीय जिम्मेदारियों के निर्वहन में किसी भी बाधा से बचा सकते हैं।

संसदीय विशेषाधिकारों को दो व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- जो संसद के प्रत्येक सदन द्वारा सामूहिक रूप से आनंद लिया जाता है, और
- जिनका सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से लाभ उठाया जाता है

सामूहिक रूप से संसद के प्रत्येक सदन से संबंधित विशेषाधिकार हैं:

1. इसे अपनी रिपोर्ट, वाद-विवाद और कार्यवाहियों को प्रकाशित करने का अधिकार है और दूसरों को इसे प्रकाशित करने से रोकने का भी अधिकार है।

2. यह बाहरी व्यक्तियों को अपनी कार्यवाही से बाहर कर सकता है और कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए गुप्त बैठकें कर सकता है।

3. यह अपनी प्रक्रिया और अपने व्यवसाय के संचालन को विनियमित करने और ऐसे मामलों पर निर्णय लेने के लिए नियम बना सकता है।

4. यह सदस्यों के साथ-साथ बाहरी लोगों को अपने विशेषाधिकारों के उल्लंघन के लिए या उसकी अवमानना के लिए फटकार, चेतावनी या कारावास (सदस्यों के मामले में निलंबन या निष्कासन) द्वारा दंडित कर सकता है।

5. इसे किसी सदस्य की गिरफ्तारी, नजरबंदी, दोषसिद्धि, कारावास और रिहाई की तत्काल सूचना प्राप्त करने का अधिकार है।

6. यह पूछताछ कर सकता है और गवाहों की उपस्थिति का आदेश दे सकता है और प्रासंगिक कागजात और रिकॉर्ड भेज सकता है।

7. न्यायालयों को किसी सदन या उसकी समितियों की कार्यवाही की जांच करने की मनाही है।

8. पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति (या तो सदस्य या बाहरी व्यक्ति) को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, और सदन के परिसर के भीतर कोई कानूनी प्रक्रिया (सिविल या आपराधिक) नहीं की जा सकती है।

व्यक्तिगत रूप से सदस्यों से संबंधित विशेषाधिकार हैं:

1. उन्हें संसद के सत्र के दौरान और सत्र शुरू होने से 40 दिन पहले और सत्र की समाप्ति के 40 दिन बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। यह विशेषाधिकार केवल दीवानी मामलों में उपलब्ध है, न कि आपराधिक मामलों या निवारक निरोध के मामलों में।

2. उन्हें संसद में बोलने की आजादी है। कोई भी सदस्य संसद या उसकी समितियों में उसके द्वारा कही गई किसी बात या उसके द्वारा दिए गए वोट के लिए किसी भी अदालत में किसी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं है। यह स्वतंत्रता संविधान के प्रावधानों और संसद की प्रक्रिया को विनियमित करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन है।

3. उन्हें जूरी सेवा से छूट दी गई है। जब संसद सत्र चल रहा हो तो संसद सदस्य अदालत में लंबित मामले में साक्ष्य देने से और गवाह के रूप में पेश होने से इनकार कर सकता है।

Q. 83) निम्नलिखित में से कौन-सी शक्तियाँ केवल राज्य सभा को प्राप्त हैं?

1. यह संसद को राज्य सूची में उल्लिखित विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकता है।
2. यह अकेले ही राष्ट्रपति को हटाने की पहल कर सकता है।
3. यह सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के विस्तार के संबंध में एकमात्र प्राधिकरण है।

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

a) केवल 1
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3

Q. 83) Solution (a)

राज्य सभा को चार विशिष्ट या विशेष शक्तियाँ दी गई हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं हैं:

1. यह संसद को राज्य सूची (अनुच्छेद 249) में सूचीबद्ध विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकता है।

2. यह संसद को केंद्र और राज्यों दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने के लिए अधिकृत कर सकता है (अनुच्छेद 312)।

3. यह अकेले ही उप-राष्ट्रपति को हटाने का फैसला ले सकता है। दूसरे शब्दों में, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, न कि लोकसभा में (अनुच्छेद 67)।

4. यदि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन या वित्तीय आपातकाल लागू करने की घोषणा ऐसे समय में की जाती है जब लोकसभा भंग हो गई हो या लोकसभा का विघटन उसके अनुमोदन के लिए अनुमत अवधि के भीतर हो, तो उद्घोषणा अकेले राज्य सभा द्वारा अनुमोदित होने पर भी प्रभावी रह सकता है (अनुच्छेद 352, 356 और 360)।

हमारी संवैधानिक व्यवस्था में राज्य सभा की स्थिति उतनी कमजोर नहीं है जितनी कि ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था में हाउस ऑफ लॉर्ड्स की या अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था में सीनेट की स्थिति जितनी मजबूत है। वित्तीय मामलों और मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण को छोड़कर, अन्य सभी क्षेत्रों में राज्य सभा की शक्तियाँ और स्थिति मोटे तौर पर समान हैं और लोकसभा के साथ समन्वय करती हैं।

Q. 84) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भविष्य निधि जमा, बचत बैंक जमा और सरकार द्वारा ट्रेजरी बिल जारी करके एकत्रित किए गए ऋण को भारत की संचित निधि में रखा जाता है।
2. भारत के लोक लेखा (Public Account) से भुगतान संसदीय विनियोग के बिना किए जा सकते हैं।
3. भारत सरकार की ओर से सभी कानूनी रूप से अधिकृत भुगतान भारत की आकस्मिकता निधि से किए जाते हैं।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2
c) केवल 3
d) केवल 2 और 3

Q. 84) Solution (b)

भारत का संविधान केंद्र सरकार के लिए निम्नलिखित तीन प्रकार की निधियों का प्रावधान करता है:

1. भारत की संचित निधि (अनुच्छेद 266)
2. भारत का लोक लेखा (अनुच्छेद 266)
3. भारत की आकस्मिकता निधि (अनुच्छेद 267)

भारत की संचित/ समेकित निधि:

यह एक ऐसा कोष है जिसमें सभी प्राप्तियों को जमा किया जाता है और सभी भुगतानों को डेबिट किया जाता है। दूसरे शब्दों में:

- भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व;

- सरकार द्वारा ट्रेजरी बिल, ऋण या अर्थोपाय अग्रिम और साधन जारी करके एकत्रित किए गए सभी ऋण;
- ऋणों के पुनर्भुगतान में सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन भारत की संचित निधि का निर्माण करते हैं।

भारत सरकार की ओर से सभी कानूनी रूप से अधिकृत भुगतान इस फंड से किए जाते हैं। इस निधि में से कोई भी धन संसदीय कानून के बिना विनियोजित (जारी या आहरित) नहीं किया जा सकता है।

भारत का सार्वजनिक खाता:

- भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त अन्य सभी सार्वजनिक धन (उनके अलावा जो भारत की संचित निधि में जमा किए गए हैं) को भारत के लोक खाते में जमा किया जाएगा।
- इसमें भविष्य निधि जमा, न्यायिक जमा, बचत बैंक जमा, विभागीय जमा, प्रेषण (remittances) आदि शामिल हैं।
- यह खाता कार्यकारी कार्रवाई द्वारा संचालित होता है, अर्थात इस खाते से भुगतान संसदीय विनियोग के बिना किया जा सकता है। इस तरह के भुगतान ज्यादातर बैंकिंग लेनदेन की प्रकृति में होते हैं।

भारत की आकस्मिकता निधि:

- संविधान ने संसद को 'भारत की आकस्मिकता निधि' स्थापित करने के लिए अधिकृत किया, जिसमें समय-समय पर कानून द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान किया जाता है।तद्नुसार, संसद ने 1950 में भारतीय आकस्मिकता निधि अधिनियम बनाया।
- यह कोष राष्ट्रपति के पास रखा जाता है और वह संसद द्वारा इसकी अनुमति मिलने तक अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए इसमें से अग्रिम राशि जमा कर सकता है।
- यह कोष राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव के पास होता है। भारत के सार्वजनिक खाते की तरह, यह भी कार्यकारी कार्रवाई द्वारा संचालित होता है।

Q. 85) अप्रत्याशित परिस्थितियों को पूरा करने के लिए संसद द्वारा दिए गए विभिन्न अनुदानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. अतिरिक्त अनुदान (Additional Grant) तब दिया जाता है जब सेवा के परिमाण या अनिश्चित स्वरूप के कारण, आम तौर पर बजट में दिए गए विवरण के साथ मांग को नहीं बताया जा सकता है।
2. प्रत्यानुदान (Vote of Credit) तब दिया जाता है जब चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किसी नई सेवा पर अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता उत्पन्न होती है, जिस पर उस वर्ष के बजट में विचार नहीं किया जाता है।
3. अनुपूरक अनुदान (Supplementary Grant) तब प्रदान किया जाता है जब संसद द्वारा विनियोग अधिनियम के माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष के लिए किसी विशेष सेवा के लिए अधिकृत राशि उस वर्ष के लिए अपर्याप्त पाई जाती है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

a) केवल 1

b) केवल 1 और 2

c) केवल 3

d) केवल 2 और 3

Q. 85) Solution (c)

एक वित्तीय वर्ष के लिए आय और व्यय के सामान्य अनुमान वाले बजट के अलावा, संसद द्वारा असाधारण या विशेष परिस्थितियों में कई अन्य अनुदान दिए जाते हैं:

- अतिरिक्त अनुदान: यह तब प्रदान किया जाता है जब चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उस वर्ष के बजट में विचार नहीं की गई किसी नई सेवा पर अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता उत्पन्न होती है।
- प्रत्यानुदान (Vote of Credit): यह भारत के संसाधनों पर एक अप्रत्याशित मांग को पूरा करने के लिए दिया जाता है, जब सेवा के परिमाण या अनिश्चित प्रकृति के कारण, मांग को आमतौर पर बजट में दिए गए विवरण के साथ नहीं बताया जा सकता है। अत: यह लोक सभा द्वारा कार्यपालिका को दिए गए ब्लैंक चेक के समान है।
- अनुपूरक अनुदान (Supplementary Grant) : यह तब दिया जाता है जब संसद द्वारा विनियोग अधिनियम के माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष के लिए किसी विशेष सेवा के लिए अधिकृत राशि उस वर्ष के लिए अपर्याप्त पाई जाती है।
- अतिरिक्त अनुदान (Excess Grant): यह तब दिया जाता है जब किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उस वर्ष के बजट में उस सेवा के लिए दी गई राशि से अधिक राशि खर्च की जाती है। वित्तीय वर्ष के बाद लोकसभा द्वारा इसे वोट दिया जाता है। मतदान के लिए लोकसभा में अतिरिक्त अनुदान की मांग प्रस्तुत करने से पहले, उन्हें संसद की लोक लेखा समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।
- असाधारण अनुदान (Exceptional Grant) : यह एक विशेष उद्देश्य के लिए दिया जाता है और किसी भी वित्तीय वर्ष की वर्तमान सेवा का हिस्सा नहीं होता है।
- टोकन अनुदान (Token Grant): यह तब दिया जाता है जब किसी नई सेवा पर प्रस्तावित व्यय को पूरा करने के लिए धन पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध कराया जा सकता है। एक सांकेतिक राशि के अनुदान की मांग (रू 1 का) लोकसभा के वोट के लिए प्रस्तुत की जाती है और यदि सहमति हो जाती है, तो धन उपलब्ध कराया जाता है। पुनर्विनियोग में एक मद से दूसरे मद में निधियों का अंतरण शामिल है।इसमें कोई अतिरिक्त खर्च नहीं होता है।

Q. 86) बजट में भारत की संचित निधि पर 'प्रभारित' व्यय और भारत की संचित निधि से किए गए व्यय को शामिल किया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत की संचित निधि से किया गया व्यय संसद द्वारा गैर-मतदान योग्य है।
2. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

a) केवल 1

b) केवल 2

c) दोनों 1 और 2

d) न तो 1 और न ही 2

Q. 86) Solution (d)

बजट में दो प्रकार के व्यय होते हैं-भारत की संचित निधि पर 'प्रभारित' व्यय और भारत की संचित निधि से किया गया व्यय। भारित व्यय संसद द्वारा गैर-मतदान योग्य है, अर्थात इस पर केवल संसद द्वारा चर्चा की जा सकती है, जबकि दूसरे प्रकार के लिए संसद द्वारा मतदान किया जाना है।

भारत की संचित निधि पर केवल उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की पेंशन ली जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते संबंधित राज्यों की संचित निधि पर भारित होते हैं।

Q. 87) निम्नलिखित विधेयक से संबंधित गतिरोध को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक में बुला सकता है:

a) साधारण विधेयक

b) वित्तीय बिल

c) धन विधेयक

d) संविधान संशोधन विधेयक

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

- केवल 1 और 2
- केवल 1, 2 और 3
- केवल 2, 3 और 4
- 1, 2, 3 और 4

Q. 87) Solution (a)

संयुक्त बैठक किसी विधेयक को पारित करने के बाद दोनों सदनों के बीच गतिरोध के समाधान के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त एक असाधारण तंत्र है। एक सदन द्वारा एक विधेयक को पारित करने और दूसरे सदन को प्रेषित करने के बाद निम्नलिखित तीन स्थितियों में से किसी एक के तहत एक गतिरोध हुआ माना जाता है:

- यदि बिल दूसरे सदन द्वारा खारिज कर दिया जाता है;
- यदि बिल में किए जाने वाले संशोधनों के बारे में सदनों ने अंततः असहमति जताई है; या
- यदि दूसरे सदन द्वारा विधेयक पारित किए बिना विधेयक की प्राप्ति की तारीख से छह महीने से अधिक बीत चुके हैं।

उपरोक्त तीन स्थितियों में, राष्ट्रपति विधेयक पर विचार-विमर्श करने और मतदान करने के उद्देश्य से दोनों सदनों को संयुक्त बैठक में बुला सकता है।

यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल साधारण विधेयकों या वित्तीय विधेयकों पर लागू होता है न कि धन विधेयकों या संविधान संशोधन विधेयकों पर।

धन विधेयक के मामले में, लोकसभा के पास अधिभावी शक्तियां होती हैं, जबकि एक संवैधानिक संशोधन विधेयक को प्रत्येक सदन द्वारा पृथक रूप से पारित किया जाना चाहिए।

Q. 88) एक विधेयक को धन विधेयक माना जाता है यदि इसमें निम्नलिखित से संबंधित प्रावधान हैं:

1. भारत की संचित निधि से धन का विनियोग।
2. स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी भी कर का अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन।
3. केंद्र सरकार द्वारा धन उधार लेने का विनियमन।

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

a) केवल 1 और 2

b) केवल 2 और 3

c) केवल 1 और 3

d) 1, 2 और 3

Q. 88) Solution (c)

संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयकों की परिभाषा से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि एक विधेयक को धन विधेयक माना जाता है यदि इसमें निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले से संबंधित 'केवल' प्रावधान होते हैं:

- किसी भी कर का अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन;
- केंद्र सरकार द्वारा धन उधार लेने का विनियमन;
- भारत की संचित निधि या भारत की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन का भुगतान या उसमें से धन की निकासी;
- भारत की संचित निधि से धन का विनियोग;
- भारत की संचित निधि पर प्रभारित किसी व्यय की घोषणा या ऐसे किसी व्यय की राशि में वृद्धि करना;
- भारत की संचित निधि या भारत के सार्वजनिक खाते के लिए धन की प्राप्ति या ऐसे धन की अभिरक्षा या जारी करना, या संघ या राज्य के खातों की लेखा परीक्षा; या

- ऊपर निर्दिष्ट मामलों में से किसी के लिए आकस्मिक कोई भी मामला।

हालाँकि, किसी विधेयक को केवल इस कारण से धन विधेयक नहीं माना जाता है कि वह निम्नलिखित के लिए प्रावधान करता है:

- जुर्माना या अन्य आर्थिक दंड लगाना, या
- प्रदान की गई सेवाओं के लिए लाइसेंस या शुल्क के लिए शुल्क की मांग या भुगतान; या
- स्थानीय उद्देश्यों के लिए किसी स्थानीय प्राधिकरण या निकाय द्वारा किसी भी कर का अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन।

यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। इस संबंध में उनके निर्णय पर किसी भी न्यायालय में या संसद के किसी सदन या यहां तक कि राष्ट्रपति द्वारा भी प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। जब कोई धन विधेयक सिफारिश के लिए राज्य सभा में भेजा जाता है और राष्ट्रपति को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो अध्यक्ष उसे धन विधेयक के रूप में समर्थन देता है।

Q. 89) सार्वजनिक विधेयक और निजी विधेयक के बीच अंतर के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. संसद में सार्वजनिक विधेयक एक मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।
2. निजी विधेयक को सदन में पेश करने के लिए सात दिन का नोटिस देना जरूरी है।
3. सदन द्वारा निजी विधेयक को अस्वीकार करना सरकार में संसदीय विश्वास की कमी की अभिव्यक्ति है और और उससे वह इस्तीफा दे सकती है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

a) केवल 1
b) केवल 1 और 2
c) केवल 3
d) केवल 2 और 3

Q. 89) Solution (a)

संसद के दोनों सदनों में विधायी प्रक्रिया समान है। प्रत्येक विधेयक को प्रत्येक सदन में समान चरणों से गुजरना होता है। एक विधेयक कानून के लिए एक प्रस्ताव है और विधिवत अधिनियमित होने पर यह एक अधिनियम या कानून बन जाता है।

संसद में पेश किए गए विधेयक दो प्रकार के होते हैं: सार्वजनिक विधेयक और निजी विधेयक (क्रमशः सरकारी विधेयक और निजी सदस्यों के विधेयक के रूप में भी जाने जाते हैं)। यद्यपि दोनों एक ही सामान्य प्रक्रिया द्वारा शासित होते हैं और सदन में समान चरणों से गुजरते हैं, वे विभिन्न मामलों में भिन्न होते हैं:

S. No.	सार्वजनिक विधेयक	निजी विधेयक

1.	इसे एक मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है	यह एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है
2.	यह सरकार (सत्तारूढ़ दल) की नीतियों को दर्शाता है।	यह सार्वजनिक मामले पर विपक्षी दल के रुख को दर्शाता है।
3.	इसके संसद द्वारा अनुमोदित होने की अधिक संभावना है	इसके संसद द्वारा अनुमोदित होने की संभावना कम होती है।
4.	सदन द्वारा इसकी अस्वीकृति सरकार में संसदीय विश्वास की कमी की अभिव्यक्ति के समान है और इससे उसका इस्तीफा हो सकता है	सदन द्वारा इसकी अस्वीकृति का सरकार में संसदीय विश्वास या उसके इस्तीफे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
5.	सदन में इसे पेश करने के लिए सात दिनों के नोटिस की आवश्यकता है	सदन में इसे पेश करने के लिए एक महीने का नोटिस चाहिए
6.	यह कानून विभाग के परामर्श से संबंधित विभाग द्वारा तैयार किया गया है।	इसका प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी संबंधित सदस्य की होती है।

Q.90) क्लोजर मोशन (closure motion) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. गिलोटिन क्लोजर के तहत, केवल महत्वपूर्ण खंडों को बहस और मतदान के लिए लिया जाता है और हस्तक्षेप करने वाले खंडों को छोड़ दिया जाता है और पारित किया जाता है।
2. कंगारू क्लोजर के तहत समय की कमी के कारण किसी विधेयक या संकल्प के बिना चर्चा वाले खंडों को भी चर्चा के साथ मतदान के लिए रखा जाता है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

a) केवल 1

b) केवल 2

c) दोनों 1 और 2

d) न तो 1 और न ही 2

Q. 90) Solution (d)

पीठासीन अधिकारी की सहमति से किए गए प्रस्ताव के अलावा आम सार्वजनिक महत्व के मामले पर कोई चर्चा नहीं हो सकती है। सदन विभिन्न मुद्दों पर या तो मंत्रियों या गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा पेश किए गए प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करके अपने निर्णय या राय व्यक्त करता है।

क्लोजर मोशन:

यह सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को कम करने के लिए एक सदस्य द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव है। यदि प्रस्ताव को सदन द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो बहस को तुरंत रोक दिया जाता है और मामले पर मतदान किया जाता है। क्लोजर मोशन चार प्रकार के होते हैं:

- साधारण या सिम्पल क्लोजर (Simple Closure) : यह तब होता है जब कोई सदस्य प्रस्ताव करता है कि 'इस मामले पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, अब मतदान के लिए रखा जाए'।
- क्लोजर बॉय कम्पार्टमेंट (Closure by Compartments) : इस मामले में, बहस शुरू होने से पहले एक विधेयक या एक लंबे संकल्प के खंड को भागों में बांटा जाता है। बहस पूरे हिस्से को कवर करती है और पूरे हिस्से को वोट देने के लिए रखा जाता है।
- कंगारू क्लोजर (Kangaroo Closure): इस प्रकार के तहत, केवल महत्वपूर्ण खंड बहस और मतदान के लिए लिए जाते हैं और हस्तक्षेप करने वाले खंडों को छोड़ दिया जाता है और पारित के रूप में लिया जाता है।
- गिलोटिन क्लोजर (Guillotine Closure): यह तब होता है जब समय की कमी के कारण किसी विधेयक या संकल्प के बिना चर्चा वाले खंडों को भी चर्चा के लिए मतदान के लिए रखा जाता है (चूंकि चर्चा के लिए आवंटित समय समाप्त हो गया है)।

Q. 91) निंदा प्रस्ताव (censure motion) और अविश्वास प्रस्ताव (no-confidence motion) के बीच अंतर के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. निन्दा प्रस्ताव को लोकसभा में स्वीकार किए जाने के कारणों का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है।
2. जब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो मंत्रिपरिषद को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।
3. अविश्वास प्रस्ताव किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ पेश किया जा सकता है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

a) केवल 1 और 2

b) केवल 2

c) केवल 3

d) केवल 2 और 3

Q. 91) Solution (b)

निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव के बीच अंतर:

क्र. सं.	निंदा प्रस्ताव	अविश्वास प्रस्ताव
1.	इसे लोकसभा में इसे अपनाने के कारणों का उल्लेख करना चाहिए।	इसे लोकसभा में अपनाने के कारणों को बताने की आवश्यकता नहीं है।

2.	इसे एक व्यक्तिगत मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ पेश किया जा सकता है।	इसे केवल मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही पेश किया जा सकता है।
3.	यह विशिष्ट नीतियों और कार्यों के लिए मंत्रिपरिषद की निंदा करने के लिए पेश किया गया है।	यह मंत्रिपरिषद में लोकसभा के विश्वास को सुनिश्चित करने के लिए पेश किया जाता है।
4.	यदि यह लोकसभा में पारित हो जाता है, तो मंत्रिपरिषद को कार्यालय से इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं होती है।	यदि यह लोकसभा में पारित हो जाता है, तो मंत्रिपरिषद को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।

Q. 92) लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इस समिति का गठन भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के प्रावधानों के तहत किया गया था।
2. सदस्यों का चुनाव लोकसभा द्वारा प्रतिवर्ष अपने सदस्यों में से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है।
3. समिति का कार्य भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट की जांच करना है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

a) केवल 1 और 2

b) केवल 2

c) केवल 3

d) केवल 2 और 3

Q. 92) Solution (c)

लोक लेखा समिति:

- यह समिति पहली बार 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत स्थापित की गई थी और तब से यह अस्तित्व में है।
- वर्तमान में, इसमें 22 सदस्य (लोकसभा से 15 और राज्य सभा से 7) शामिल हैं। सदस्यों का चुनाव संसद द्वारा प्रतिवर्ष अपने सदस्यों में से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। इस प्रकार, सभी दलों को इसमें उचित प्रतिनिधित्व मिलता है। सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष का होता है।
- एक मंत्री को समिति के सदस्य के रूप में नहीं चुना जा सकता है।

- समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा अपने सदस्यों में से की जाती है।
- 1966-67 तक, समिति के अध्यक्ष सत्ताधारी दल के थे। हालाँकि, 1967 के बाद से एक परंपरा विकसित हुई है जिसके तहत समिति के अध्यक्ष को हमेशा विपक्ष से चुना जाता है।
- समिति का कार्य भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट की जांच करना है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष रखा जाता है।
- सीएजी (CAG) राष्ट्रपति को तीन ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, अर्थात् विनियोग खातों पर ऑडिट रिपोर्ट, वित्त खातों पर ऑडिट रिपोर्ट और सार्वजनिक उपक्रमों पर ऑडिट रिपोर्ट।
- समिति तकनीकी अनियमितताओं का पता लगाने के लिए न केवल कानूनी और औपचारिक दृष्टिकोण से सार्वजनिक व्यय की जांच करती है, बल्कि बर्बादी, हानि, भ्रष्टाचार, अपव्यय, अक्षमता और निरर्थक व्यय के मामलों को सामने लाने के लिए अर्थव्यवस्था, विवेक, बुद्धिमत्ता और औचित्य के दृष्टिकोण से भी जांच करती है।

Q. 93) प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. इस समिति में लोकसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है।
2. एक मंत्री को इस समिति के सदस्य के रूप में नहीं चुना जा सकता है।
3. समिति का अध्यक्ष निरपवाद रूप से विपक्ष से होता है।

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

a) केवल 1 और 2

b) केवल 2

c) केवल 3

d) 1, 2 और 3

Q. 93) Solution (b)

प्राक्कलन समिति:

- इस समिति का उद्भव 1921 में स्थापित स्थायी वित्तीय समिति के रूप में देखा जा सकता है। स्वतंत्रता के बाद के युग में पहली प्राक्कलन समिति का गठन 1950 में तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर किया गया था।
- मूल रूप से, इसमें 25 सदस्य थे लेकिन 1956 में इसकी सदस्यता बढ़ाकर 30 कर दी गई थी। सभी तीस सदस्य केवल लोकसभा से होते हैं। इस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है।

- इन सदस्यों को लोकसभा द्वारा प्रत्येक वर्ष अपने ही सदस्यों में से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से चुना जाता है। इस प्रकार, सभी दलों को इसमें उचित प्रतिनिधित्व मिलता है। कार्यालय की अवधि एक वर्ष है।
- एक मंत्री को समिति के सदस्य के रूप में नहीं चुना जा सकता है। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा अपने सदस्यों में से की जाती है और वह निरपवाद रूप से सत्ताधारी दल से होता है।

Q. 94) सार्वजनिक उपक्रम समिति (Committee on Public Undertakings) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. समिति में 15 सदस्य होते हैं जिनमें 10 लोकसभा से और 5 राज्यसभा से होते हैं।
2. समिति सार्वजनिक उपक्रमों के व्यवसाय या वाणिज्यिक कार्यों से अलग प्रमुख सरकारी नीति के मामलों की जांच करती है।
3. समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा अपने सदस्यों में से की जाती है जो केवल लोकसभा से चुने जाते हैं।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

a) केवल 1
b) केवल 1 और 2
c) केवल 3
d) केवल 2 और 3

Q. 94) Solution (c)

सार्वजनिक उपक्रम समिति:

- यह समिति 1964 में कृष्णा मेनन समिति की सिफारिश पर बनाई गई थी।
- मूल रूप से, इसमें 15 सदस्य थे (लोकसभा से 10 और राज्य सभा से 5)। हालाँकि, 1974 में, इसकी सदस्यता 22 (लोकसभा से 15 और राज्य सभा से 7) तक बढ़ा दी गई थी।
- इस समिति के सदस्यों का चुनाव संसद द्वारा प्रतिवर्ष अपने सदस्यों में से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। इस प्रकार, सभी दलों को इसमें उचित प्रतिनिधित्व मिलता है। सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष का होता है। एक मंत्री को समिति के सदस्य के रूप में नहीं चुना जा सकता है।
- समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा अपने सदस्यों में से की जाती है जो केवल लोकसभा से चुने जाते हैं।
- इस प्रकार, समिति के सदस्य जो राज्यसभा से हैं, उन्हें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

समिति के कार्य हैं:

- सार्वजनिक उपक्रमों की रिपोर्ट और खातों की जांच करने के लिए
- सार्वजनिक उपक्रमों पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्टों की जांच करना।
- (सार्वजनिक उपक्रमों की स्वायत्तता और दक्षता के संदर्भ में) जांच करना कि क्या सार्वजनिक उपक्रमों के मामलों का प्रबंधन ठोस व्यावसायिक सिद्धांतों और विवेकपूर्ण वाणिज्यिक प्रथाओं के अनुसार किया जा रहा है।
- सार्वजनिक उपक्रमों के संबंध में लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति में निहित ऐसे अन्य कार्यों का प्रयोग करना जो अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर उसे आवंटित किए जाते हैं।

समिति को निम्नलिखित में से किसी की परीक्षण और जांच नहीं करनी है:

- सार्वजनिक उपक्रमों के व्यवसाय या वाणिज्यिक कार्यों से अलग प्रमुख सरकारी नीति के मामले।
- दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के मामले।
- जिन मामलों पर विचार करने के लिए मशीनरी किसी विशेष क़ानून द्वारा स्थापित की जाती है जिसके तहत एक विशेष सार्वजनिक उपक्रम स्थापित किया जाता है।

Q. 95) निम्नलिखित में से किस समिति का गठन सरकारी मंत्रालयों और विभागों के खर्च और धन के उपयोग के मामले में कामकाज की जांच करने के उद्देश्य से संसद द्वारा किया जाता है?

a) लोक लेखा समिति

b) सरकारी आश्वासनों पर समिति

c) सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति

d) प्राक्कलन समिति

Q. 95) Solution (d)

प्राक्कलन समिति संसद के चयनित सदस्यों की एक समिति है, जिसका गठन संसद द्वारा सरकारी मंत्रालयों और विभागों के खर्च और धन के उपयोग की जांच के उद्देश्य से किया जाता है।

समिति का कार्य बजट में शामिल अनुमानों की जांच करना और सार्वजनिक व्यय में 'अर्थव्यवस्था' का सुझाव देना है। इसलिए, इसे 'सतत अर्थव्यवस्था समिति' के रूप में वर्णित किया गया है।

अधिक विस्तार से, समिति के कार्य हैं:

- यह रिपोर्ट करने के लिए कि अनुमानों में अंतर्निहित नीति के अनुरूप अर्थव्यवस्था, संगठन में सुधार, दक्षता और प्रशासनिक सुधार क्या प्रभावित हो सकते हैं

- प्रशासन में दक्षता और मितव्ययिता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देना
- यह जांचने के लिए कि क्या अनुमानों में निहित नीति की सीमाओं के भीतर पैसा अच्छी तरह से रखा गया है
- उस रूप का सुझाव देना जिसमें अनुमानों को संसद में प्रस्तुत किया जाना है

समिति ऐसे सार्वजनिक उपक्रमों के संबंध में अपने कार्यों का प्रयोग नहीं करेगी जो सार्वजनिक उपक्रम समिति को आवंटित किए गए हैं। समिति पूरे वित्तीय वर्ष में समय-समय पर प्राक्कलनों की जांच जारी रख सकती है और जैसे-जैसे इसकी जांच होती है, सदन को रिपोर्ट कर सकती है। किसी एक वर्ष के समस्त प्राक्कलनों की जांच करना समिति का दायित्व नहीं होगा। इस तथ्य के बावजूद कि समिति ने कोई रिपोर्ट नहीं दी है, अनुदान की मांगों पर अंततः मतदान किया जा सकता है।

Q. 96) विभागीय स्थायी समितियों (departmental standing committees) के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. स्थायी समितियों का मुख्य उद्देश्य संसद के लिए मंत्रिपरिषद की वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
2. प्रत्येक स्थायी समिति में 22 सदस्य होते हैं; जो लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 होते हैं

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

a) केवल 1

b) केवल 2

c) दोनों 1 और 2

d) न तो 1 और न ही 2

Q. 96) Solution (a)

विभागीय स्थायी समितियां:

- लोकसभा की नियम समिति की सिफारिश पर, 1993 में संसद में 17 विभागीय-संबंधित स्थायी समितियों (डीआरएससी) का गठन किया गया था। 2004 में, ऐसी सात और समितियाँ स्थापित की गईं; इस प्रकार उनकी संख्या 17 से बढ़कर 24 हो गई।
- स्थायी समितियों का मुख्य उद्देश्य कार्यपालिका (अर्थात् मंत्रिपरिषद) की संसद के प्रति अधिक जवाबदेही, विशेष रूप से वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करना है। वे बजट पर अधिक प्रभावी ढंग से बहस करने में संसद की सहायता भी करते हैं।
- 24 स्थायी समितियाँ अपने अधिकार क्षेत्र में केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को कवर करती हैं।
- प्रत्येक स्थायी समिति में 31 सदस्य होते हैं (21 लोकसभा से और 10 राज्य सभा से)। लोकसभा के सदस्यों को अध्यक्ष द्वारा अपने सदस्यों में से नामित किया जाता है, जैसे राज्यसभा के सदस्यों को सभापति द्वारा अपने सदस्यों में से नामित किया जाता है।

- एक मंत्री किसी भी स्थायी समिति के सदस्य के रूप में नामित होने के योग्य नहीं है। यदि कोई सदस्य किसी स्थायी समिति में नामांकन के बाद मंत्री नियुक्त हो जाता है, तो वह समिति का सदस्य नहीं रह जाता है।
- प्रत्येक स्थायी समिति का कार्यकाल उसके गठन की तारीख से एक वर्ष का होता है।
- 24 स्थायी समितियों में से 8 राज्य सभा के अधीन और 16 लोक सभा के अधीन कार्य करती हैं।

Q. 97) निम्नलिखित में से कौन सी विभागीय स्थायी समितियाँ राज्य सभा के अधिकार क्षेत्र में आती हैं?

1. गृह मामलों की समिति
2. विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी समिति
3. कृषि संबंधी समिति

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

a) केवल 1 और 2

b) केवल 2 और 3

c) केवल 1 और 3

d) 1, 2 और 3

Q. 97) Solution (a)

दोनों सदनों की चौबीस विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समितियों में से, निम्नलिखित आठ समितियाँ राज्य सभा के सभापति के निर्देशन और नियंत्रण में कार्य करती हैं:

1. वाणिज्य पर समिति
2. गृह मामलों की समिति
3. मानव संसाधन विकास समिति
4. उद्योग पर समिति
5. विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी समिति
6. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर समिति
7. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण समिति
8. कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय संबंधी समिति

अन्य सोलह समितियाँ लोकसभा अध्यक्ष के निर्देशन और नियंत्रण में कार्य करती हैं।

Q. 98) निम्नलिखित में से कौन सी समिति लोकसभा के कार्यक्रम और समय सारिणी को नियंत्रित करती है तथा सरकार द्वारा सदन के समक्ष लाए गए विधायी और अन्य कार्यों के लेन-देन के लिए समय आवंटित करती है।?

a) सामान्य प्रयोजन समिति (General Purposes Committee)

b) सदन समिति

c) नियम समिति

d) कार्य सलाहकार समिति (Business Advisory Committee)

Q. 98) Solution (d)

कार्य सलाहकार समिति: यह समिति सदन के कार्यक्रम और समय सारिणी को नियंत्रित करती है। यह सरकार द्वारा सदन के समक्ष लाए गए विधायी और अन्य कार्यों के लेन-देन के लिए समय आवंटित करता है। लोकसभा समिति में अध्यक्ष के रूप में लोकसभा अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं। राज्यसभा में इसके पदेन अध्यक्ष के रूप में सभापति सहित 11 सदस्य होते हैं।

Q. 99) संसदीय मंचों (Parliamentary forums) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. लोकसभा का अध्यक्ष सभी संसदीय मंचों का पदेन अध्यक्ष होता है।
2. संसदीय मंचों के गठन के पीछे का उद्देश्य सदस्यों को महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित और सार्थक चर्चा करने की दृष्टि से संबंधित मंत्रियों के साथ बातचीत करने के लिए एक मंच प्रदान करना है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

a) केवल 1

b) केवल 2

c) दोनों 1 और 2

d) न तो 1 और न ही 2

Q.99) Solution (b)

संसदीय मंचों के गठन के पीछे उद्देश्य हैं:

i. कार्यान्वयन प्रक्रिया को तेज करने के लिए परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित और सार्थक चर्चा करने की दृष्टि से सदस्यों को संबंधित मंत्रियों, विशेषज्ञों और नोडल मंत्रालयों के प्रमुख अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए एक मंच प्रदान करना;

ii. सदस्यों को चिंता के प्रमुख क्षेत्रों और जमीनी स्तर की स्थिति के बारे में संवेदनशील बनाना और उन्हें देश और विदेश दोनों के विशेषज्ञों से नवीनतम जानकारी, ज्ञान, तकनीकी जानकारी और मूल्यवान इनपुट से लैस करना ताकि वे इन मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठा सकें। सदन के पटल और विभागीय-संबंधित स्थायी समितियों (डीआरएससी) की बैठकों में; तथा

iii. संबंधित मंत्रालयों, विश्वसनीय गैर सरकारी संगठनों, समाचार पत्रों, संयुक्त राष्ट्र, इंटरनेट आदि से महत्वपूर्ण मुद्दों पर डेटा के संग्रह के माध्यम से एक डेटा-बेस तैयार करना और सदस्यों को इसका प्रसार करना ताकि वे मंचों की चर्चा में सार्थक रूप से भाग ले सकें और स्पष्टीकरण मांग सकें। बैठकों में उपस्थित मंत्रालय के विशेषज्ञों या अधिकारियों से।

लोकसभा का अध्यक्ष जनसंख्या और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर संसदीय मंच को छोड़कर सभी मंचों का पदेन अध्यक्ष होता है, जिसमें राज्यसभा का सभापति पदेन अध्यक्ष होता है और अध्यक्ष पदेन सह-अध्यक्ष होता है। राज्य सभा के उपसभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष, संबंधित मंत्री और विभाग से संबंधित स्थायी समितियों के अध्यक्ष संबंधित मंचों के पदेन उपाध्यक्ष होते हैं।

प्रत्येक फोरम में 31 से अधिक सदस्य नहीं होते (राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति को छोड़कर) जिनमें से 21 से अधिक लोकसभा से नहीं होते हैं और 10 से अधिक राज्यसभा से नहीं होते हैं।

Q.100) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति यह देखने के लिए सभा पटल पर रखे गए सभी पत्रों की जांच करती है कि क्या वे संविधान के उपबंधों अथवा संबंधित अधिनियम या नियम का पालन करते हैं।
2. विशेषाधिकार समिति कदाचार के मामलों की जांच करके और उचित कार्रवाई की सिफारिश करके संसद सदस्यों की आचार संहिता लागू करती है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 100) Solution (d)

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति: यह समिति जांच करती है और सदन को रिपोर्ट करती है कि क्या संसद द्वारा प्रत्यायोजित या संविधान द्वारा कार्यपालिका को प्रदत्त विनियमों, नियमों और उपनियमों को बनाने की शक्तियों का इसके द्वारा उचित रूप से प्रयोग किया जा रहा है। दोनों सदनों में समिति में 15 सदस्य होते हैं। इसका गठन 1953 में किया गया था।

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (Committee on Papers Laid on the Table) : इस समिति का गठन 1975 में किया गया था। लोक सभा समिति में 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्य सभा समिति में 10 सदस्य होते हैं। यह मंत्रियों द्वारा सदन के पटल पर रखे गए सभी कागजातों की जांच करता है कि वे संविधान के प्रावधानों, या संबंधित अधिनियम या नियम का पालन करते हैं या नहीं। यह वैधानिक अधिसूचनाओं और आदेशों की जांच नहीं करता है जो अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

विशेषाधिकार समिति (Committee of Privileges) : इस समिति के कार्य प्रकृति में अर्ध-न्यायिक हैं। यह सदन और उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों के उल्लंघन के मामलों की जांच करता है और उचित कार्रवाई की सिफारिश करता है। लोकसभा समिति में 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा समिति में 10 सदस्य होते हैं।

आचार समिति (Ethics Committee) : इस समिति का गठन 1997 में राज्यसभा में और 2000 में लोकसभा में किया गया था। यह संसद सदस्यों की आचार संहिता को लागू करती है। यह कदाचार के मामलों की जांच करता है और उचित कार्रवाई की सिफारिश करता है। इस प्रकार, यह संसद में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने से संबंधित है।

Q. 101) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. केंद्रीय कानूनों के साथ-साथ राज्य कानूनों दोनों के लिए न्यायालयों की एकल प्रणाली को भारत सरकार अधिनियम 1919 से अपनाया गया था।
2. भारतीय संविधान का भाग VI सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र और शक्तियों से संबंधित है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

a) केवल 1

b) केवल 2

c) दोनों 1 और 2

d) न तो 1 और न ही 2

Q. 101) Solution (d)

भारतीय संविधान ने एक एकीकृत न्यायिक प्रणाली की स्थापना की है जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालय हैं।

एक उच्च न्यायालय (और राज्य स्तर से नीचे) के तहत, अधीनस्थ न्यायालयों का एक पदानुक्रम होता है, अर्थात जिला अदालतें और अन्य निचली अदालतें।

1935 के भारत सरकार अधिनियम से अपनाई गई अदालतों की यह एकल प्रणाली, केंद्रीय कानूनों के साथ-साथ राज्य के कानूनों को भी लागू करती है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत स्थापित भारत के संघीय न्यायालय का स्थान लेता है। हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र उसके पूर्ववर्ती न्यायालय की तुलना में अधिक है। यह इसलिए है क्योंकि; सुप्रीम कोर्ट ने अपील की सर्वोच्च अदालत के रूप में ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल की जगह ले ली है।

संविधान के भाग V में अनुच्छेद 124 से 147 सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों, प्रक्रियाओं आदि से संबंधित है। संसद भी उन्हें विनियमित करने के लिए अधिकृत है।

Q. 102) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति को दस वर्ष तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए।
2. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 102) Solution (b)

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएँ:

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए:

1. वह भारत का नागरिक होना चाहिए।

2. (ए) वह पांच साल के लिए एक उच्च न्यायालय (या उत्तराधिकार में उच्च न्यायालयों) का न्यायाधीश होना चाहिए था; या (बी) वह दस साल के लिए एक उच्च न्यायालय (या उत्तराधिकार में उच्च न्यायालयों) का वकील होना चाहिए था; या (सी) वह राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए।

उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की है।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। वित्तीय आपात स्थिति के दौरान उनकी नियुक्ति के बाद उनके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

Q. 103) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश पांच साल के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, तक पद धारण करता है।
2. सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

a) केवल 1

b) केवल 2

c) दोनों 1 और 2

d) न तो 1 और न ही 2

Q. 103) Solution (d)

न्यायाधीशों का कार्यकाल:

संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल निश्चित नहीं किया है। हालाँकि, यह इस संबंध में निम्नलिखित तीन प्रावधान करता है:

1. वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर बने रहते हैं। उसकी उम्र के संबंध में कोई भी प्रश्न ऐसे प्राधिकारी द्वारा और संसद द्वारा प्रदान किए गए तरीके से निर्धारित किया जाना है।
2. वह राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है।
3. उन्हें संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है।

Q. 104) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित करता है।
2. राष्ट्रपति को संबोधित एक न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव पर लोकसभा या राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
3. न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

a) केवल 1 और 2

b) केवल 2 और 3

c) केवल 1 और 3

d) 1, 2 और 3

Q. 104) Solution (c)

न्यायाधीशों को हटाना:

सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति हटाने का आदेश तभी जारी कर सकता है जब संसद द्वारा उसे उसी सत्र में इस तरह के निष्कासन के लिए एक अभिभाषण प्रस्तुत किया गया हो।

अभिभाषण को संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत (अर्थात उस सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत) द्वारा समर्थित होना चाहिए। निष्कासन का आधार दो है- सिद्ध कदाचार या अक्षमता हैं।

जज इंक्वायरी एक्ट (1968) महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को हटाने से संबंधित प्रक्रिया को नियंत्रित करता है:

1. 100 सदस्यों (लोकसभा के मामले में) या 50 सदस्यों (राज्य सभा के मामले में) द्वारा हस्ताक्षरित हटाने का प्रस्ताव अध्यक्ष/सभापति को दिया जाना है।
2. अध्यक्ष/सभापति प्रस्ताव को स्वीकार कर सकते हैं या इसे स्वीकार करने से इनकार कर सकते हैं।
3. यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है, तो अध्यक्ष/सभापति को आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन करना होता है।
4. समिति में शामिल होना चाहिए:
    - मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश,
    - एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और
    - एक प्रतिष्ठित न्यायविद्।
5. यदि समिति न्यायाधीश को दुर्व्यवहार या अक्षमता से पीड़ित होने का दोषी पाती है, तो सदन प्रस्ताव पर विचार कर सकता है।
6. संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के बाद, न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्ट्रपति को एक अभिभाषण प्रस्तुत किया जाता है।
7. अंत में, राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश पारित करता है।

सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश पर अब तक महाभियोग नहीं लगाया गया है, महाभियोग का पहला मामला सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वी. रामास्वामी (1991-1993) का है। हालांकि जांच समिति ने उन्हें दुर्व्यवहार का दोषी पाया, लेकिन उन्हें हटाया नहीं जा सका क्योंकि महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा में विफल रहा था। कांग्रेस पार्टी मतदान से अलग रही।

Q. 105) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. राष्ट्रपति एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है जब स्थायी न्यायाधीशों की कोरम की कमी होती है।
2. एक अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए एक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है।
3. भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

a) केवल 1

b) केवल 1 और 2

c) केवल 3

d) केवल 2 और 3

Q. 105) Solution (d)

तदर्थ न्यायाधीश:

- जब सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी सत्र को आयोजित करने या जारी रखने के लिए स्थायी न्यायाधीशों की गणपूर्ति की कमी होती है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं।
- वह ऐसा केवल संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श और राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही कर सकता है।
- इस प्रकार नियुक्त न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य होना चाहिए। इस प्रकार नियुक्त न्यायाधीश का यह कर्तव्य है कि वह अपने कार्यालय के अन्य कर्तव्यों को प्राथमिकता देते हुए सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में भाग लें।
- सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में भाग लेने के दौरान वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सभी अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और विशेषाधिकारों (और कर्तव्यों का निर्वहन) का लाभ लेता है।

सेवानिवृत्त न्यायाधीश:

- किसी भी समय, भारत का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश (जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए विधिवत रूप से योग्य है) से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में एक अस्थायी अवधि के लिए कार्य करने का अनुरोध कर सकता है।
- वह ऐसा केवल राष्ट्रपति और इस प्रकार नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की पूर्व सहमति से ही कर सकता है।
- ऐसा न्यायाधीश ऐसे भत्तों का हकदार है जो राष्ट्रपति निर्धारित करें।
- वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सभी अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और विशेषाधिकारों का भी लाभ लेगा। लेकिन, उन्हें अन्यथा सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश:

राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है जब:

1. भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय रिक्त है; या
2. भारत के मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से अनुपस्थित हैं; या
3. भारत के मुख्य न्यायाधीश अपने कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हैं।

Q. 106) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. अनुच्छेद 143 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में किए गए संदर्भों का निर्णय कम से कम पांच न्यायाधीशों की एक पीठ द्वारा किया जाता है।
2. संविधान भारत की संसद को सर्वोच्च न्यायालय की सीट के रूप में दिल्ली के अलावा अन्य स्थानों या स्थानों को नियुक्त करने के लिए अधिकृत करता है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

a) केवल 1

b) केवल 2

c) दोनों 1 और 2

d) न तो 1 और न ही 2

Q. 106) Solution (a)

भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रक्रिया:

- सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति के अनुमोदन से, न्यायालय के व्यवहार और प्रक्रिया को सामान्य रूप से विनियमित करने के लिए नियम बना सकता है।
- अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा दिए गए संवैधानिक मामलों या संदर्भों का निर्णय कम से कम पांच न्यायाधीशों वाली पीठ द्वारा किया जाता है।
- अन्य सभी मामलों का निर्णय एकल न्यायाधीशों और खंडपीठों द्वारा किया जाता है।
- निर्णय खुली अदालत द्वारा दिए जाते हैं। सभी निर्णय बहुमत से होते हैं लेकिन यदि भिन्न होते हैं, तो न्यायाधीश असहमतिपूर्ण निर्णय या राय दे सकते हैं

सुप्रीम कोर्ट की सीट

- संविधान दिल्ली को सर्वोच्च न्यायालय की सीट घोषित करता है। लेकिन, यह भारत के मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय की सीट के रूप में अन्य स्थान या स्थानों को नियुक्त करने के लिए भी अधिकृत करता है। वह इस संबंध में राष्ट्रपति के अनुमोदन से ही निर्णय ले सकता है।
- यह प्रावधान केवल वैकल्पिक है और अनिवार्य नहीं है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी न्यायालय राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय की सीट के रूप में किसी अन्य स्थान को नियुक्त करने के लिए कोई निर्देश नहीं दे सकता है।

Q. 107) संविधान सर्वोच्च न्यायालय के स्वतंत्र और निष्पक्ष कामकाज की सुरक्षा और सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान प्रदान करता है?

1. संविधान संसद या राज्य विधानमंडल में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के उनके कर्तव्यों के निर्वहन में आचरण के संबंध में किसी भी चर्चा पर रोक लगाता है।

2. भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यपालिका के हस्तक्षेप के बिना सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति कर सकता है।

3. संसद सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों को कम करने के लिए अधिकृत नहीं है।

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

a) केवल 1 और 2

b) केवल 2 और 3

c) केवल 1 और 3

d) 1, 2 और 3

Q. 107) Solution (d)

संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के स्वतंत्र और निष्पक्ष कामकाज की सुरक्षा और सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए हैं:

1. नियुक्ति का तरीका: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति (जिसका अर्थ है कैबिनेट) द्वारा न्यायपालिका के सदस्यों (यानी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश) के परामर्श से की जाती है। यह प्रावधान कार्यपालिका के पूर्ण विवेक को कम करता है और साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि न्यायिक नियुक्तियां किसी भी राजनीतिक या व्यावहारिक विचारों पर आधारित नहीं हैं।

2. कार्यकाल की सुरक्षा: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाती है। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा केवल संविधान में उल्लिखित तरीके और आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि वे राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त अपने पद पर नहीं रहते, यद्यपि उनकी नियुक्ति उनके द्वारा की जाती है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि अब तक सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को हटाया (या महाभियोग) नहीं लगाया गया है।

3. निश्चित सेवा शर्तें: उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार, अवकाश और पेंशन समय-समय पर संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं। वित्तीय आपात स्थिति को छोड़कर उनकी नियुक्ति के बाद उन्हें उनके अलाभकारी स्वरूप में नहीं बदला जा सकता है। इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा की शर्तें उनके कार्यकाल के दौरान समान रहती हैं।

4. संचित निधि पर प्रभारित व्यय: न्यायाधीशों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय के सभी प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। इस प्रकार, वे संसद द्वारा गैर-मतदान योग्य हैं (हालांकि इसके द्वारा उन पर चर्चा की जा सकती है)।

5. न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं की जा सकती: संविधान संसद या राज्य विधानमंडल में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अपने कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में किसी भी चर्चा को प्रतिबंधित करता है, सिवाय इसके कि जब महाभियोग प्रस्ताव संसद के विचाराधीन हो।

6. सेवानिवृत्ति के बाद अभ्यास पर प्रतिबंध: सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी न्यायालय में या किसी भी प्राधिकरण के समक्ष याचना करने या कार्य करने से प्रतिबंधित किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि वे भविष्य के पक्ष की आशा में किसी का पक्ष नहीं लेते हैं।

7. अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति: सर्वोच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति को उसकी अवमानना के लिए दंडित कर सकता है। इस प्रकार, इसके कार्यों और निर्णयों की किसी के द्वारा आलोचना और विरोध नहीं किया जा सकता है। यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपने अधिकार, गरिमा और सम्मान को बनाए रखने के लिए निहित है।

8. अपने कर्मचारियों को नियुक्त करने की स्वतंत्रता: भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यपालिका के हस्तक्षेप के बिना सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त कर सकता है। वह उनकी सेवा की शर्तें भी निर्धारित कर सकता है।

9. इसके अधिकार क्षेत्र में कटौती नहीं की जा सकती: संसद सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों को कम करने के लिए अधिकृत नहीं है। संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को विभिन्न प्रकार के क्षेत्राधिकार की गारंटी दी है। हालाँकि, संसद इसे बढ़ा सकती है।

10. कार्यपालिका से अलगाव: संविधान राज्य को सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है। इसका मतलब है कि कार्यकारी अधिकारियों के पास न्यायिक शक्तियां नहीं होनी चाहिए। नतीजतन, इसके लागू होने पर, न्यायिक प्रशासन में कार्यकारी अधिकारियों की भूमिका समाप्त हो गई।

Q. 108) निम्नलिखित में से किस मामले के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास अनन्य मूल क्षेत्राधिकार है?

1. केंद्र और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद
2. दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद
3. अंतर्राज्यीय जल विवाद

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

a) केवल 1
b) केवल 1 और 2
c) केवल 3
d) केवल 2 और 3

Q. 108) Solution (b)

एक संघीय अदालत के रूप में, सुप्रीम कोर्ट भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों के बीच विवादों का फैसला करता है। अधिक विस्तृत रूप से, कोई विवाद:

a. केंद्र और एक या अधिक राज्यों के बीच; या

b. एक तरफ केंद्र और किसी राज्य या राज्यों के बीच और दूसरी तरफ एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच; या

c. दो या दो से अधिक राज्यों के बीच।

उपरोक्त संघीय विवादों में, सर्वोच्च न्यायालय के पास अनन्य मूल अधिकार क्षेत्र है। अनन्य साधन, कोई अन्य अदालत ऐसे विवादों और मूल साधनों, ऐसे विवादों को पहली बार में सुनने की शक्ति, अपील के माध्यम से नहीं तय कर सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय के अनन्य मूल क्षेत्राधिकार के संबंध में, दो बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए:

- विवाद में एक प्रश्न शामिल होना चाहिए (चाहे कानून या तथ्य का) जिस पर कानूनी अधिकार का अस्तित्व या सीमा निर्भर करती है। इस प्रकार, राजनीतिक प्रकृति के प्रश्नों को इससे बाहर रखा गया है।
- किसी निजी नागरिक द्वारा केंद्र या राज्य के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लाए गए किसी भी मुकदमे पर इसके तहत विचार नहीं किया जा सकता है।

इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय के इस अधिकार क्षेत्र का विस्तार निम्नलिखित तक नहीं है::

a. किसी संविधान-पूर्व संधि, समझौते, वाचा, समझोते , सनद या अन्य समान साधन से उत्पन्न होने वाला विवाद।

b. किसी संधि, समझौते आदि से उत्पन्न विवाद, जो विशेष रूप से यह प्रदान करता है कि उक्त अधिकार क्षेत्र ऐसे विवाद तक सीमित नहीं है।

c. अंतर्राज्यीय जल विवाद।

d. वित्त आयोग को भेजे गए मामलें

e. केंद्र और राज्यों के बीच कुछ खर्चों और पेंशन का समायोजन।

f. केंद्र और राज्यों के बीच वाणिज्यिक प्रकृति का साधारण विवाद।

g. केंद्र के खिलाफ एक राज्य द्वारा हर्जाने की वसूली।

1961 में, सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र के तहत पहला मुकदमा पश्चिम बंगाल द्वारा केंद्र के खिलाफ लाया गया था। राज्य सरकार ने संसद द्वारा पारित कोयला क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अधिनियम की वैधता को बरकरार रखते हुए मुकदमे को खारिज कर दिया।

Q. 109) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सर्वोच्च न्यायालय का रिट अधिकार क्षेत्र मौलिक और अनन्य है।
2. सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

a) केवल 1

b) केवल 2

c) दोनों 1 और 2

d) न तो 1 और न ही 2

Q. 109) Solution (b)

सुप्रीम कोर्ट का रिट क्षेत्राधिकार:

- संविधान ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों के गारंटर और रक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया है।
- सुप्रीम कोर्ट को एक पीड़ित नागरिक के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण सहित रिटें जारी करने की शक्ति दी गई है। इस संबंध में, सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र इस अर्थ में है कि एक पीड़ित नागरिक जरूरी नहीं कि अपील के माध्यम से सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है,
- हालांकि, सुप्रीम कोर्ट का रिट अधिकार क्षेत्र अनन्य नहीं है। उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का भी अधिकार है। इसका मतलब है, जब किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो पीड़ित पक्ष के पास सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जाने का विकल्प होता है।
- इसलिए, संघीय विवादों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र मौलिक अधिकारों से संबंधित विवादों के संबंध में अपने मूल क्षेत्राधिकार से अलग है। पहले मामले में, यह अनन्य है और दूसरे मामले में, यह उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के साथ समवर्ती है। इसके अलावा, पहले मामले में शामिल पक्ष संघ (केंद्र और राज्य) की इकाइयाँ हैं जबकि दूसरे मामले में विवाद एक नागरिक और सरकार (केंद्र या राज्य) के बीच है।
- सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार में भी अंतर है। सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है न कि अन्य उद्देश्यों के लिए। दूसरी ओर, उच्च न्यायालय न केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए बल्कि अन्य उद्देश्यों के लिए भी रिट जारी कर सकता है।
- इसका अर्थ है कि उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में व्यापक है। लेकिन, संसद सर्वोच्च न्यायालय को अन्य प्रयोजनों के लिए भी रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है।

Q.110) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून या सार्वजनिक महत्व के किसी भी प्रश्न पर राष्ट्रपति को अपनी राय देने से मना कर सकता है जो उत्पन्न हुआ है या जो उत्पन्न होने की संभावना है।
2. भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को व्यक्त की गई राय केवल सलाहकारी है, न्यायिक अभिव्यक्ति नहीं।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

a) केवल 1

b) केवल 2

c) दोनों 1 और 2

d) न तो 1 और न ही 2

Q. 110) Solution (c)

सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार:

संविधान (अनुच्छेद 143) राष्ट्रपति को दो श्रेणियों के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत करता है:

a. कानून या सार्वजनिक महत्व के तथ्य के किसी भी प्रश्न पर जो उत्पन्न हो गया हो या जिसके उत्पन्न होने की संभावना हो।

b. किसी भी संविधान-पूर्व संधि, समझौते, प्रसंविदा, अनुबंध, सनद या इसी तरह के अन्य साधनों से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद पर।

पहले मामले में, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को अपनी राय देने के लिए निविदा दे सकता है या मना कर सकता है। लेकिन, दूसरे मामले में, सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति को अपनी राय देनी चाहिए।

दोनों ही मामलों में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई राय केवल सलाहकारी है, न्यायिक अभिव्यक्ति नहीं। इसलिए, यह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है; वह राय का पालन कर सकता है या नहीं कर सकता है। हालाँकि, यह सरकार को उसके द्वारा तय किए जाने वाले मामले पर एक आधिकारिक कानूनी राय रखने की सुविधा देता है।

Q. 111) भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है।
2. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है।

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

a) केवल 1

b) केवल 2

c) दोनों 1 और 2

d) न तो 1 और न ही 2

Q. 111) Solution (b)

उच्च न्यायालय की स्थापना भारत में 1862 में हुई जब कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए।

भारत का संविधान प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है, लेकिन 1956 के सातवें संशोधन अधिनियम ने संसद को दो या दो से अधिक राज्यों या दो या अधिक राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने के लिए अधिकृत किया गया।

न्यायाधीशों की नियुक्ति:

- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
- मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद की जाती है।
- अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श किया जाता है। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय के मामले में, राष्ट्रपति द्वारा सभी संबंधित राज्यों के राज्यपालों से परामर्श किया जाता है।

Q. 112) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी तरीके से और उसी आधार पर हटाया जा सकता है जिस तरह से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है।
2. उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करता है।
3. राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3

Q. 112) Solution (c)

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल:

संविधान ने किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल निश्चित नहीं है। हालाँकि, यह इस संबंध में निम्नलिखित चार प्रावधान करता है:

1. वह 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर बने रहते हैं। उनकी उम्र के संबंध में कोई भी प्रश्न भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाना है और राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है।
2. वह राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है।
3. उन्हें संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है।
4. जब वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होता है या जब उसे किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाता है तो वह अपना पद खाली कर देता है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना:

- किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से उसके पद से हटाया जा सकता है।
- राष्ट्रपति हटाने का आदेश तभी जारी कर सकता है जब संसद द्वारा उसे उसी सत्र में इस तरह के निष्कासन के लिए एक अभिभाषण प्रस्तुत किया गया हो।
- अभिभाषण को संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत (अर्थात उस सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत) द्वारा समर्थित होना चाहिए।
- निष्कासन के आधार दो सिद्ध कदाचार या अक्षमता हैं।
- इस प्रकार, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी तरीके से और उसी आधार पर हटाया जा सकता है जिस तरह से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण:

- राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है।
- स्थानान्तरण पर, वह अपने वेतन के अतिरिक्त ऐसा प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने का हकदार है जैसा कि संसद द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

Q. 113) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा की शर्तें संबंधित राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित की जाती हैं।
2. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और पेंशन राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 113) Solution (d)

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार, अवकाश और पेंशन समय-समय पर संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। लेकिन, वित्तीय आपात स्थिति के अलावा उनकी नियुक्ति के बाद उन्हें उनके अलाभकारी स्वरूप में नहीं बदला जा सकता है। इस प्रकार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा की शर्तें उनके कार्यकाल के दौरान समान रहती हैं।

न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन के साथ-साथ एक उच्च न्यायालय के प्रशासनिक खर्च राज्य की संचित निधि पर प्रभारित होते हैं। इस प्रकार, वे राज्य विधायिका द्वारा गैर-मतदान योग्य हैं (हालांकि इसके द्वारा उन पर चर्चा की जा सकती है)। यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन भारत की संचित निधि पर प्रभारित होती है, न कि राज्य पर।

Q. 114) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के चुनाव से संबंधित विवादों के संबंध में उच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र है।
2. नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में उच्च न्यायालयों का मूल और अनन्य क्षेत्राधिकार है।
3. उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के समवर्ती है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2
c) केवल 3
d) केवल 1 और 3

Q. 114) Solution (d)

उच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार:

इसका अर्थ है उच्च न्यायालय की प्रथम दृष्टया में विवादों को सुनने की शक्ति, अपील के माध्यम से नहीं। यह निम्नलिखित तक विस्तृत है:

- अदालत की अवमानना के मामले।
- संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के चुनाव से संबंधित विवाद।
- राजस्व मामले या राजस्व संग्रह में आदेशित या किए गए कार्य के संबंध में।
- नागरिकों के मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन।
- मामलों को एक अधीनस्थ अदालत से संविधान की व्याख्या से संबंधित अपनी फाइल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया।
- चार उच्च न्यायालयों (यानी, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास और दिल्ली उच्च न्यायालय) के पास उच्च मूल्य के मामलों में मूल नागरिक अधिकार क्षेत्र है।

1973 से पहले, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास उच्च न्यायालयों में भी मूल आपराधिक अधिकार क्षेत्र था। इसे आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 द्वारा पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था।

उच्च न्यायालयों का रिट क्षेत्राधिकार:

- संविधान का अनुच्छेद 226 एक उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और किसी अन्य उद्देश्य के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार-पृच्छा सहित रिट जारी करने का अधिकार देता है।
- वाक्यांश 'किसी अन्य उद्देश्य के लिए' एक सामान्य कानूनी अधिकार के प्रवर्तन को संदर्भित करता है। उच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति, प्राधिकरण और सरकार को न केवल अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर बल्कि अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के बाहर भी रिट जारी कर सकता है यदि उसके प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में कार्रवाई का कारण उत्पन्न हो।
- उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 226 के तहत) अनन्य नहीं है, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 32 के तहत) के समवर्ती है। इसका मतलब है, जब किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो पीड़ित पक्ष के पास सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जाने का विकल्प होता है।
- हालाँकि, उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में व्यापक है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है, न कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए, अर्थात यह उस मामले तक विस्तारित नहीं होता है जहां एक सामान्य कानूनी अधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाया जाता है।

Q. 115) न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों पर न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान द्वारा प्रदान की गई है।
2. न्यायपालिका पर न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान की मूल विशेषता है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 115) Solution (c)

न्यायिक समीक्षा केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के विधायी अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने के लिए न्यायपालिका की शक्ति है। जांच करने पर, यदि वे संविधान (अधिकारातीत) का उल्लंघन करते पाए जाते हैं, तो उन्हें न्यायपालिका द्वारा अवैध, असंवैधानिक और अमान्य (रिक्त और शून्य) घोषित किया जा सकता है। नतीजतन, उन्हें सरकार द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है।

न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पन्न और विकसित हुआ। यह पहली बार अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जॉन मार्शल द्वारा मार्बरी बनाम मैडिसन (1803) के प्रसिद्ध मामले में प्रतिपादित किया गया था।

दूसरी ओर, भारत में, संविधान स्वयं न्यायपालिका (उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों दोनों) को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करता है। इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा की शक्ति को संविधान की मूल विशेषता या संविधान की मूल संरचना के एक तत्व के रूप में घोषित किया है। इसलिए, न्यायिक समीक्षा की शक्ति को संवैधानिक संशोधन द्वारा भी कम या बाहर नहीं किया जा सकता है।

Q. 116) निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करता है?

1. अनुच्छेद 13
2. अनुच्छेद 133
3. अनुच्छेद 246

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3

Q. 116) Solution (d)

निम्नलिखित अनुच्छेद स्पष्ट रूप से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करते हैं:

1. अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि सभी कानून जो मौलिक अधिकारों के साथ असंगत हैं या उन्हें न्यून करते हैं, वे अमान्य और शून्य होंगे।
2. अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने के अधिकार की गारंटी देता है और सर्वोच्च न्यायालय को उस उद्देश्य के लिए निर्देश या आदेश या रिट जारी करने का अधिकार देता है।
3. अनुच्छेद 131 केंद्र-राज्य और अंतर-राज्यीय विवादों में सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र का प्रावधान करता है।
4. अनुच्छेद 132 संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रावधान करता है।
5. अनुच्छेद 133 दीवानी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रावधान करता है।
6. अनुच्छेद 134 आपराधिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रावधान करता है।
7. अनुच्छेद 134-ए उच्च न्यायालयों से सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र से संबंधित है।

8. अनुच्छेद 135 सुप्रीम कोर्ट को किसी भी पूर्व संविधान कानून के तहत संघीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार देता है।

9. अनुच्छेद 136 सुप्रीम कोर्ट को किसी भी अदालत या ट्रिब्यूनल (सैन्य न्यायाधिकरण और कोर्ट मार्शल को छोड़कर) से अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने का अधिकार देता है।

10. अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को कानून या तथ्य के किसी भी प्रश्न और किसी भी पूर्व-संविधान कानूनी मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत करता है।

11. अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और किसी अन्य उद्देश्य के लिए निर्देश या आदेश या रिट जारी करने का अधिकार देता है।

12. अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालयों को उनके संबंधित क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र (सैन्य न्यायालयों या न्यायाधिकरणों को छोड़कर) के भीतर सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण की शक्ति प्रदान करता है।

13. अनुच्छेद 245 संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों की क्षेत्रीय सीमा से संबंधित है।

14. अनुच्छेद 246 संसद और राज्यों के विधान मंडलों (अर्थात संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची) द्वारा बनाए गए कानूनों की विषय वस्तु से संबंधित है।

15. अनुच्छेद 251 और 254 में प्रावधान है कि केंद्रीय कानून और राज्य के कानून के बीच संघर्ष की स्थिति में, केंद्रीय कानून राज्य के कानून पर हावी होता है और राज्य का कानून शून्य होगा।

16. अनुच्छेद 372 पूर्व संविधान कानूनों के प्रवृत्त/लागू रहने से संबंधित है।

Q. 117) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. न्यायिक सक्रियता (judicial activism) की अवधारणा यूके में उत्पन्न और विकसित हुई।

2. जनहित याचिका की अवधारणा न्यायिक सक्रियता का एक उत्पाद है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

a) केवल 1

b) केवल 2

c) दोनों 1 और 2

d) न तो 1 और न ही 2

Q. 117) Solution (b)

न्यायिक सक्रियता नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और समाज में न्याय को बढ़ावा देने में न्यायपालिका द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका को दर्शाती है। दूसरे शब्दों में, इसका तात्पर्य सरकार के अन्य दो अंगों (विधायिका और कार्यपालिका) को अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए दबाव डालने के लिए न्यायपालिका द्वारा निभाई गई मुखर भूमिका से है।

न्यायिक सक्रियता की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पन्न और विकसित हुई। भारत में, न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत 1970 के दशक के मध्य में पेश किया गया था। न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर, न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती, न्यायमूर्ति ओ. चिन्नप्पा रेड्डी और न्यायमूर्ति डी.ए. देसाई ने देश में न्यायिक सक्रियता की नींव रखी।

न्यायिक सक्रियता न्यायिक शक्ति का प्रयोग करने का एक तरीका है जो न्यायाधीशों को प्रगतिशील और नई सामाजिक नीतियों के पक्ष में न्यायिक मिसाल के सामान्य रूप से सख्ती से पालन करने के लिए प्रेरित करती है। यह आमतौर पर सोशल इंजीनियरिंग के लिए कॉल करने वाले निर्णय द्वारा चिह्नित किया जाता है, और कभी-कभी ये निर्णय विधायी और कार्यकारी मामलों में घुसपैठ का प्रतिनिधित्व करते हैं।

जनहित याचिका (PIL) की अवधारणा 1960 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पन्न और विकसित हुई थी। भारत में, जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सक्रियता भूमिका का एक उत्पाद है। इसे 1980 के दशक की शुरुआत में पेश किया गया था। न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर और न्यायमूर्ति पी.एन.भगवती जनहित याचिका की अवधारणा के अग्रदूत थे।

जनहित याचिका के तहत, कोई भी जन-हितैषी नागरिक या सामाजिक संगठन किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अदालत का रुख कर सकता है, जो अपनी गरीबी या अज्ञानता या सामाजिक या आर्थिक रूप से वंचित स्थिति के कारण खुद उपायों के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने में असमर्थ हैं। इस प्रकार, एक जनहित याचिका में, 'पर्याप्त रुचि' रखने वाला जनता का कोई भी सदस्य अन्य व्यक्तियों के अधिकारों को लागू करने और एक सामान्य शिकायत के निवारण के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है।

Q. 118) जनहित याचिका के रूप में निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आने वाली याचिकाओं पर विचार किया जा सकता है?

1. चिकित्सा संस्थान में प्रवेश के संबंध में याचिका
2. श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना
3. मामला दर्ज करने से इंकार करने पर पुलिस के खिलाफ याचिका

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

a) केवल 1

b) केवल 1 और 2

c) केवल 3

d) केवल 2 और 3

Q. 118) Solution (d)

जनहित याचिका का दायरा (PIL):

1998 में, सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका के रूप में प्राप्त पत्रों या याचिकाओं पर विचार करने के लिए दिशानिर्देशों का एक सेट तैयार किया।

इन दिशानिर्देशों को 1993 और 2003 में संशोधित किया गया था। उनके अनुसार, केवल निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले पत्रों या याचिकाओं को आम तौर पर जनहित याचिका के रूप में माना जाएगा:

- बंधुआ मजदूरी का मामला
- उपेक्षित बच्चे
- श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना और आकस्मिक श्रमिकों का शोषण और श्रम कानूनों के उल्लंघन की शिकायतें (व्यक्तिगत मामलों को छोड़कर)
- जेलों से प्रताड़ना, समय से पहले रिहाई और 14 साल की जेल पूरी होने के बाद रिहाई की मांग, जेल में मौत, स्थानांतरण, निजी बॉन्ड पर रिहाई, मौलिक अधिकार के रूप में त्वरित सुनवाई की शिकायत करने वाली याचिकाएं
- मामला दर्ज करने से इंकार करने, पुलिस द्वारा प्रताड़ित करने और पुलिस हिरासत में मौत के मामले में पुलिस के खिलाफ याचिकाएं
- महिलाओं पर अत्याचार, विशेष रूप से दुल्हन के उत्पीड़न, दुल्हन को जलाने, बलात्कार, हत्या, अपहरण आदि के खिलाफ याचिकाएं।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों से सह-ग्रामीणों या पुलिस द्वारा ग्रामीणों के उत्पीड़न या प्रताड़ना की शिकायत करने वाली याचिकाएं
- पर्यावरण प्रदूषण, पारिस्थितिक संतुलन की गड़बड़ी, दवाओं, खाद्य अपमिश्रण, विरासत और संस्कृति के रखरखाव, प्राचीन वस्तुएं, वन और वन्य जीवन और सार्वजनिक महत्व के अन्य मामलों से संबंधित याचिकाएं
- दंगा पीड़ितों की याचिका
- पारिवारिक पेंशन

निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले मामलों पर जनहित याचिका के रूप में विचार नहीं किया जाएगा:

- जमींदार-किरायेदार मामले
- सेवा मामले और पेंशन और ग्रेच्युटी से संबंधित मामले
- चिकित्सा और अन्य शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश
- उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए याचिकाएं

Q. 119) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति को दस साल के लिए वकील या अभिवक्ता होना चाहिए था।
2. जिला न्यायालयों और अन्य अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निहित है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

a) केवल 1

b) केवल 2

c) दोनों 1 और 2

d) न तो 1 और न ही 2

Q. 119) Solution (d)

संविधान के भाग VI में अनुच्छेद 233 से 237 अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन को विनियमित करने और कार्यपालिका से उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान करता है।

जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति:

किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, तैनाती और पदोन्नति राज्य के राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है।

जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए:

- वह पहले से ही केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में नहीं होना चाहिए।
- उसे सात साल तक वकील या अभिवक्ता होना चाहिए था।
- उनकी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय द्वारा सिफारिश की जानी चाहिए।

अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण:

जिला न्यायालयों और अन्य अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, जिसमें राज्य की न्यायिक सेवा से संबंधित व्यक्तियों की तैनाती, पदोन्नति और छुट्टी शामिल है और जिला न्यायाधीश के पद से किसी भी पद पर हैं, उच्च न्यायालय में निहित हैं।

Q.120) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. जिला न्यायाधीश के पास दीवानी और आपराधिक दोनों मामलों में मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार है।
2. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास आजीवन कारावास और मृत्युदंड सहित किसी भी सजा को लागू करने की शक्ति है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

a) केवल 1

b) केवल 2

c) दोनों 1 और 2

d) न तो 1 और न ही 2

Q. 120) Solution (a)

अधीनस्थ न्यायालय:

- अधीनस्थ न्यायपालिका की संगठनात्मक संरचना, अधिकार क्षेत्र और नामकरण राज्यों द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसलिए, वे एक राज्य से दूसरे राज्य में थोड़े भिन्न होते हैं।
- जिला न्यायाधीश जिले में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण है। उसके पास दीवानी और आपराधिक दोनों मामलों में मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार है। दूसरे शब्दों में, जिला न्यायाधीश सत्र न्यायाधीश भी होता है।
- जब वह दीवानी मामलों को देखता है, तो उसे जिला न्यायाधीश के रूप में जाना जाता है और जब वह आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है, तो उसे सत्र न्यायाधीश कहा जाता है।
- जिला न्यायाधीश न्यायिक और प्रशासनिक दोनों शक्तियों का प्रयोग करता है। उसके पास जिले के सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर पर्यवेक्षी शक्तियाँ भी हैं। उनके आदेशों और निर्णयों के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जाती है।
- सत्र न्यायाधीश को आजीवन कारावास और मृत्युदंड सहित कोई भी दंड अधिरोपित करने की शक्ति होती है। हालांकि, उनके द्वारा पारित मौत की सजा उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि के अधीन है, चाहे कोई अपील हो या नहीं।
- जिला एवं सत्र न्यायालय के नीचे दीवानी पक्ष में अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय तथा आपराधिक पक्ष में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय है। अधीनस्थ न्यायाधीश दीवानी मुकदमों पर असीमित आर्थिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है।
- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उन आपराधिक मामलों का फैसला करता है जिनके लिए सात वर्ष की अवधि तक कारावास की सजा हो सकती है।
- सबसे निचले स्तर पर, दीवानी पक्ष पर, मुंसिफ का न्यायालय है और आपराधिक पक्ष पर, न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय है। मुंसिफ के पास सीमित क्षेत्राधिकार होता है और वह छोटी आर्थिक हिस्सेदारी के दीवानी मामलों का फैसला करता है।
- न्यायिक मजिस्ट्रेट आपराधिक मामलों की कोशिश करता है जिसमें तीन साल तक की कैद की सजा हो सकती है।

Q. 121) भारत के चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद के मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त के पास निर्णायक मताधिकार होता है।
2. मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं।
3. संविधान ने सेवानिवृत्त होने वाले चुनाव आयुक्तों को सरकार द्वारा आगे किसी भी नियुक्ति से वंचित नहीं किया है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

a) केवल 1 और 2

b) केवल 2 और 3

c) केवल 3

d) 1, 2 और 3

Q. 121) Solution (c)

चुनाव आयोग देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सीधे भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है।

मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्तों के पास समान शक्तियां हैं और उन्हें समान वेतन, भत्ते और अन्य अनुलब्धियां मिलती हैं, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त और/या दो के बीच मतभेद के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान हैं। इस मामले पर आयोग द्वारा बहुमत से निर्णय लिया जाता है।

मुख्य चुनाव आयुक्त को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके से और उसी आधार पर उन्हें उनके पद से हटाया नहीं जा सकता है। दूसरे शब्दों में, उसे राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित एक प्रस्ताव के आधार पर, या तो साबित दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। इस प्रकार, वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त अपना पद धारण नहीं करता, यद्यपि वह उसके द्वारा नियुक्त किया जाता है।

हालांकि संविधान ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को सुरक्षित रखने और सुनिश्चित करने की मांग की है, लेकिन कुछ खामियों पर ध्यान दिया जा सकता है, जैसे,

- संविधान ने चुनाव आयोग के सदस्यों की योग्यता (कानूनी, शैक्षिक, प्रशासनिक या न्यायिक) निर्धारित नहीं की है।
- संविधान ने चुनाव आयोग के सदस्यों के कार्यकाल को निर्दिष्ट नहीं किया है।
- संविधान ने सेवानिवृत्त होने वाले चुनाव आयुक्तों को सरकार द्वारा आगे किसी भी नियुक्ति से वंचित नहीं किया है।

Q. 122) संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को किनके चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है:

1. भारतीय संसद
2. पंचायतों
3. भारत के उपराष्ट्रपति का पद
4. राज्यों के राज्यपालों का पद

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

a) केवल 1

b) केवल 1 और 3
c) केवल 1, 2 और 3
d) केवल 1, 3 और 4

Q. 122) Solution (b)

संविधान के अनुच्छेद 324 में यह प्रावधान है कि संसद, राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय और भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालय के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित होगी।

इस प्रकार, चुनाव आयोग इस अर्थ में एक अखिल भारतीय निकाय है कि यह केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों के लिए समान है।

चुनाव आयोग का राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनावों से कोई सरोकार नहीं है। इसके लिए भारत का संविधान एक अलग राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान करता है।

राज्यपाल को न तो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है और न ही परोक्ष रूप से किसी विशेष रूप से गठित निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित किया जाता है जैसा कि राष्ट्रपति के मामले में होता है। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा उनके हाथ और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है।

Q. 123) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 284 में वित्त आयोग का प्रावधान है।
2. संविधान राष्ट्रपति को वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता और उनके चयन के तरीके को निर्धारित करने के लिए अधिकृत करता है।
3. वित्त आयोग भारत के राष्ट्रपति को उन सिद्धांतों के बारे में सिफारिशें करता है जो भारत के आकस्मिक निधि से राज्यों को सहायता अनुदान को नियंत्रित करना चाहिए।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2
c) केवल 3
d) केवल 1 और 3

Q. 123) Solution (b)

भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 एक अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में एक वित्त आयोग का प्रावधान करता है। इसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक पाँचवें वर्ष या ऐसे पूर्व समय में किया जाता है, जब वह आवश्यक समझे।

वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। वे राष्ट्रपति द्वारा अपने आदेश में निर्दिष्ट अवधि के लिए पद धारण करते हैं। वे पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं।

संविधान संसद को आयोग के सदस्यों की योग्यता और उनके चयन के तरीके को निर्धारित करने के लिए अधिकृत करता है। तदनुसार, संसद ने आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताएं निर्दिष्ट की हैं। अध्यक्ष को सार्वजनिक मामलों में अनुभव रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए और चार अन्य सदस्यों को निम्नलिखित में से चुना जाना चाहिए:

1. उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश या एक के रूप में नियुक्त होने के योग्य।
2. एक व्यक्ति जिसे सरकार के वित्त और खातों का विशेष ज्ञान है।
3. एक व्यक्ति जिसे वित्तीय मामलों और प्रशासन में व्यापक अनुभव है।
4. एक व्यक्ति जिसे अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान है

वित्त आयोग को निम्नलिखित मामलों पर भारत के राष्ट्रपति को सिफारिशें करने की आवश्यकता है:

1. केंद्र और राज्यों के बीच साझा किए जाने वाले करों की शुद्ध आय का वितरण, और इस तरह की आय के संबंधित शेयरों के राज्यों के बीच आवंटन।
2. केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत (अर्थात, भारत की संचित निधि से)।
3. राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों के अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय।
4. सुदृढ़ वित्त के हित में राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित कोई अन्य मामला।

Q. 124) वस्तु एवं सेवा कर परिषद (Goods and Services Tax Council) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए::

1. अनुच्छेद 279-ए भारत के राष्ट्रपति को जीएसटी परिषद का गठन करने का अधिकार देता है।
2. परिषद का प्रत्येक निर्णय बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भारित मतों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से लिया जाता है।
3. जीएसटी परिषद की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम परिषद के कुल सदस्यों की संख्या का आधा है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2
c) केवल 3
d) केवल 1 और 3

Q. 124) Solution (d)

2016 के 101वें संशोधन अधिनियम ने देश में एक नई कर व्यवस्था (यानी वस्तु और सेवा कर - जीएसटी) की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त किया।

संशोधन ने संविधान में एक नया अनुच्छेद 279-ए जोड़ा गया। इस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को एक आदेश द्वारा जीएसटी परिषद का गठन करने का अधिकार दिया। तदनुसार, राष्ट्रपति ने 2016 में आदेश जारी किया और परिषद का गठन किया।

परिषद के निर्णय उसकी बैठकों में लिए जाते हैं। परिषद के सदस्यों की कुल संख्या का आधा हिस्सा बैठक आयोजित करने के लिए गणपूर्ति है। परिषद का प्रत्येक निर्णय बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भारित मतों के कम से कम तीन-चौथाई बहुमत से लिया जाना है। निर्णय निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार लिया जाता है:

1. केंद्र सरकार के वोट का भार उस बैठक में डाले गए कुल वोटों का एक तिहाई होगा।
2. सभी राज्य सरकारों के संयुक्त मतों का भार उस बैठक में डाले गए कुल मतों के दो-तिहाई के बराबर होगा।

Q. 125) भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत के संविधान के भाग XVIII में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी का प्रावधान है।
2. वह छह साल की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, तक पद धारण करता है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 125) Solution (d)

मूल रूप से, भारत के संविधान में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

1956 के सातवें संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान के भाग XVII में एक नया अनुच्छेद 350-बी जोड़ा गया।

इस अनुच्छेद में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

1. भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी होना चाहिए। उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना है।
2. यह विशेष अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह संविधान के तहत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करे।

संविधान भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी को हटाने के लिए योग्यता, कार्यकाल, वेतन और भत्ते, सेवा शर्तों और प्रक्रिया को निर्दिष्ट नहीं करता है।

Q. 126) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. कैग छह साल की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, तक पद धारण करता है।
2. CAG का वेतन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होता है।
3. भारत के संविधान को बनाए रखना CAG का कर्तव्य है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3

Q. 126) Solution (c)

भारत का संविधान (अनुच्छेद 148) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) के एक स्वतंत्र पद का प्रावधान करता है।

वह छह वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, तक पद धारण करता है। वह किसी भी समय राष्ट्रपति को त्याग पत्र संबोधित कर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा उसी आधार पर और उसी तरह से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में हटाया जा सकता है।

कैग (CAG) की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उनका वेतन और अन्य सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं। उनका वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर है। उनकी नियुक्ति के बाद न तो उनके वेतन और न ही अनुपस्थिति की छुट्टी, पेंशन या सेवानिवृत्ति की आयु के संबंध में उनके अधिकारों में उनके अहित में परिवर्तन किया जा सकता है।

कैग (CAG) जनता की जेब का संरक्षक है और केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करता है। उनका कर्तव्य वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में भारत के संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है। वह भारत में सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली की एक कड़ी है; अन्य सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग और संघ लोक सेवा आयोग हैं।

Q. 127) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. कैग (CAG) भारत की संचित निधि से धन के मुद्दे पर नियंत्रण रखता है।
2. कैग (CAG) प्रत्येक राज्य के आकस्मिक निधि और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक खाते से सभी व्यय का लेखा-जोखा करता है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

a) केवल 1

b) केवल 2

c) दोनों 1 और 2

d) न तो 1 और न ही 2

Q. 127) Solution (b)

संसद और संविधान द्वारा निर्धारित कैग (CAG) के कर्तव्य और कार्य हैं:

- वह भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की समेकित निधि और एक विधान सभा वाले प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश की समेकित निधि से सभी व्यय से संबंधित लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है।
- वह भारत की आकस्मिकता निधि और भारत के सार्वजनिक खाते के साथ-साथ प्रत्येक राज्य की आकस्मिक निधि और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक खाते से सभी व्यय का लेखा-जोखा करता है।
- वह राष्ट्रपति को उस प्रपत्र के निर्धारण के संबंध में सलाह देता है जिसमें केंद्र और राज्यों के खाते रखे जाएंगे।
- वह किसी भी कर या शुल्क की शुद्ध आय का पता लगाता है और प्रमाणित करता है। उसका प्रमाणपत्र अंतिम है। 'शुद्ध आय' का अर्थ है कर या शुल्क की आय घटाकर संग्रह की लागत।
- वह संसद की लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक, मित्र और दार्शनिक के रूप में कार्य करते हैं।

कैग (CAG) तीन ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है- विनियोग खातों पर ऑडिट रिपोर्ट, वित्त खातों पर ऑडिट रिपोर्ट और सार्वजनिक उपक्रमों पर ऑडिट रिपोर्ट। राष्ट्रपति इन रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखता है। इसके बाद, लोक लेखा समिति उनकी जांच करती है और अपने निष्कर्षों को संसद को रिपोर्ट करती है।

भारत का संविधान सीएजी को नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में देखता है। हालांकि, व्यवहार में, कैग (CAG) केवल एक महालेखा परीक्षक की भूमिका निभा रहा है, नियंत्रक की नहीं। दूसरे शब्दों में, 'समेकित निधि से धन के मुद्दे पर सीएजी का कोई नियंत्रण नहीं है और कई विभाग सीएजी से विशिष्ट प्राधिकरण के बिना चेक जारी करके धन निकालने के लिए अधिकृत हैं, जो केवल लेखा परीक्षा चरण में संबंधित है जब व्यय पहले ही हो चुका है'।

Q. 128) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत का महान्यायवादी/अटार्नी जनरल संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में किए गए किसी भी संदर्भ में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है।
2. भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों और उनकी संयुक्त बैठक की कार्यवाही में बोलने, मतदान करने और भाग लेने का अधिकार है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

a) केवल 1

b) केवल 2

c) दोनों 1 और 2

d) न तो 1 और न ही 2

Q. 128) Solution (a)

संविधान (अनुच्छेद 76) ने भारत के लिए महान्यायवादी के कार्यालय के लिए प्रावधान किया है। वह देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी हैं।

भारत सरकार के मुख्य कानून अधिकारी के रूप में, एजी के कर्तव्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- ऐसे कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना, जो राष्ट्रपति द्वारा उसे भेजे जाते हैं।
- कानूनी चरित्र के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो राष्ट्रपति द्वारा उसे सौंपे जाते हैं।
- संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा उसे प्रदत्त कार्यों का निर्वहन करना।

राष्ट्रपति ने महान्यायवादी/अटार्नी जनरल को निम्नलिखित कर्तव्य सौंपे हैं:

- भारत सरकार की ओर से सभी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित होना जिसमें भारत सरकार का संबंध है।
- संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में किए गए किसी भी संदर्भ में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना।
- किसी भी मामले में, जिसमें भारत सरकार का संबंध है, किसी भी उच्च न्यायालय में (जब भारत सरकार द्वारा आवश्यक हो) उपस्थित होना।

अपने आधिकारिक कर्तव्यों के प्रदर्शन में, महान्यायवादी को भारत के क्षेत्र में सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार है। इसके अलावा, उसे संसद के दोनों सदनों या उनकी संयुक्त बैठक और संसद की किसी भी समिति की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, जिसमें उसे सदस्य नामित किया जा सकता है, लेकिन वोट देने के अधिकार के बिना। वह उन सभी विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का आनंद लेता है जो एक संसद सदस्य के लिए उपलब्ध हैं।

Q. 129) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के सॉलिसिटर जनरल के पद का प्रावधान है।
2. भारत के सॉलिसिटर जनरल को वे सभी विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त हैं जो एक संसद सदस्य के लिए उपलब्ध हैं।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

a) केवल 1

b) केवल 2

c) दोनों 1 और 2

d) न तो 1 और न ही 2

Q. 129) Solution (d)

महान्यायवादी/अटार्नी जनरल (एजी) के अलावा, भारत सरकार के अन्य विधि अधिकारी हैं। वे भारत के सॉलिसिटर जनरल और भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल हैं।

वे एजी को उसकी आधिकारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहायता करते हैं।

केवल एजी का पद संविधान द्वारा निर्मित है। दूसरे शब्दों में, अनुच्छेद 76 में सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का उल्लेख नहीं है।

प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा तीन साल की अवधि के लिए सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है।

भारत के सॉलिसिटर जनरल को कोई संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त नहीं हैं।

Q.130) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. राज्य के महाधिवक्ता/सालिसिटर जनरल का पद भारत के महाधिवक्ता के कार्यालय से मेल खाता है।
2. महाधिवक्ता/सालिसिटर जनरल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

a) केवल 1

b) केवल 2

c) दोनों 1 और 2

d) न तो 1 और न ही 2

Q. 130) Solution (d)

संविधान (अनुच्छेद 165) ने राज्यों के लिए महाधिवक्ता/सालिसिटर जनरल के पद की व्यवस्था की है। वह राज्य के सर्वोच्च कानून अधिकारी हैं। इस प्रकार वह भारत के महान्यायवादी से मेल खाता है।

महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो। दूसरे शब्दों में, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए और दस साल तक न्यायिक पद पर रहना चाहिए या दस साल तक उच्च न्यायालय का वकील होना चाहिए।

वह राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त पद धारण करता है। परंपरागत रूप से, वह इस्तीफा दे देता है जब सरकार (मंत्रिपरिषद) इस्तीफा दे देती है या उसे बदल दिया जाता है, क्योंकि उसे उसकी सलाह पर नियुक्त किया जाता है।

राज्य में सरकार के मुख्य विधि अधिकारी के रूप में, महाधिवक्ता के कर्तव्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- राज्य सरकार को ऐसे कानूनी मामलों पर सलाह देना जो राज्यपाल द्वारा उसे भेजे जाते हैं।
- कानूनी चरित्र के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो राज्यपाल द्वारा उसे सौंपे जाते हैं।
- संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा उसे प्रदत्त कार्यों का निर्वहन करना।

Q. 131) निम्नलिखित में से कौन-सा/से संवैधानिक निकाय नहीं है/हैं?

1. राज्य लोक सेवा आयोग
2. अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग
3. राज्य सूचना आयोग
4. अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 3 और 4
d) केवल 1 और 4

Q. 131) Solution (b)

1. राज्य लोक सेवा आयोग:

- यह एक संवैधानिक निकाय है। भारत के संविधान के भाग XIV में अनुच्छेद 315 से 323 में भारत संघ के लिए लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान है।
- संविधान के अनुच्छेदों के समान सेट (अर्थात, भाग XIV में 315 से 323) लोक सेवा आयोग की संरचना, नियुक्ति और सदस्यों को हटाने, शक्ति और कार्यों और स्वतंत्रता से संबंधित हैं।
- प्रत्येक राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करने और अनुशासनात्मक मामलों पर राज्यपाल को सलाह देने के लिए जिम्मेदार है।

2. अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग:

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) की स्थापना की। इस प्रकार यह एक वैधानिक निकाय है।

आयोग के निम्नलिखित कार्य हैं::

- संघ और राज्यों के अधीन अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।
- संविधान और संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा अधिनियमित कानूनों में प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों के कामकाज की निगरानी करना।
- केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण के लिए रक्षोपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करना।
- अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करें और ऐसे मामलों को उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ उठाएं।
- अल्पसंख्यकों के प्रति किसी भी प्रकार के भेदभाव से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का अध्ययन कराना और उन्हें दूर करने के उपायों की सिफारिश करना।

3. राज्य सूचना आयोग:

- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग के गठन का प्रावधान करता है।
- राज्य सूचना आयोग एक उच्चाधिकार प्राप्त स्वतंत्र निकाय है जो अन्य बातों के साथ-साथ इससे की गई शिकायतों को देखता है और अपीलों का निर्णय करता है।
- यह संबंधित राज्य सरकार के तहत कार्यालयों, वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि से संबंधित शिकायतों और अपीलों पर विचार करता है।

4. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (STs)

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (STs) इस अर्थ में एक संवैधानिक निकाय है कि यह सीधे संविधान के अनुच्छेद 338-ए द्वारा स्थापित किया गया है।

आयोग के कार्य हैं:

- अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक और अन्य कानूनी सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करना और उनके कामकाज का मूल्यांकन करना;
- अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना;
- अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देना और संघ या राज्य के तहत उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना;
- राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से और ऐसे अन्य समयों पर प्रस्तुत करना जो वह उचित समझे, उन रक्षोपायों के कार्यकरण पर रिपोर्ट देना।

Q. 132) नीति आयोग (NITI Aayog) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह एक संविधानेत्तर निकाय है।
2. राज्यों के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल नीति आयोग की संचालन परिषद के सदस्य हैं।
3. नीति आयोग के उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3

Q. 132) Solution (c)

नीति आयोग भारत सरकार की प्रमुख नीति 'थिंक टैंक' है, जो दिशात्मक और नीतिगत इनपुट दोनों प्रदान करता है। भारत सरकार के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक नीतियां और कार्यक्रम तैयार करते समय, नीति आयोग केंद्र और राज्यों को प्रासंगिक तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है।

नीति आयोग, योजना आयोग की तरह, भारत सरकार (यानी, केंद्रीय मंत्रिमंडल) के एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था। इसलिए, यह न तो एक संवैधानिक निकाय है और न ही एक वैधानिक निकाय है। दूसरे शब्दों में, यह एक गैर-संवैधानिक या संविधानेत्तर निकाय (अर्थात, संविधान द्वारा निर्मित नहीं) और एक गैर-सांविधिक निकाय (संसद के अधिनियम द्वारा निर्मित नहीं) है।

नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधायिकाओं के साथ केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री (यानी, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू और कश्मीर) और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल हैं।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति भारत के प्रधान मंत्री द्वारा की जाती है। उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है।

Q. 133) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अध्यक्ष भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए।
2. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक समिति की सिफारिशों पर की जाती है।
3. आयोग को उस तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के बाद किसी भी मामले की जांच करने का अधिकार नहीं है, जिस दिन मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कार्य किया गया था।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

a) केवल 1 और 2

b) केवल 2 और 3

c) केवल 3

d) 1, 2 और 3

Q. 133) Solution (c)

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक (और संवैधानिक नहीं) निकाय है। इसकी स्थापना 1993 में संसद द्वारा अधिनियमित एक कानून, अर्थात् मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत की गई थी।

नियुक्ति:

- आयोग एक बहु-सदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और पांच सदस्य होते हैं।
- अध्यक्ष भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए और सदस्य सर्वोच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और तीन व्यक्ति होने चाहिए (जिनमें से कम से कम एक महिला होनी चाहिए) मानवाधिकारों के संबंध में ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए।
- इन पूर्णकालिक सदस्यों के अलावा, आयोग में सात पदेन सदस्य भी होते हैं- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त।
- अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा छह सदस्यीय समिति की सिफारिशों पर की जाती है जिसमें प्रधान मंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति,संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होते हैं।
- इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के एक मौजूदा मुख्य न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद ही नियुक्त किया जा सकता है।

आयोग को उस तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के बाद किसी भी मामले की जांच करने का अधिकार नहीं है, जिस दिन मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कार्य किया गया था। दूसरे शब्दों में, यह किसी मामले को उसके घटित होने के एक वर्ष के भीतर जांच कर सकता है।

Q. 134) केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. आयोग के पास उचित आधार होने पर कार्यालयों, वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित शिकायतों और अपीलों की जांच करने का अधिकार है।
2. मुख्य सूचना आयुक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए या जब तक वे 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते, जो भी पहले हो, पद धारण करते हैं।
3. राज्य सभा में विपक्ष का नेता उस समिति का सदस्य होता है जो राष्ट्रपति के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति की सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

a) केवल 1 और 2

b) केवल 2 और 3

c) केवल 1 और 3

d) 1, 2 और 3

Q. 134) Solution (a)

केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 2005 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। इसका गठन सूचना का अधिकार अधिनियम (2005) के प्रावधानों के तहत एक आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से किया गया था।

केंद्रीय सूचना आयोग एक उच्च अधिकार प्राप्त स्वतंत्र निकाय है जो अन्य बातों के साथ-साथ की गई शिकायतों को देखता है और अपीलों का निर्णय करता है। यह केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के तहत कार्यालयों, वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि से संबंधित शिकायतों और अपीलों पर विचार करता है। उचित आधार होने पर आयोग किसी भी मामले में जांच का आदेश दे सकता है (स्व-प्रेरणा शक्ति)।

आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और दस से अधिक सूचना आयुक्त नहीं होते हैं। आयोग, जब शुरू में गठित किया गया था, में मुख्य सूचना आयुक्त सहित पांच आयुक्त थे।

उन्हें राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है जिसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधान मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधान मंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं।

मुख्य सूचना आयुक्त और एक सूचना आयुक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए या जब तक वे 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते, जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे। वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं हैं।

Q. 135) केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह न तो संवैधानिक निकाय है और न ही सांविधिक निकाय है।
2. यह उन शिकायतों को देखता है जिन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अपराध घोषित किया गया है।
3. केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, तक पद धारण करता है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

a) केवल 1 और 2

b) केवल 2

c) केवल 3

d) केवल 1 और 3

Q. 135) Solution (b)

केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मुख्य एजेंसी है। इसकी स्थापना 1964 में केंद्र सरकार के एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा की गई थी।

इसकी स्थापना की सिफारिश भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति द्वारा की गई थी।

मूल रूप से सीवीसी न तो एक संवैधानिक निकाय था और न ही एक सांविधिक निकाय। बाद में, 2003 में, संसद ने केंद्रीय सतर्कता आयोग को वैधानिक दर्जा प्रदान करने वाला एक अधिनियम पारित किया।

केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किए गए एक संदर्भ पर पूछताछ या जांच या निरीक्षण का संचालन करना है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि एक लोक सेवक केंद्र सरकार या उसके अधिकारियों का कर्मचारी है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अपराध किया गया है।

केंद्रीय सतर्कता आयोग एक बहु-सदस्यीय निकाय है जिसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (अध्यक्ष) होता है और दो से अधिक सतर्कता आयुक्त नहीं होते हैं।

उन्हें राष्ट्रपति द्वारा अपने हाथ के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है और तीन सदस्यीय समिति की सिफारिश पर प्रधान मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में प्रधान मंत्री की सिफारिश पर मुहर लगाई जाती है।

वे चार साल की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, तक पद धारण करते हैं। अपने कार्यकाल के बाद, वे केंद्र या राज्य सरकार के तहत आगामी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं।

Q. 136) केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. यह गृह मंत्रालय के तहत काम करता है।
2. सीबीआई भ्रष्टाचार के अपराध, आर्थिक अपराध, आतंकवाद और गंभीर और संगठित अपराध की जांच करती है।
3. यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 से अपनी शक्तियाँ प्राप्त करता है।

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

a) केवल 1 और 2

b) केवल 2

c) केवल 3

d) 1, 2 और 3

Q. 136) Solution (c)

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी। बाद में, इसे कार्मिक मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया और अब इसे एक संलग्न कार्यालय का दर्जा प्राप्त है।

भ्रष्टाचार की रोकथाम पर संथानम समिति (1962-1964) द्वारा सीबीआई की स्थापना की सिफारिश की गई थी।

सीबीआई एक सांविधिक निकाय नहीं है। यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 से अपनी शक्तियाँ प्राप्त करता है।

सीबीआई केंद्र सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है। यह भ्रष्टाचार की रोकथाम और प्रशासन में सत्यनिष्ठा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह केंद्रीय सतर्कता आयोग और लोकपाल को भी सहायता प्रदान करता है।

सीबीआई आतंकवाद के अलावा भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध और गंभीर और संगठित अपराध के अपराध की जांच करती है।

एनआईए (NIA) का गठन 2008 में मुंबई आतंकवादी हमले के बाद मुख्य रूप से आतंकवादी हमलों की घटनाओं, आतंकवाद के वित्तपोषण और अन्य आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच के लिए किया गया है।

Q. 137) लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में भारत के प्रधान मंत्री शामिल हैं।
2. लोकपाल के पास किसी भी लोक सेवक के खिलाफ कार्रवाई करने की स्वत: संज्ञान की शक्ति है।
3. सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्थानों को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा गया है।

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

a) केवल 1 और 2

b) केवल 2

c) केवल 3

d) केवल 1 और 3

Q. 137) Solution (d)

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- यह केंद्र में लोकपाल की संस्था और राज्य के स्तर पर लोकायुक्त की स्थापना करना चाहता है और इस प्रकार केंद्र और राज्यों दोनों में राष्ट्र के लिए एक समान सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी रोड मैप प्रदान करना चाहता है। लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में प्रधान मंत्री, मंत्री, संसद सदस्य और समूह ए, बी, सी और डी के अधिकारी और केंद्र सरकार के अधिकारी शामिल हैं।
- लोकपाल में एक अध्यक्ष होगा जिसमें अधिकतम 8 सदस्य होंगे जिनमें से 50% न्यायिक सदस्य होंगे।
- लोकपाल के 50% सदस्य एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और महिलाओं में से होंगे।

- इसमें भ्रष्ट तरीकों से अर्जित लोक सेवकों की संपत्ति की कुर्की और जब्ती के प्रावधान शामिल हैं, भले ही अभियोजन लंबित हो।
- यह स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित करता है। प्रारंभिक जांच के लिए, यह तीन महीने के लिए तीन महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। जांच के लिए यह छह महीने का होता है जिसे एक बार में छह महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। परीक्षण के लिए, यह एक वर्ष है जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और इसे प्राप्त करने के लिए, विशेष अदालतें स्थापित की जानी हैं।
- सरकार द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से वित्तपोषित संस्थान लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में हैं, लेकिन सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्थानों को बाहर रखा गया है।
- यह ईमानदार और न्यायसंगत लोक सेवकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है।
- लोकपाल को सरकार या सक्षम प्राधिकारी के स्थान पर लोक सेवकों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने की शक्ति प्रदान की गई।

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की कमियां निम्नलिखित हैं:

- लोकपाल किसी भी लोक सेवक के खिलाफ स्वप्रेरणा से कार्यवाही नहीं कर सकता।
- सार के बजाय शिकायत के रूप पर जोर।
- लोक सेवकों के खिलाफ झूठी और तुच्छ शिकायतों के लिए भारी सजा लोकपाल को शिकायत दर्ज करने से रोक सकती है।
- बेनामी शिकायतों की अनुमति नहीं है - केवल सादे कागज पर शिकायत नहीं कर सकते हैं और इसे सहायक दस्तावेजों के साथ एक बॉक्स में छोड़ सकते हैं।
- लोक सेवक को कानूनी सहायता, जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है।
- शिकायत दर्ज करने के लिए 7 वर्ष की सीमा अवधि।
- पीएम के खिलाफ शिकायतों (non-transparent procedure) से निपटने के लिए बहुत ही गैर-पारदर्शी प्रक्रिया

Q. 138) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. प्रधानमंत्री एनडीएमए (NDMA) के पदेन अध्यक्ष होते हैं
2. यह केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है।
3. यह आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत के न्यूनतम मानक प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देशों की सिफारिश करता है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

a) केवल 1 और 2

b) केवल 1 और 3

c) केवल 2 और 3

d) 1, 2 और 3

Q. 138) Solution (b)

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) देश में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय है। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है।

एनडीएमए की स्थापना इस दृष्टिकोण के साथ की गई थी: 'एक समग्र, सक्रिय, प्रौद्योगिकी संचालित और सतत विकास रणनीति द्वारा एक सुरक्षित और आपदा प्रतिरोधी भारत का निर्माण करना जिसमें सभी हितधारक शामिल हों और रोकथाम, तैयारी और शमन की संस्कृति को बढ़ावा दें।

एनडीएमए में एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं, जो नौ से अधिक नहीं होते हैं। प्रधानमंत्री एनडीएमए के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अन्य सदस्यों को एनडीएमए के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। एनडीएमए के अध्यक्ष सदस्यों में से एक को एनडीएमए के उपाध्यक्ष के रूप में नामित करते हैं। उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है जबकि अन्य सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है।

एनडीएमए निम्नलिखित कार्य करता है:

- यह आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत के न्यूनतम मानक प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देशों की सिफारिश करता है।
- यह अनुशंसा करता है, गंभीर परिमाण की आपदाओं के मामलों में, ऋणों की अदायगी में राहत या ऐसी आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को रियायती शर्तों पर नए ऋण प्रदान करना।
- यह राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDMA) के सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का प्रयोग करता है।
- इस बल का गठन किसी खतरनाक आपदा की स्थिति या आपदा के लिए विशेषज्ञ प्रतिक्रिया के उद्देश्य से किया गया है।
- यह संबंधित विभाग या प्राधिकरण को किसी भी खतरनाक आपदा की स्थिति या आपदा में बचाव या राहत के लिए प्रावधानों या सामग्रियों की आपातकालीन खरीद करने के लिए अधिकृत करता है। ऐसे मामले में, निविदाओं को आमंत्रित करने की आवश्यकता वाली मानक प्रक्रिया को माफ कर दिया गया माना जाता है।
- यह अपनी गतिविधियों पर एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है और इसे केंद्र सरकार को प्रस्तुत करता है। केंद्र सरकार इसे संसद के दोनों सदनों के सामने रखवाती है।

Q. 139) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. अनुच्छेद 323 ए के तहत ट्रिब्यूनल/ न्यायाधिकरण संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा उनकी विधायी क्षमता के भीतर आने वाले मामलों के संबंध में स्थापित किए जा सकते हैं।
2. अनुच्छेद 323 बी केवल लोक सेवा मामलों के लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना का प्रावधान करता है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

a) केवल 1

b) केवल 2

c) दोनों 1 और 2

d) न तो 1 और न ही 2

Q. 139) Solution (d)

मूल संविधान में न्यायाधिकरणों के संबंध में प्रावधान नहीं थे। 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम ने संविधान में एक नया भाग XIV-A जोड़ा।

यह भाग 'अधिकरण' के रूप में है और इसमें केवल दो अनुच्छेद शामिल हैं-अनुच्छेद 323ए प्रशासनिक ट्रिब्यूनल से संबंधित है और अनुच्छेद 323 बी अन्य मामलों के लिए ट्रिब्यूनल से संबंधित है।

अनुच्छेद 323 ए और 323 बी निम्नलिखित तीन पहलुओं में भिन्न हैं:

- जबकि अनुच्छेद 323 ए केवल सार्वजनिक सेवा मामलों के लिए अधिकरण की स्थापना पर विचार करता है, अनुच्छेद 323 बी कुछ अन्य मामलों के लिए अधिकरण की स्थापना पर विचार करता है।
- जबकि अनुच्छेद 323 ए के तहत अधिकरण केवल संसद द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं, अनुच्छेद 323 बी के तहत अधिकरण संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों द्वारा उनकी विधायी क्षमता के भीतर आने वाले मामलों के संबंध में स्थापित किए जा सकते हैं।
- अनुच्छेद 323 ए के तहत, केंद्र के लिए केवल एक और प्रत्येक राज्य या दो या अधिक राज्यों के लिए एक अधिकरण स्थापित किया जा सकता है। अधिकरण के पदानुक्रम का कोई सवाल ही नहीं है, जबकि अनुच्छेद 323 बी के तहत अधिकरण का एक पदानुक्रम बनाया जा सकता है।

Q.140) सहकारी संघवाद (cooperative federalism) के लक्ष्य को साकार करने और भारत में सुशासन को सक्षम करने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्थान का गठन किया गया है?

a) लोकपाल और लोकायुक्त

b) चुनाव आयोग

c) केंद्रीय सतर्कता आयोग

d) नीति आयोग

Q. 140) Solution (d)

नीति आयोग का गठन सहकारी संघवाद के महत्वपूर्ण लक्ष्य को साकार करने और भारत में सुशासन को सक्षम करने के लिए, एक मजबूत राष्ट्र बनाने वाले मजबूत राज्यों के निर्माण के लिए किया गया है। वास्तव में संघीय राज्य में, कई उद्देश्यों को प्राप्त किया जाना चाहिए जो पूरे देश में राजनीतिक प्रभाव डाल सकते हैं। किसी भी संघीय सरकार के लिए राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग के बिना राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करना असंभव है। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम करें।

सहकारी संघवाद की दो प्रमुख विशेषताएं या पहलू हैं:

- केंद्र और राज्यों द्वारा राष्ट्रीय विकास एजेंडा पर संयुक्त रूप से ध्यान केंद्रित करना; तथा
- केंद्रीय मंत्रालयों के साथ राज्य के दृष्टिकोण की वकालत।

इसे ध्यान में रखते हुए, नीति आयोग को राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों की एक साझा दृष्टि विकसित करने का कार्य सौंपा गया है। इन प्राथमिकताओं को राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करना चाहिए और राज्यों को निरंतर आधार पर संरचित समर्थन के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना चाहिए। नीति आयोग को राज्यों को ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएँ तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करने में मदद करनी चाहिए और सरकार के उच्च स्तरों पर इन्हें उत्तरोत्तर एकत्रित करना चाहिए। इसका उद्देश्य उस चरण से प्रगति करना है जब केंद्र ने वास्तव में संघीय सरकार के लिए विकास नीतियों का फैसला किया, जिसमें राज्य योजना प्रक्रिया में समान हितधारक हैं।

Q. 141) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत के संविधान का भाग XX कुछ राज्यों के लिए अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान प्रदान करता है।
2. अनुच्छेद 371-ए के अनुसार, संसद राज्य की विधान सभा की सहमति के बिना असम में भूमि और उसके संसाधनों के स्वामित्व और हस्तांतरण में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

a) केवल 1

b) केवल 2

c) दोनों 1 और 2

d) न तो 1 और न ही 2

Q. 141) Solution (d)

भारत के संविधान का भाग XXI एक देश और राज्यों के संघ के रूप में भारत के संविधान से संबंधित कानूनों का संकलन है जिससे इसका गठन हुआ है। संविधान के इस भाग में कुछ राज्यों के लिए अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधानों पर अनुच्छेद शामिल हैं। भाग XXI भारतीय संघ के अन्य राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधानों को परिभाषित करता है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371-ए नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान करता है।

निम्नलिखित मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम नागालैंड पर तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि राज्य विधान सभा ऐसा निर्णय नहीं लेती:

- नागाओं की धार्मिक या सामाजिक प्रथाएं;
- नागा प्रथागत कानून और प्रक्रिया;
- नागा प्रथागत कानून के अनुसार निर्णयों को शामिल करते हुए दीवानी और आपराधिक न्याय का प्रशासन; तथा

- भूमि और उसके संसाधनों का स्वामित्व और हस्तांतरण।

राज्यपाल को यह सुनिश्चित करना होता है कि केंद्र सरकार द्वारा किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रदान किया गया धन उस उद्देश्य से संबंधित अनुदान की मांग में शामिल है, न कि राज्य विधानसभा में पेश की गई किसी अन्य मांग में।

अनुच्छेद में कहा गया है कि जब तक शत्रुतापूर्ण नागाओं के कारण आंतरिक अशांति जारी रहेगी, तब तक नागालैंड के राज्यपाल के पास राज्य में कानून और व्यवस्था के लिए विशेष जिम्मेदारी होगी। इस जिम्मेदारी के निर्वहन में राज्यपाल, मंत्रिपरिषद से परामर्श करने के बाद, अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करता है और उसका निर्णय अंतिम होता है।

Q. 142) भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371-एफ किस राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान प्रदान करता है:

a) आंध्र प्रदेश

b) तेलंगाना

c) सिक्किम

d) मणिपुर

Q. 142) Solution (c)

1975 के 36वें संविधान संशोधन अधिनियम ने सिक्किम को भारतीय संघ का एक पूर्ण राज्य बना दिया। इसमें सिक्किम के संबंध में विशेष प्रावधानों वाला एक नया अनुच्छेद 371-एफ शामिल था। ये इस प्रकार हैं:

1. सिक्किम विधान सभा में कम से कम 30 सदस्य होने चाहिए।
2. लोकसभा में सिक्किम को एक सीट आवंटित की जाती है और सिक्किम एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बनाता है।
3. सिक्किम की आबादी के विभिन्न वर्गों के अधिकारों और हितों की रक्षा के उद्देश्य से, संसद को निम्नलिखित के लिए प्रावधान करने का अधिकार है:
    1. सिक्किम विधान सभा में सीटों की संख्या जो ऐसे वर्गों से संबंधित उम्मीदवारों द्वारा भरी जा सकती है; तथा
    2. विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन जहां से ऐसे वर्गों के उम्मीदवार अकेले विधानसभा के चुनाव के लिए खड़े हो सकते हैं।
4. सिक्किम की आबादी के विभिन्न वर्गों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति सुनिश्चित करने के लिए शांति और एक समान व्यवस्था के लिए राज्यपाल की विशेष जिम्मेदारी होगी। इस उत्तरदायित्व के निर्वहन में राज्यपाल अपने विवेक से राष्ट्रपति द्वारा जारी निर्देशों के अधीन कार्य करेगा।
5. राष्ट्रपति सिक्किम में भारतीय संघ के राज्य में लागू किसी भी कानून को (प्रतिबंधों या संशोधनों के साथ) बढ़ा सकते हैं।

Q. 143) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. अनुच्छेद 371-जी में प्रावधान है कि मिजोरम विधान सभा में कम से कम 20 सदस्य होने चाहिए।
2. अनुच्छेद 371-एच में प्रावधान है कि अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य होने चाहिए।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

a) केवल 1

b) केवल 2

c) दोनों 1 और 2

d) न तो 1 और न ही 2

Q. 143) Solution (b)

अनुच्छेद 371-जी मिजोरम के लिए निम्नलिखित विशेष प्रावधानों को निर्दिष्ट करता है:

1. निम्नलिखित मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम मिजोरम पर तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि राज्य विधान सभा ऐसा निर्णय न ले:
    1. मिज़ो की धार्मिक या सामाजिक प्रथाएं;
    2. मिजो प्रथागत कानून और प्रक्रिया;
    3. दीवानी और फौजदारी न्याय का प्रशासन जिसमें मिजो प्रथागत कानून के अनुसार निर्णय शामिल हैं; और (iv) भूमि का स्वामित्व और हस्तांतरण।
2. मिजोरम विधान सभा में कम से कम 40 सदस्य होने चाहिए।

अनुच्छेद 371-एच के तहत अरुणाचल प्रदेश के लिए निम्नलिखित विशेष प्रावधान किए गए हैं:

1. अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के पास राज्य में कानून और व्यवस्था के लिए विशेष जिम्मेदारी होगी। इस जिम्मेदारी के निर्वहन में राज्यपाल, मंत्रिपरिषद से परामर्श करने के बाद, अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करता है और उसका निर्णय अंतिम होता है। राष्ट्रपति के ऐसा निर्देश देने पर राज्यपाल का यह विशेष उत्तरदायित्व समाप्त हो जाएगा।
2. अरुणाचल प्रदेश विधान सभा में कम से कम 30 सदस्य होने चाहिए।

Q. 144) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारतीय संविधान का भाग VIII केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है।
2. एक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक राष्ट्रपति का एजेंट होता है, न कि राज्य का मुखिया।
3. संसद सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्य सूची सहित तीन सूचियों में से किसी भी विषय पर कानून बना सकती है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

a) केवल 1 और 2

b) केवल 2 और 3

c) केवल 1 और 3

d) 1, 2 और 3

Q. 144) Solution (d)

संविधान के भाग आठ में अनुच्छेद 239 से 241 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। भले ही सभी केंद्र शासित प्रदेश एक श्रेणी के हैं, लेकिन उनकी प्रशासनिक व्यवस्था में एकरूपता नहीं है।

प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा उसके द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से कार्य करता है। एक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक राष्ट्रपति का एजेंट होता है न कि राज्यपाल की तरह राज्य का मुखिया।

राष्ट्रपति एक प्रशासक के पद को निर्दिष्ट कर सकता है; यह उपराज्यपाल या मुख्य आयुक्त या प्रशासक हो सकता है। वर्तमान में, यह दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के मामले में उपराज्यपाल और चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव और लक्षद्वीप के मामले में प्रशासक है।

राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक भी नियुक्त कर सकता है। उस क्षमता में, राज्यपाल को अपने मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रूप से कार्य करना होता है।

केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संसद तीन सूचियों (राज्य सूची सहित) के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। संसद की यह शक्ति पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू और कश्मीर तक भी फैली हुई है, जिनकी अपनी स्थानीय विधायिकाएँ हैं। इसका अर्थ यह है कि राज्य सूची के विषयों पर केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संसद की विधायी शक्ति उनके लिए स्थानीय विधायिका स्थापित करने के बाद भी अप्रभावित रहती है।

Q. 145) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. जम्मू और कश्मीर की विधान सभा सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है।
2. राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए नियम तभी बना सकते हैं जब विधानसभा निलंबित या विघटित हो।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

a) केवल 1

b) केवल 2

c) दोनों 1 और 2

d) न तो 1 और न ही 2

Q. 145) Solution (b)

जम्मू और कश्मीर की विधान सभा राज्य सूची (सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस को छोड़कर) और समवर्ती सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है।

राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए नियम तभी बना सकते हैं जब विधानसभा निलंबित या विघटित हो।

राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए विनियम में संसद के अधिनियम के समान ही बल और प्रभाव होता है और इन केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में संसद के किसी भी अधिनियम को निरस्त या संशोधित भी कर सकता है।

Q. 146) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी का अपना उच्च न्यायालय है।
2. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मद्रास उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में रखा गया है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

a) केवल 1

b) केवल 2

c) दोनों 1 और 2

d) न तो 1 और न ही 2

Q. 146) Solution (d)

संसद एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है या इसे आसन्न राज्य के उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में रख सकती है।

दिल्ली का अपना एक उच्च न्यायालय है (1966 से)। बॉम्बे हाईकोर्ट को केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव पर अधिकार क्षेत्र मिला है।

अंडमान और नोकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और पुडुचेरी को क्रमशः कोलकाता, पंजाब और हरियाणा, केरल और मद्रास उच्च न्यायालयों के अधीन रखा गया है।

जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के लिए सामान्य उच्च न्यायालय है।

संशोधन अधिनियम के माध्यम से लाए गए अनुच्छेद 230 के अनुसार, संसद कानून द्वारा किसी भी केंद्र शासित प्रदेश से उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा सकती है, या उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बाहर कर सकती है।

केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में इस शक्ति को संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत संघ सूची में प्रविष्टि 79 के रूप में शामिल करके केंद्र के लिए अनन्य बना दिया गया था। दूसरी ओर, संशोधन, अनुच्छेद 241 के माध्यम से, संसद को केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक उच्च न्यायालय का गठन करने या ऐसे क्षेत्र में किसी भी अदालत को उच्च न्यायालय घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है। केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित इस तरह के उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति राज्य के उच्च न्यायालय के समान होती है।

Q. 147) निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के रूप में नामित कुछ क्षेत्रों के लिए प्रशासन का प्रावधान करता है?

1. भाग XI
2. भाग X
3. पांचवी अनुसूची

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

a) केवल 1 और 2

b) केवल 2 और 3

c) केवल 1 और 3

d) 1, 2 और 3

Q. 147) Solution (c)

संविधान के भाग X में अनुच्छेद 244 में 'अनुसूचित क्षेत्रों' और 'जनजातीय क्षेत्रों' के रूप में नामित कुछ क्षेत्रों के लिए प्रशासन की एक विशेष प्रणाली की परिकल्पना की गई है।

संविधान की पांचवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के चार राज्यों को छोड़कर किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है।

दूसरी ओर, संविधान की छठी अनुसूची, चार उत्तर-पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है।

Q. 148) भारतीय संविधान की पांचवीं अनुसूची के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है।
2. संविधान की पांचवीं अनुसूची के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों में ही एक जनजाति सलाहकार परिषद की स्थापना की जा सकती है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

a) केवल 1

b) केवल 2

c) दोनों 1 और 2

d) न तो 1 और न ही 2

Q. 148) Solution (a)

पाँचवीं अनुसूची में निहित प्रशासन की विभिन्न विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- राष्ट्रपति को किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। वह अपने क्षेत्र को बढ़ा या घटा भी सकता है, उसकी सीमा रेखाओं में परिवर्तन कर सकता है, ऐसे पदनाम को रद्द कर सकता है या संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से किसी क्षेत्र पर इस तरह के पुन: पदनाम के लिए नए आदेश दे सकता है।
- अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य को अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति पर सलाह देने के लिए एक जनजाति सलाहकार परिषद की स्थापना करनी होती है। इसमें 20 सदस्य होते हैं, जिनमें से तीन-चौथाई राज्य विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होते हैं। इसी तरह की परिषद अनुसूचित जनजातियों वाले राज्य में भी स्थापित की जा सकती है, लेकिन अनुसूचित क्षेत्रों में नहीं, यदि राष्ट्रपति ऐसा निर्देश देते हैं।
- किसी राज्य की कार्यकारी शक्ति उसके अनुसूचित क्षेत्रों तक फैली हुई है। लेकिन ऐसे क्षेत्रों के संबंध में राज्यपाल की विशेष जिम्मेदारी होती है। उसे ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में, वार्षिक रूप से या जब भी राष्ट्रपति की आवश्यकता हो, राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। केंद्र की कार्यकारी शक्ति ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राज्यों को निर्देश देने तक फैली हुई है।
- राज्यपाल को यह निर्देश देने का अधिकार है कि संसद या राज्य विधायिका का कोई विशेष अधिनियम अनुसूचित क्षेत्र पर लागू न हो या निर्दिष्ट संशोधनों और अपवादों के साथ लागू न हो। वह जनजाति सलाहकार परिषद से परामर्श करके किसी अनुसूचित क्षेत्र की शांति और अच्छी सरकार के लिए नियम भी बना सकता है। इस तरह के विनियम अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनके बीच भूमि के हस्तांतरण को सीमित या प्रतिबंधित कर सकते हैं, अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को भूमि के आवंटन को विनियमित कर सकते हैं और अनुसूचित जनजातियों के संबंध में धन-उधार के व्यवसाय को विनियमित कर सकते हैं।

Q. 149) भारत के संविधान की छठी अनुसूची के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्र संबंधित राज्य के कार्यपालिका प्राधिकार से बाहर हैं।
2. राष्ट्रपति को असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों को स्वायत्त जिलों के रूप में गठित करने का अधिकार है।
3. प्रत्येक स्वायत्त जिले में एक जिला परिषद होती है जिसमें 30 सदस्य होते हैं, जिनमें से चार राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं और शेष 26 वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

a) केवल 1

b) केवल 1 और 2

c) केवल 3

d) 2 और 3

Q. 149) Solution (c)

छठी अनुसूची के तहत संविधान में चार उत्तर-पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान हैं।

चार राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में आदिवासी क्षेत्रों को स्वायत्त जिलों के रूप में गठित किया गया है। लेकिन, वे संबंधित राज्य के कार्यकारी प्राधिकरण के बाहर नहीं आते हैं।

राज्यपाल को स्वायत्त जिलों को व्यवस्थित और पुनर्गठित करने का अधिकार है। इस प्रकार, वह उनके क्षेत्रों को बढ़ा या घटा सकता है या उनके नाम बदल सकता है या उनकी सीमाओं को परिभाषित कर सकता है और इसी तरह।

यदि एक स्वायत्त जिले में विभिन्न जनजातियाँ हैं, तो राज्यपाल जिले को कई स्वायत्त क्षेत्रों में विभाजित कर सकता है।

प्रत्येक स्वायत्त जिले में एक जिला परिषद होती है जिसमें 30 सदस्य होते हैं, जिनमें से 4 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं और शेष 26 वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। निर्वाचित सदस्य 5 साल की अवधि के लिए पद धारण करते हैं (जब तक कि परिषद पहले भंग नहीं हो जाती) और मनोनीत सदस्य राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं।

Q.150) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. 1991 के 68वें संविधान संशोधन अधिनियम ने केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को एक विशेष दर्जा प्रदान किया।
2. केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में मंत्रिपरिषद की संख्या विधानसभा की कुल संख्या का बीस प्रतिशत तय की जाती है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 150) Solution (d)

1991 के 69वें संविधान संशोधन अधिनियम ने केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को एक विशेष दर्जा प्रदान किया, और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बदल दिया और दिल्ली के प्रशासक को लेफ्टिनेंट (लेफ्टिनेंट) गवर्नर के रूप में नामित किया।

इसने दिल्ली के लिए एक विधान सभा और एक मंत्रिपरिषद का गठन किया। पहले, दिल्ली में एक महानगर परिषद और एक कार्यकारी परिषद थी।

विधानसभा की ताकत 70 सदस्यों पर तय की जाती है, जो सीधे लोगों द्वारा चुने जाते हैं। चुनाव भारत के चुनाव आयोग द्वारा आयोजित किए जाते हैं।

विधानसभा राज्य सूची और समवर्ती सूची के सभी मामलों पर राज्य सूची के तीन मामलों, यानी सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर कानून बना सकती है। लेकिन, संसद के कानून विधानसभा द्वारा बनाए गए कानूनों पर प्रबल या अभिभावी होते हैं।

मंत्रिपरिषद की संख्या विधानसभा की कुल संख्या की दस प्रतिशत तय की जाती है, यानी सात-एक मुख्यमंत्री और छह अन्य मंत्री।

मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है (उपराज्यपाल द्वारा नहीं)। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से सभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

Q. 151) बलवंत राय मेहता समिति द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिशें दी गई हैं/हैं?

1. ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के प्रतिनिधियों का प्रत्यक्ष चुनाव।
2. पंचायत समिति को एक कार्यकारी निकाय होना चाहिए।
3. जिला परिषद को कार्यकारी निकाय के बजाय सलाहकारी और पर्यवेक्षी निकाय होना चाहिए।

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3

Q. 151) Solution (b)

जनवरी 1957 में, भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952) और राष्ट्रीय विस्तार सेवा (1953) के कामकाज की जांच करने और उनके बेहतर कामकाज के उपायों का सुझाव देने के लिए एक समिति नियुक्त की। इस समिति के अध्यक्ष बलवंत राय जी मेहता थे। समिति ने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और 'लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण' की योजना की स्थापना की सिफारिश की, जिसे अंततः पंचायती राज के रूप में जाना जाने लगा। इसके द्वारा की गई विशिष्ट सिफारिशें हैं:

1. त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना - ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। इन स्तरों को अप्रत्यक्ष चुनावों के माध्यम से व्यवस्थित रूप से जोड़ा जाना चाहिए।
2. प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ ग्राम पंचायत का गठन किया जाना चाहिए, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों के साथ पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन किया जाना चाहिए।
3. सभी नियोजन और विकास गतिविधियों को इन निकायों को सौंपा जाना चाहिए।
4. पंचायत समिति कार्यकारी निकाय होनी चाहिए जबकि जिला परिषद सलाहकार, समन्वय और पर्यवेक्षी निकाय होनी चाहिए।
5. जिला कलेक्टर को जिला परिषद का अध्यक्ष होना चाहिए।
6. इन लोकतांत्रिक निकायों को सत्ता और जिम्मेदारी का वास्तविक हस्तांतरण होना चाहिए।

7. इन निकायों को अपने कार्यों का निर्वहन करने और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त संसाधनों को स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

8. भविष्य में प्राधिकरण के और हस्तांतरण को प्रभावित करने के लिए एक प्रणाली विकसित की जानी चाहिए।

समिति की इन सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद ने जनवरी 1958 में स्वीकार कर लिया। परिषद ने एक भी कठोर पैटर्न या स्वरूप पर जोर नहीं दिया और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल अपने स्वयं के पैटर्न विकसित करने के लिए इसे राज्यों पर छोड़ दिया। लेकिन बुनियादी सिद्धांत और व्यापक बुनियादी सिद्धांत पूरे देश में एक जैसे होने चाहिए। राजस्थान पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य था।

Q. 152) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243-ओ पंचायतों के 29 कार्यात्मक मदों से संबंधित है।

2. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 को व्यावहारिक रूप दिया है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

a) केवल 1

b) केवल 2

c) दोनों 1 और 2

d) न तो 1 और न ही 2

Q. 152) Solution (d)

73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने भारत के संविधान में एक नया भाग-IX जोड़ा। यह भाग 'पंचायतों' के रूप में हकदार है और इसमें अनुच्छेद 243 से 243 ओ के प्रावधान शामिल हैं। इसके अलावा, अधिनियम ने संविधान में एक नई ग्यारहवीं अनुसूची भी जोड़ी है। इस अनुसूची में पंचायतों की 29 कार्यात्मक मदें शामिल हैं। यह अनुच्छेद 243-जी से संबंधित है।

अधिनियम ने संविधान के अनुच्छेद 40 को एक व्यावहारिक आकार दिया है जो कहता है कि, "राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।"

यह लेख राज्य के नीति निदेशक तत्वों का एक हिस्सा है। यह अधिनियम पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। इसने उन्हें संविधान के न्यायोचित भाग के दायरे में ला दिया है।

दूसरे शब्दों में, राज्य सरकारें अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नई पंचायती राज प्रणाली को अपनाने के लिए संवैधानिक दायित्व के अधीन हैं। नतीजतन, न तो पंचायतों का गठन और न ही नियमित अंतराल पर चुनाव कराना राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है।

Q. 153) 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यदि कोई व्यक्ति 25 वर्ष से कम आयु का है तो उसे पंचायत का सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
2. ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के सभी सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाएंगे।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 153) Solution (b)

73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार एक व्यक्ति को पंचायत के सदस्य के रूप में चुने जाने या सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा यदि वह इस प्रकार अयोग्य है:

a) संबंधित राज्य की विधायिका के चुनाव के उद्देश्य से उस समय लागू किसी भी कानून के तहत, या
b) राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के तहत।

तथापि, कोई भी व्यक्ति इस आधार पर अयोग्य नहीं होगा कि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है यदि उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। इसके अलावा, अयोग्यता के सभी प्रश्नों को राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्राधिकरण के पास भेजा जाएगा।

73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार, ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के सभी सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाएंगे। इसके अलावा, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से उनके निर्वाचित सदस्यों द्वारा और उनमें से किया जाएगा।

हालाँकि, ग्राम स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाएगा। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पंचायत के अध्यक्ष और पंचायत के अन्य सदस्यों को पंचायतों की बैठकों में मत देने का अधिकार होगा।

Q. 154) भारतीय संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पंचायतों के दायरे में आती है?

1. परिवार कल्याण
2. पुस्तकालयें
3. उच्च व्यावसायिक शिक्षा
4. सार्वजनिक वितरण प्रणाली

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

a) केवल 1, 2 और 3

b) केवल 2, 3 और 4

c) केवल 1, 2 और 4

d) केवल 1, 3 और 4

Q. 154) Solution (c)

ग्यारहवीं अनुसूची: इसमें पंचायतों के दायरे में रखे गए निम्नलिखित 29 कार्यात्मक मदें शामिल हैं:

1. कृषि, कृषि विस्तार सहित
2. भूमि सुधार, भूमि सुधारों का कार्यान्वयन, भूमि चकबंदी और मृदा संरक्षण
3. लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और वाटरशेड विकास
4. पशुपालन, डेयरी और मुर्गी पालन
5. मछली पालन
6. सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी
7. लघु वनोपज
8. खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों सहित लघु उद्योग
9. खादी, ग्राम एवं कुटीर उद्योग
10. ग्रामीण आवास
11. पीने का पानी
12. ईंधन और चारा
13. सड़कें, पुलिया, पुल, घाट, जलमार्ग और संचार के अन्य साधन
14. बिजली के वितरण सहित ग्रामीण विद्युतीकरण
15. गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत
16. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
17. प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों सहित शिक्षा
18. तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा
19. वयस्क और अनौपचारिक शिक्षा
20. पुस्तकालयें

21. सांस्कृतिक गतिविधियां
22. बाजार और मेले
23. अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और औषधालयों सहित स्वास्थ्य और स्वच्छता
24. परिवार कल्याण
25. महिला बाल विकास
26. विकलांग और मानसिक रूप से मंद लोगों के कल्याण सहित सामाजिक कल्याण
27. कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण
28. सार्वजनिक वितरण प्रणाली
29. सामुदायिक संपत्ति का रखरखाव।

Q. 155) निम्नलिखित में से कौन सा/से भारत के संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के अनिवार्य प्रावधान हैं/हैं?

1. पंचायती राज के तीनों स्तरों पर पंचायतों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों का आरक्षण।
2. पंचायती राज के तीन स्तरों पर पंचायतों में पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण।
3. पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करना।

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

a) केवल 1
b) केवल 1 और 2
c) केवल 3
d) 1, 2 और 3

Q. 155) Solution (a)

73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के प्रावधानों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है- अनिवार्य और स्वैच्छिक।अधिनियम के अनिवार्य (अनिवार्य या बाध्यकर) प्रावधानों को नई पंचायती राज व्यवस्था बनाने वाले राज्य कानूनों में शामिल करना होगा। दूसरी ओर, स्वैच्छिक प्रावधानों को राज्यों के विवेक पर शामिल किया जा सकता है। इस प्रकार अधिनियम के स्वैच्छिक प्रावधान नई पंचायती राज प्रणाली को अपनाते समय राज्यों के भौगोलिक, राजनीतिक-प्रशासनिक और अन्य जैसे स्थानीय कारकों को ध्यान में रखने के अधिकार को सुनिश्चित करते हैं।

अनिवार्य प्रावधान:

1. किसी गाँव या गाँवों के समूह में ग्राम सभा का संगठन।
2. ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की स्थापना।
3. ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की सभी सीटों पर सीधे चुनाव।
4. मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव।
5. प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए पंचायत के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के मतदान के अधिकार।
6. पंचायतों के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी।
7. तीनों स्तरों पर पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों (सदस्य और अध्यक्ष दोनों) का आरक्षण।
8. तीनों स्तरों पर पंचायतों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों (सदस्य और अध्यक्ष दोनों) का आरक्षण।
9. सभी स्तरों पर पंचायतों के लिए पांच साल का कार्यकाल तय करना और किसी भी पंचायत के अधिक्रमण की स्थिति में छह महीने के भीतर नए सिरे से चुनाव कराना।
10. पंचायतों के चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग की स्थापना।
11. पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए प्रत्येक पांच वर्ष के बाद एक राज्य वित्त आयोग का गठन।

स्वैच्छिक प्रावधान:

1. ग्राम सभा को ग्राम स्तर पर शक्तियाँ और कार्य प्रदान करना।
2. ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव के तरीके का निर्धारण।
3. जिला पंचायतों में मध्यवर्ती पंचायतों या राज्य में मध्यवर्ती पंचायत न होने की स्थिति में ग्राम पंचायतों के अध्यक्षों को प्रतिनिधित्व देना।
4. जिला पंचायतों में मध्यवर्ती पंचायतों के अध्यक्षों को प्रतिनिधित्व देना।
5. संसद के सदस्यों (दोनों सदनों) और राज्य विधायिका (दोनों सदनों) को उनके निर्वाचन क्षेत्रों के भीतर आने वाले विभिन्न स्तरों पर पंचायतों में प्रतिनिधित्व देना।
6. किसी भी स्तर पर पंचायतों में पिछड़े वर्गों के लिए सीटों (सदस्य और अध्यक्ष दोनों) का आरक्षण प्रदान करना।
7. पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करना (संक्षेप में, उन्हें स्वायत्त निकाय बनाना)।
8. आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करने के लिए पंचायतों को शक्तियों और जिम्मेदारियों का हस्तांतरण; और संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 कार्यों में से कुछ या सभी को करने के लिए।
9. पंचायतों को वित्तीय शक्तियाँ प्रदान करना, अर्थात उन्हें कर, शुल्क, टोल और फ़ीस लगाने, एकत्र करने और उचित करने के लिए अधिकृत करना।
10. एक पंचायत को राज्य सरकार द्वारा लगाए और एकत्र किए गए करों, शुल्कों, टोलों और फ़ीसों को सौंपना।

11. राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देना।
12. पंचायतों के सभी धन को जमा करने के लिए निधियों के गठन का प्रावधान।

Q. 156) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक पंचायतों द्वारा खातों के रखरखाव और ऐसे खातों की लेखा परीक्षा के संबंध में प्रावधान करते हैं।
2. राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा पंचायतों के सभी चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण और संचालन के लिए की जाती है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 156) Solution (d)

पंचायतों के खातों की लेखापरीक्षा: राज्य विधानमंडल पंचायतों द्वारा खातों के रखरखाव और ऐसे खातों की लेखा परीक्षा के संबंध में प्रावधान कर सकता है।

राज्य चुनाव आयोग:

- मतदाता सूची तैयार करने और पंचायतों के सभी चुनावों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य चुनाव आयोग में निहित होगा। इसमें एक राज्य चुनाव आयुक्त होता है जिसे राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- उनकी सेवा की शर्तें और पद का कार्यकाल भी राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाएगा। राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए निर्धारित तरीके और आधारों को छोड़कर उसे कार्यालय से नहीं हटाया जाएगा। उनकी नियुक्ति के बाद उनकी सेवा की शर्तों में उनके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
- राज्य विधायिका पंचायतों के चुनाव से संबंधित सभी मामलों के संबंध में प्रावधान कर सकती है।

Q. 157) 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह अधिनियम प्रत्येक नगरपालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान करता है।

2. विघटन होने की स्थिति में नगर पालिका के गठन के लिए नए चुनाव उसके विघटन की तारीख से छह महीने की अवधि की समाप्ति से पहले पूरे किए जाने चाहिए।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

a) केवल 1

b) केवल 2

c) दोनों 1 और 2

d) न तो 1 और न ही 2

Q. 157) Solution (b)

74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने भारत के संविधान में एक नया भाग IX-A जोड़ा। यह हिस्सा 'नगर पालिकाओं' के रूप में हकदार है और इसमें अनुच्छेद 243-पी से 243-जेडजी के प्रावधान शामिल हैं। इसके अलावा, अधिनियम ने संविधान में एक नई बारहवीं अनुसूची भी जोड़ी है। इस अनुसूची में नगर पालिकाओं के अठारह कार्यात्मक मदें शामिल हैं। यह अनुच्छेद 243-डब्ल्यू से संबंधित है।

इस अधिनियम ने नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। इसने उन्हें संविधान के न्यायोचित भाग के दायरे में ला दिया है। दूसरे शब्दों में, राज्य सरकारें अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नगर पालिकाओं की नई प्रणाली को अपनाने के लिए संवैधानिक दायित्व के अधीन हैं।

सीटों का आरक्षण: अधिनियम प्रत्येक नगरपालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी आबादी के अनुपात में नगरपालिका क्षेत्र में कुल आबादी के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। इसके अलावा, यह महिलाओं के लिए सीटों की कुल संख्या (एससी और एसटी से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सहित) के कम से कम एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान करता है।

राज्य विधायिका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं में अध्यक्षों के पदों के आरक्षण के तरीके का प्रावधान कर सकती है। यह पिछड़े वर्गों के पक्ष में किसी भी नगर पालिका या नगर पालिकाओं में अध्यक्षों के कार्यालयों में सीटों के आरक्षण के लिए कोई प्रावधान कर सकता है।

नगर पालिकाओं की अवधि: अधिनियम प्रत्येक नगरपालिका के लिए पांच साल के कार्यकाल का प्रावधान करता है। हालांकि, इसका कार्यकाल पूरा होने से पहले इसे भंग किया जा सकता है। इसके अलावा, नगरपालिका के गठन के लिए नए चुनाव (ए) पांच साल की अवधि की समाप्ति से पहले पूरा किया जाएगा; या (बी) विघटन के मामले में, इसके विघटन की तारीख से छह महीने की अवधि की समाप्ति से पहले।

लेकिन, जहां शेष अवधि (जिसके लिए भंग की गई नगरपालिका जारी रहेगी) छह महीने से कम है, ऐसी अवधि के लिए नई नगरपालिका के गठन के लिए कोई चुनाव कराना आवश्यक नहीं होगा।

इसके अलावा, एक नगरपालिका अपनी अवधि की समाप्ति से पहले एक नगर पालिका के विघटन पर गठित केवल उस शेष अवधि के लिए जारी रहेगी, जिसके लिए भंग की गई नगरपालिका जारी रहेगी यदि इसे भंग नहीं किया गया था। दूसरे शब्दों में, समय से पहले

विघटन के बाद पुनर्गठित नगरपालिका पांच साल की पूरी अवधि का लाभ नहीं लेती है, लेकिन शेष अवधि के लिए ही कार्यरत् में रहती है।

अधिनियम विघटन के संबंध में दो और प्रावधान भी करता है:

a. एक नगरपालिका को उसके विघटन से पहले सुनवाई का उचित अवसर दिया जाना चाहिए; तथा

b. वर्तमान में लागू किसी भी कानून में कोई भी संशोधन पांच साल की अवधि की समाप्ति से पहले नगरपालिका के विघटन का कारण नहीं बनेगा।

Q. 158) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारतीय संविधान का भाग XVIII राजभाषा से संबंधित है।
2. संसद की राजभाषा समिति में राज्यसभा से 20 और लोकसभा से 10 सदस्य शामिल हैं।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q. 158) Solution (d)

संविधान का भाग XVII अनुच्छेद 343 से 351 में आधिकारिक भाषा से संबंधित है। इसके प्रावधानों को चार प्रमुखों में विभाजित किया गया है-संघ की भाषा, क्षेत्रीय भाषाएं, न्यायपालिका की भाषा और कानूनों के ग्रंथ और विशेष निर्देश।

राजभाषा अधिनियम (1963) ने संघ के आधिकारिक उद्देश्य के लिए हिंदी के उपयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए संसद की राजभाषा समिति की स्थापना का प्रावधान किया। अधिनियम के तहत, इस समिति का गठन अधिनियम के लागू होने के दस साल बाद (यानी, 26 जनवरी, 1965) किया जाना था।

तदनुसार, इस समिति का गठन 1976 में किया गया था। इस समिति में संसद के 30 सदस्य, लोकसभा से 20 और राज्य सभा से 10 सदस्य शामिल हैं।

समिति संघ के आधिकारिक प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करती है और उस पर सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और राष्ट्रपति रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएंगे और इसे सभी राज्यों के सरकारों को भेजेंगे।

Q. 159) निम्नलिखित में से किसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है?

1. हिंदी
2. संस्कृत
3. उड़िया
4. उर्दू

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

a) केवल 1, 2 और 3
b) केवल 2 और 3
c) केवल 2, 3 और 4
d) केवल 3 और 4

Q. 159) Solution (b)

2004 में, भारत सरकार ने "शास्त्रीय भाषा" नामक भाषाओं की नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया। अब तक, छह भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है:

- तामिल
- संस्कृत
- तेलुगू
- कन्नड़
- मलयालम
- उड़िया

एक बार जब किसी भाषा को शास्त्रीय घोषित कर दिया जाता है, तो उसे उस भाषा के अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता मिलती है और प्रतिष्ठित विद्वानों के लिए दो प्रमुख पुरस्कारों का मार्ग भी खुल जाता है। इसके अलावा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरोध किया जा सकता है कि - कम से कम केंद्रीय विश्वविद्यालयों में - भाषा में प्रतिष्ठित विद्वानों के लिए शास्त्रीय भाषाओं के लिए एक निश्चित संख्या में पेशेवर पदों का निर्माण करें।

Q.160) निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट है?

1. डोगरी
2. नेपाली
3. अवधी

नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए:

a) केवल 1 और 2

b) केवल 2 और 3

c) केवल 1 और 3

d) 1, 2 और 3

Q.160) Solution (a)

संविधान की आठवीं अनुसूची 22 भाषाओं (मूल रूप से 14 भाषाओं) को निर्दिष्ट करती है। ये हैं असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी (डोंगरी), गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली (मैथिली), मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। सिंधी को 1967 के 21वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था; 1992 के 71वें संशोधन अधिनियम द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया; और बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को 92वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा जोड़ा गया था।

संविधान के प्रावधानों के संदर्भ में, आठवीं अनुसूची में उपरोक्त क्षेत्रीय भाषाओं के विनिर्देशन के पीछे दो उद्देश्य हैं:

1. इन भाषाओं के सदस्यों को राजभाषा आयोग में प्रतिनिधित्व दिया जाना है; तथा
2. इन भाषाओं के रूप, शैली और अभिव्यक्ति का उपयोग हिंदी भाषा के संवर्धन के लिए किया जाना है।